



पूँजीवाद का आम-संकट

लेखक

घी० त्रेपेत्कोव

अनुवादक

जुगमंदिर तायल



राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा) लि
छमेनीवाला मार्केट, एम. आर्. रोड, जयपुर 302001

General Crisis of Capitalism
का हिन्दी अनुवाद

English Edition

- © Progress Publishers, Moscow
In arrangement with
Mezhdunarodnaya Kniga, Moscow

हिंदी संस्करण

- © राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लि०
चमेलीवाला मार्केट, एम० आई० रोड,
जयपुर-302001

1985 (RPPH 5)

मूल्य : 6.00

अनुक्रम

प्रस्तावना	5
अध्याय : 1 : पूँजीवाद के आग-संकट की उत्पत्ति और उसका सारतत्त्व	9
पूँजीवाद के आग-संकट की ऐतिहासिक अनिवार्यता	9
पूँजीवाद के आग-संकट का सारतत्त्व	14
अध्याय : 2 : विश्व का दो विरोधी सामाजिक-व्यवस्थाओं में विभाजन और उनके बीच संघर्ष	20
इस में महान् अकतूरर समाजवादी क्रान्ति की विजय और विश्व का दो व्यवस्थाओं में विभाजन	20
दो विरोधी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और पूँजीवाद के आग-संकट का गहरा होना	25
अध्याय : 3 : साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का संकट और पतन	32
उपनिवेशी व्यवस्था का पतन पूँजीवाद के आग-संकट की एक अभिव्यक्ति	32
नव-उपनिवेशवाद	40
विकासशील देशों की अर्धव्यवस्थाओं के विशिष्ट लक्षण	47
अध्याय : 4 : पूँजीवादी अर्धव्यवस्था की बढ़ती हुई अस्थिरता और पतनशीलता	64
उत्पादन-दरणाओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग	64
बहुमध्य वैरोजवादी की दूरानी बीमारी	66
अर्धव्यवस्था का सैम्पीकरण	68
आर्थिक-संकट	71
बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति और लीज बने-आवने	73

अध्याय : 5 : राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का विकास

इजारेदार पूंजीवाद का राज्य-इजारेदार पूंजीवाद
रूप में विकास

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के प्रमुख रूप

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद और समाजवाद के नि
परिस्थितियों का निर्माण

अध्याय : 6 . पूंजीवादी राजनीति और विचारधारा का

बढ़ता हुआ संकट

पूंजीवादी देशों में बढ़ा हुआ राजनैतिक प्रतिक्रिया
पूंजीपति वर्ग की विचारधारा का गहरा होता सं

प्रस्तावना

जिस ऐतिहासिक युग में हम जी रहे हैं, उसकी मूल विशेषता पूँजीवाद से समाजवाद की ओर क्रांतिकारी संक्रमण है। मार्क्स-एंगेल्स और लेनिन ने जिस सामाजिक परिवर्तन का पूर्व-अनुमान किया था, वह अब सब हो रहा है। पूँजीवादी दुनिया की नींव चरमरा रही है और सारे संसार में समाजवाद की स्थिति अधिक-से-अधिक मजबूत होती जा रही है।

सामाजिक विकास के वस्तुगत नियमों की खोज करते हुए मार्क्सवाद-लेनिनवाद पूँजीवाद के भीतरी अंतर्विरोधों का उद्घाटन करता है और यह बताता है कि समाज में क्रांतिकारी विस्फोट तथा एक नयी सामाजिक-संघटना में समाज का संक्रमण अवश्यभावी है। मार्क्स और एंगेल्स ने पूँजीवाद से समाजवाद की ओर क्रांतिकारी संक्रमण की ऐतिहासिक आवश्यकता की सैद्धांतिक-आधारभूमि को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अन्य सभी पूर्ववर्ती सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के समान पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था भी ऐतिहासिक दृष्टि से अल्पकालिक है और जैसे पहले आदिम जनजातीय व्यवस्था का स्थान दास-स्वामियों के समाज ने, दास-स्वामियों के समाज का स्थान सामन्तवाद ने तथा सामन्तवाद का स्थान पूँजीवाद ने लिया था वैसे ही पूँजीवाद का स्थान अनिवार्य रूप से साम्यवाद लेगा।

पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था की प्रमुख विशेषता ऐसा अंतर्विरोध है जिसका समाधान नहीं हो सकता, जो अनिवार्य रूप से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म देता है तथा एक नयी सामाजिक-संघटना की ओर क्रमिक रूप से ब-ब-कदम-ब-कदम आगे बढ़ता है। मार्क्स और एंगेल्स के युग में अर्थात् 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजवादी क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक वस्तुगत व आत्मगत परिस्थितियाँ पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थीं। 1915 में लेनिन ने लिखा था : 'अधुना 20वीं शताब्दी पहले सर्वहारा वर्ग बहुत कमजोर था। समाजवाद की सफलता के

सिए वस्तुगत परिस्थितियाँ तब तक परिपक्व नहीं हुई थी १। ये परिस्थितियाँ 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विकसित हुईं जब पूँजीवाद ने अपने विकास के इजारेदार-पूँजीवादी दौर में प्रवेश किया।

पूँजीवाद के (जिसकी प्रमुख विशेषता मुक्त प्रतियोगिता है) साम्राज्यवाद के रूप में विकसित हो जाने के परिणामस्वरूप पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था व राजनीति में गहरे परिवर्तन हुए। सर्वहारा के बढ़ते हुए संघर्षों ने मार्क्सवादी दृष्टि से इन परिवर्तनों के अध्ययन की वलपूर्वक माँग की। मार्क्स व एंगेल्स के कार्य को जारी रखते हुए यह ऐतिहासिक कार्य लेनिन ने पूरा किया। अपने अध्ययन-कार्य के दौरान तथा 19वीं शताब्दी के अंतिम व बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों की जानकारी देने वाली विज्ञान तथ्यात्मक-सामग्री का सैद्धांतिक-सामान्यीकरण करते हुए लेनिन ने मार्क्स की शिक्षाओं का विकास किया और उन्हें आगे बढ़ाते हुए साम्राज्यवाद के नये सिद्धांत का निर्माण किया।

साम्राज्यवाद के आर्थिक सारतत्त्व का विश्लेषण करते हुए लेनिन ने बताया कि मुक्त प्रतियोगिता के क्षेत्र को कम करके बीसवीं शताब्दी के आरंभ में पूँजी तथा उत्पादन के केन्द्रीकरण व संकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा जमा लेने वाले पूँजीपतियों के शक्तिशाली गठबंधनों को जन्म दिया। इस प्रक्रिया ने इजारेदार बैंकिंग पूँजी का इजारेदार औद्योगिक पूँजी में विलय करके वित्तीय पूँजी तथा वित्तीय कुलीन तंत्र को भी जन्म दिया और इसके साथ पूँजी के निर्यात को भी तेजी से बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप न केवल राष्ट्रीय बल्कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों का निर्माण हुआ जिनमें पूँजीवादी देशों के अनेक समूह शामिल थे। इन इजारेदारियों ने विश्व का (जिसका सबसे बड़े पूँजीवादी देशों के बीच क्षेत्रीय विभाजन पहले ही हो चुका था) आर्थिक विभाजन शुरू किया। पूँजीवाद का मूल लक्षण—इजारेदारियों का आधिपत्य—इन नियमों के अंतर्गत विभिन्न रूपों में प्रकट होता है।

लेनिन पूँजीवाद की इजारेदारी-अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद के आर्थिक सारतत्त्व को स्पष्ट करने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने यह भी बताया कि पूँजीवाद की मूल विशेषताओं के विकास तथा उनकी निरंतरता के रूप में ही साम्राज्यवाद का उदय हुआ है, तथा यह पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली की ही एक विशिष्ट अवस्था है। इसकी विशेषताएँ तीन हैं—(1) साम्राज्यवाद अवश्य अपरा परजीवी व मरणमान्य इजारेदार पूँजीवाद है, (2) मुक्त प्रतियोगिता वाले पूँजी-

1. वी० आई० लेनिन—मार्क्सवाद और वृद्ध : वृद्ध के प्रति सभी सामाजिक वर्गों की दृष्टिकोण। तदनुसार रचनाएँ, भाग 21, पृष्ठ 313, प्रथम प्रकाशन, मार्च 1974 (बर्लिन में)

वाद के सदर्थ में यह पूँजीवाद की उच्चतम अवस्था है और इसके साथ, (3) यह पूँजीवाद की अंतिम अवस्था व समाजवादी क्रांति की पूर्व संध्या भी है।

लेनिन ने साम्राज्यवाद को मरते हुए पूँजीवाद के रूप में विवेचित किया और यह रेखांकित किया कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद के समस्त अंतर्विरोधों को तीव्रतर कर देता है। उन्होंने लिखा : “अंतर्विरोधों का यह तीव्रीकरण इतिहास के उस संक्रमण-काल की सबसे अधिक बलवान व गतिशील-शक्ति होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी की अंतिम विजय के साथ आरंभ होता है।”¹ पूँजीवाद के समस्त अंतर्विरोधों का यह अत्यंत तीव्रीकरण ही (जोकि साम्राज्यवाद के युग की विशेषता है) पूँजीवाद के पतन व समाजवादी क्रांति के विजय की ऐतिहासिक अनिवार्यता को निश्चित करता है।

साम्राज्यवाद के नियमों के विश्लेषण से लेनिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूँजीवाद के युग के भीतर सर्वहारा समाजवादी क्रांति की विजय की परिस्थितियाँ परिपक्व हो चुकी हैं और संसार ने पूँजीवादी व्यवस्था के विनाश व समाजवादी क्रांति और राष्ट्रीय भुक्ति क्रांतियों के युग में प्रवेश कर लिया है। इतिहास ने लेनिन के इन निष्कर्षों को पुष्ट किया है कि समाजवादी क्रांति सामाजिक-विकास के वस्तुनिष्ठ नियमों के अनुसार होती है और पूँजीवादी समाज के भीतरी अंतर्विरोध इसके मुख्य कारण होते हैं। समाजवादी क्रांति की सफलता इस पर निर्भर होती है कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की परिपक्वता किस स्तर पर है।

भूमंडलीय स्तर पर पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना का क्रांतिकारी परिवर्तन एक ऐसे ऐतिहासिक युग में होता है, जिसमें पूँजीवाद आम-संकट से घिरता जाता है। पूँजीवाद के आम-संकट के सारतत्त्व व इसके विकास के संपूर्ण दौरों की समझ, लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत तथा इस सिद्धांत पर आधारित समाजवादी क्रांति के सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। पूँजीवाद का आम-संकट पूँजीवाद के विकास की साम्राज्यवादी अवस्था में उसके तमाम अंतर्विरोधों के लगातार तीव्र होते जाने का अनिवार्य परिणाम है। साम्राज्यवाद का ऐतिहासिक स्थान निश्चित करते हुए लेनिन ने उसके साथ-साथ पूँजीवाद के आम-संकट के सिद्धांत की आधार-शिलाओं का भी विकास किया।

पूँजीवाद के आम-संकट के संबंध में लेनिन ने जो कुछ लिखा है वह मार्क्स-वादी-लेनिनवादी दलों के सामान्य कियानाप और सभी देशों में सर्वहारा के क्रांतिकारी संघर्षों के लिए बहुत मूल्यवान है। लेनिन ने एक नये ऐतिहासिक युग—साम्राज्यवाद व सर्वहारा क्रांति का युग तथा पूँजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण व साम्यवादी समाज के निर्माण का युग—के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत

1. थो० आई० लेनिन—‘साम्राज्यवाद : पूँजीवाद की उच्चतम अवस्था’, संपादित रचनाएँ, भाग 22, पृष्ठ 300 (अध्याय 3)

का प्रत्यक्षिक विचार विचार ।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्तावों, कम्युनिस्ट तथा सहयोगियों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सम्मेलन-निर्देशिकाएँ इन के प्रस्तावों में पूर्वी, बाद के बाद-अन्तर के संघों में सोवियत के विचारों का और अधिक प्रभावपूर्ण विचार दिया गया है ।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 22वीं कांग्रेस के सम्मेलन से हुए निर्देशों के अन्तर्गत के 'प्रथम चरण' की योजना का मतलब विश्व सम्मेलन के लिए बहुत दूर की चीज है । पूर्वी-पक्ष के लोग अभी अभी आरम्भ कर रहे हैं । फिर भी, इन के कर्तव्य की सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग करना है कि पूर्वी-पक्ष एक अधिक-वर्धित समाज व्यवस्था है ।

इससे स्पष्ट है कि हमें अपने पूर्वी-पक्ष के आत्म-अन्तर की पूर्वी-पक्ष के विचारों की सामान्य विशेषताओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है । यह प्रक्रिया सामान्यवाद के भीतरी अन्तर्भाव और नये वर्ग-अनुभव के समावर्धन के रूप में ही जाने के कारण हो रही है ।

विचार महाराज होगा पूर्वी-पक्ष का आत्म-अन्तर आज केवल दो वर्ग-व्यवस्थाओं—सामान्यवाद और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों—के बीच समावर्धन के रूप में परिचित नये वर्ग-अनुभव के रूप में ही प्रकट नहीं होता है, बल्कि विभिन्न पूर्वी-पक्षी देशों में विचार बढ़ती आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्रियाओं के रूप में भी प्रकट होगा है । ये सभी प्रक्रियाएँ अन्तर्भावों तथा अन्तर्भावों के एक अटल जाल में जुड़ी हैं । ये वैज्ञानिक-अर्थनीकी चार्ज में भी प्रभावित हैं जो अब तथा उत्पादन के सामाजिकरण को बढ़ाती है तथा साथ ही पूर्वी-पक्ष के सामाजिक वर्गों का और व्यापक स्तर पर पुनरुत्पादन करती है ।

1. सियोनित बोलेव—सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की स्तर और यह व विदेश नीति में पार्टी के सामाजिक कार्यकार, सोवोस्ली प्रेस एग्जेंसी प्रकाशन १६ मार्च, 1976, पृष्ठ 34 (अध्यायी में)

पूँजीवाद के आम-संकट की उत्पत्ति और उसका सारतत्त्व

पूँजीवाद के आम-संकट की ऐतिहासिक अनिवार्यता

पूँजीवाद का आम-संकट इसके भीतरी विरोधी अन्तर्द्वंद्वों से जो पूँजीवादी विकास की इजारेदारी अवस्था में तीक्ष्णतम हो जाते हैं, उत्पन्न होता है। जैसा कि दिन ने बताया है, पूँजीवाद का आम-संकट कोई संयोगजन्य घटना नहीं है, बल्कि पूँजीवाद के पतन और शय के दौरान अवश्यभावी तथा प्राकृतिक अवस्था है। दिन ने खोद देकर कहा है, 'पूँजीवाद का शासन इसलिए नष्ट नहीं होता है कि कभी कोई व्यक्ति सत्ता पर कब्जा करने के लिए तत्पर है' 'यदि पूँजीवादी देशों का समस्त आर्थिक विकास पतन की ओर अग्रसर नहीं हो तो पूँजीवादी-शासन का पतन करना असंभव होगा' 'यदि पूँजीवाद इतिहास के द्वारा अग्रसर और निर्बल हो बना दिया जाये तो कोई भी शक्ति इसे नष्ट नहीं कर सकती।'¹

उत्पादन-शक्तियों के लगातार विकास के कारण, उत्पादन-साधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित पूँजीवादी उत्पादन-संबंध पुराने होने लगते हैं। पूँजीवादी उत्पादन-संबंध सामाजिक-आर्थिक विकास में अधिक-से-अधिक बाधा डालने लगते हैं। 19वीं शताब्दी का अंत होने तक इजारेदारों के आधिपत्य और पूँजीवादी संबंध आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो जाने के कारण, उत्पादन शक्तियों व पूँजीवादी उत्पादन संबंधों के बीच अंतर्विरोध बहुत ही तीव्र हो गये। अब तक अज्ञान, उत्पादन का अप्रगुणपूर्ण सकेन्द्रीकरण और विश्व-अर्थव्यवस्था के द्विधे में बहूत से देशों के शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन-शक्तियों की ऐसी आन्ध्र-चलन अभिवृद्धि हुई कि पूँजीवादी उत्पादन संबंध उत्पादन-शक्तियों के विकास में

1 श्री० आर्० लेनिन, 'वृद्ध और पतित', पृष्ठ 14 (27) 1917 की रिलेटिव क्लरिफिकेशन रचनाएँ, भाग 24, पृ० 41 (अंग्रेजी में)

प्रेरक शक्ति बनने के स्थान पर बेटी बन गये। मानवता के सामने प्रबल उत्पादन-शक्तियों को स्वतंत्र करने तथा उनके भावी विकास के लिए पूरा क्षेत्र प्रदान करने तथा समाज के हित में उनका उपयोग करने की जरूरत उत्पन्न हो गई। यह जरूरत उत्पन्न हो गई कि क्रांति के द्वारा, जो पूँजीवादी उत्पादन संबंधों को नष्ट कर देगी, इस द्वंद्व का समाधान किया जाये।

इजारेदारी आधिपत्य विश्वस्तरीय पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण, जो कि साम्राज्यवाद के अंतर्गत पूर्ण हुई, ने पूँजीवादी उत्पादन की सामाजिक प्रकृति को अधिक तीव्र और गहन किया। लेनिन ने लिखा है—“पूँजीवाद अपनी साम्राज्यवादी अवस्था में, उत्पादन के परिपूर्ण समाजीकरण की ओर सीधा भागे बढ़ता है और पूँजीपतियों को, उनकी इच्छा व चेतना के विरुद्ध कुछ नये प्रकार की सामाजिक व्यवस्था—पूर्ण मुक्त प्रतियोगिता से पूर्ण समाजीकरण की ओर सक्रमण की व्यवस्था—में धींच लेता है।”¹ किन्तु उत्पादन का समाजीकरण निजी पूँजी द्वारा उत्पादन के सारे साधनों को ग्रहण किये जाने के विरोध में है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत करोड़ों मजदूरों के सामूहिक परिश्रम का लाभ शक्तिशाली उद्योगपतियों का एक छोटा समूह उठाता है। उत्पादन के सामाजिक चरित्र तथा लाभ ग्रहण करने की निजी संपत्ति वाली व्यवस्था के बीच अंतर्विरोध पहले कभी इतना तीव्र व गहरा नहीं होता है जैसा पूँजीवादी विकास की इजारेदारी अर्थात् साम्राज्यवादी अवस्था में होता है।

उत्पादन का समाजीकरण यह प्रकट करता है कि स्वयं पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर अर्थव्यवस्था के लोक-नियंत्रण की परिस्थितियाँ परिपक्व हो रही हैं और निजी पूँजीवादी-स्वामित्व की व्यवस्था इसके सारतर्क के अनुकूल नहीं रह गई है। उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को लोक-स्वामित्व में बदलना आवश्यक हो जाता है। इसका अर्थ यह होना है कि कुल मिलाकर पूँजीवाद से समाजवाद की ओर क्रांतिकारी सक्रमण की वस्तुनिष्ठ भौतिक परिस्थितियाँ परिपक्व हो गयी हैं।

साम्राज्यवाद के अंतर्गत पूँजी और श्रम के बीच अंतर्विरोध तीव्र हो जाते हैं। इजारेदार पूँजीपति इजारेदारी-मूल्य, जो शोषण का एक नया साधन है, लागू करते हैं। इसने उन्हें न केवल अनिश्चित मूल्य ही, बल्कि श्रम की कीमत का एक भाग भी भिन्न करने लगा है। आधुनिक तकनीक व उत्पादन की अभियांत्रिक पद्धति के प्रयोग में इजारेदार-मूल्य श्रम को संचय बनाने तथा शोषण को बढ़ाने को कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप सर्वहारा के रोष में वृद्धि होती है।

1. वी० आई० लेनिन, 'साम्राज्यवाद - पूँजीवाद की उच्चतम अवस्था', संशोधित संस्करण, भाग 22, पृ० 205 (बेबी के)

इजारेदार पूंजीपति वर्ग तथा अन्य वर्गों व सामाजिक सस्तरों—किसान, व मध्यम पूंजी वाले शहरी वर्ग, बुद्धिजीवी—के बीच अंतर्विरोधों का बढ़ना रहता है। इससे समाज के नातिकारी रूपांतरण के सपर्ष को विकसित करने एवं मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समस्त जनवादी शक्तियों के एक साम्राज्यवाद-धी गठजोड़ में एकताबद्ध होने की परिस्थितियाँ बनती हैं।

साम्राज्यवादी देशों के भीतर सामाजिक अंतर्विरोधों के निरंतर बढ़ते जाने से राष्ट्रीय अंतर्विरोध, प्रमुख रूप से साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार पूंजीपति पराधीन देशों की शोषित जनता के बीच अंतर्विरोध बढ़ने लगते हैं। साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार पूंजीपति पराधीन देशों की कीमत पर अपने अंतर्विरोधों को दूर करने व अधिक-से-अधिक लाभ कमाने की कोशिश में हैं। पूंजी का निर्यात करके और वस्तुओं के असमान विनिमय के द्वारा इजारेदार पूंजीपति वर्ग पराधीन देशों की जनता द्वारा उत्पन्न भारी मूल्य को हड़प रहे हैं। उत्पीड़न और शोषण का अनिवार्य परिणाम प्रतिरोध है। जन-समूह दृढ़-व्यय से संपूर्ण राजनीतिक व पूंजीपति वर्ग और उपनिवेशी व पराधीन देशों की ता के बीच अंतर्विरोधों की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के विरासत परिपक्वता के लिए वस्तुनिष्ठ आधारशिला का काम देती है। इसका अर्थ यह है कि साम्राज्यवादी ढाँचे के भीतर ही उपनिवेशी व पराधीन देश इजारेदारी के आरक्षित-क्षेत्र बदलकर सर्वहारा क्रांति की प्रभावी शक्ति बन जाने

साम्राज्यवाद के अंतर्गत साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच आपसी अंतर्विरोध बढ़ जाते हैं। हरेक इजारेदार-समूह विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों इजारेदार-समूहों की स्थिति को निर्बल करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील होता है। वे ऊँचे मुनाफे कमाने, बाजारों व कच्चे माल के स्रोतों पर अधिकार व पुनर्वितरण और लाभदायक विनियोग क्षेत्रों के लिए आपस में प्रतियोगिता के रूप में लड़ाई लड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तीव्र रूप में बढ़े हुए अंतर्विरोध सामने आते हैं। इनसे साम्राज्यवाद की शक्ति कमजोर हो जाती है और वस्तुनिष्ठ रूप से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन व समाजवादी क्रांति की सफलता की संभावना भी समावनाएँ बढ़ती हैं।

साम्राज्यवाद के युग की विशेषता, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर गतिमान होने के लिए वस्तुनिष्ठ (भौतिक और सामाजिक) परिस्थितियों का परिपक्व होना नहीं है, बल्कि आवश्यक आन्तरिक परिस्थितियों की रचना भी है। इसे मजदूर वर्ग की बढ़ती चेतना व संगठन, सामूहिक क्रांतिकारी कार्यवाही के लिए हमची परता, मजदूर वर्ग व पैर-सर्वहारा जनसमूहों (विशेष रूप से मेहनतकश किसान) के बीच मजबूत गठबंधन, मार्क्सवादी-लेनिनवादी दलों के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रीय

मुक्ति आंदोलनों, जो समाजवादी क्रांति के पक्ष में प्रभावी शक्ति हैं, के विकास के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, पूंजीवाद में समाजवाद की ओर संक्रमण के लिए वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ परिस्थितियों के परिणाम होने की प्रक्रिया विभिन्न-विभिन्न देशों में एक साथ तथा एक समान रूप में नहीं होती है। यह तथ्य लेनिन द्वारा रचित साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवाद के आर्थिक-राजनीतिक भगवान् विकास होने के वस्तुनिष्ठ नियम की स्थापना का संदर्भ है।

इजारेदार पूंजीवाद की अवस्था में आर्थिक विकास निर्गम समान ही नहीं होता है (असमान-विकास हमने पूर्व भी पूंजीवाद की विशेषता होती है) बल्कि अनियमित भी होता है। साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवादी देशों का असमान आर्थिक विकास उनके असमान राजनीतिक विकास से निरटना में जुड़ा है। 1916 में लेनिन ने लिखा था—“पूंजीवाद का विकास विभिन्न देशों में अत्यंत असमान रूप में आगे बढ़ता है” हमने असाध्य रूप में यह निष्कर्ष निरूपण है कि समाजवाद सभी देशों में एक साथ विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यह पहले एक या बनेक देशों में विजयी होगा जबकि अन्य देश कुछ समय के लिए पूंजीवादी या पूर्व-पूंजीवादी अवस्था में बने रहेंगे।” अतः विभिन्न देशों में समाजवादी क्रांति की परिस्थितियाँ विभिन्न रूपों में विद्यमान होती हैं। इस कारण समाजवादी क्रांति पहले उस देश में होती है जहाँ उसके लिए परिस्थितियाँ सबसे जल्दी परिपक्व होती हैं। पूंजीवाद की इजारेदारी अवस्था में होने वाला अनियमित विकास पूंजीवादी देशों के बीच तीव्र अंतर्विरोधों तथा द्वंद्वों को जन्म देता है। हमने विश्व पूंजीवादी व्यवस्था समग्रतः कमजोर होती है और कुछ देशों में समाजवादी क्रांति की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार पूंजीवाद के आम-संकट के उदय और उसके गहराने से समाजवाद द्वारा पूंजीवाद के क्रांतिकारी प्रतिस्थापन की ओर वस्तुनिष्ठ रूप में प्रगति होती है। किंतु यह प्रतिस्थापन एक साथ नहीं होता, यह एक पूरे ऐतिहासिक दौर में जीवित रहता है और इसके मुख्यात की घोषणा एक देश में समाजवादी क्रांतिकारी की विजय से होती है।

पूंजीवाद के आम-संकट की पूर्वपेक्षाएँ इजारेदार पूंजीवाद में अंतर्निहित अंतर्विरोधों के उद्गम होने के साथ ही प्रकट व एकत्र होना शुरू कर देती हैं। पहला महायुद्ध, जो साम्राज्यवादी देशों के बीच विश्व के क्षेत्रीय पुनर्वितरण की इच्छा के कारण उस समय मौजूद अंतर्विरोधों के स्वतः विस्फोट का परिणाम था, पूंजीवाद के आम-संकट की मुख्यात को सामने लाया। इजारेदार पूंजीपति वर्ग ने सोचा था कि

1. वो० आई० लेनिन, 'अवस्था क्रांति का वैज्ञानिक कार्यक्रम', सकलित 'स्वतंत्र', भाग 23, पृ० 79 (अध्याय 3)।

वे शक्ति-प्रयोग द्वारा अपने हितानुसार विश्व का पुनर्विभाजन कर सकते हैं और साथ ही क्रान्तिकारी आंदोलन का दमन करके साम्राज्यवाद की स्थिति को मजबूत भी बना सकते हैं। लेकिन युद्ध का उल्टा नतीजा सामने आया—उमन पूंजीवादी समाज के भीतरी व बाहरी अवरोधों का समाधान नो नहीं हो सका, उन्हें तीव्र और उग्र कर दिया। इसने भारी मात्रा में भौतिक नुकसान दिया, विशाल मात्रा में मानव-जीवन की हानि की और मेहनतकशों की गरीबी तथा पीड़ा को उस समय चरम सीमा पर पहुँचा दिया। इसके साथ युद्ध ने इजरायेलियों को भारी मात्रा में सपूह होने से सहायता भी दी। अमेरिका के पूंजीपतियों ने विशेष रूप से भारी लाभ कमाया क्योंकि सैनिक सामान की बिक्री में उनके मुनाफ़े भविष्यकाल की तुलना में तीन-चार गुना ज्यादा हो गये।

पहले महायुद्ध ने पूंजीवादी अवरोधों को बहुत अधिक बढ़ाया अनेक पूंजीवादी देशों में क्रान्तिकारी विस्फोटों को जन्म दिया उत्पीड़ित जनसमूहों के राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलनों को जाग्रत किया। उस समय लेनिन ने लिखा था— यूरोपीय महायुद्ध एक भारी ऐतिहासिक संकट है एक नये युग की शुरुआत है। अन्य किसी संकट के समान युद्ध ने गहराई में दबे विरोधों को बढ़ा दिया है और उन्हें धरातल के ऊपर ला दिया है।¹

पहले महायुद्ध ने संपूर्ण साम्राज्यवादी व्यवस्था की शक्ति को कम किया और साम्राज्यवादी जमीर को, उसके सबसे कमजोर हिस्से पर तोड़न में सहायता दी। शास्त्र में साम्राज्यवादी व्यवस्था में वह कड़ी और उससे सम्बन्धित अवरोधों का केन्द्र-बिंदु इस सिद्ध हुआ। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में इस समाजवादी क्रान्ति के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ परिस्थितियों का उपयुक्त स्थान हो गया था। समाजवादी अक्टूबर क्रान्ति (1917) ने इस में समूची दुनिया के लिए महत्व की ऐतिहासिक प्रक्रिया—समाजवाद द्वारा पूंजीवाद की प्रतिस्थापना की प्रक्रिया—आरम्भ की।

पहला महायुद्ध और महान् समाजवादी अक्टूबर क्रान्ति ने पूंजीवाद के आम-संकट की शुरुआत को रेखांकित किया। पहले महायुद्ध के समय में लेनिन का यह भूतप्राकृत था कि सामाजिक क्रान्ति की तुलना में यह एक छोटा संकट था एक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी संकट था। उन्होंने आसन्न समाजवादी क्रान्ति को बड़ा संकट माना। इसका अर्थ यह है कि महान् समाजवादी अक्टूबर क्रान्ति ने पूंजीवादी व्यवस्था में विनाश और समाजवादी-व्यवस्था की ओर संक्रमण के युग की शुरुआत की।

1. वी. आई. लेनिन, 'युन बाँटपाटुवाद और नीचिन समाजवाद इतरनेकनन की दुनया में पना कैसे हो सकती है', अकस्मिक रचनाएँ, भाग II, पृ. 92 (अंग्रेजी में)।

2. पूंजीवाद के आम-संकट का सारतत्त्व

समाजवादी क्रांति के बाद के युग को लेनिन ने समग्र रूप में पूंजीवाद के पतन और समाजवादी समाज के जन्म के युग के रूप में चित्रित किया है।¹ उनके निष्कर्ष पूंजीवाद के आम-संकट—जो समाजवादी क्रांति के परिणामस्वरूप पूंजीवाद के आंतरिक विघटन और पतन की अनिवार्य रूप से भूमंडलीय ऐतिहासिक प्रक्रिया है—के सारतत्त्व के वैज्ञानिक-वर्णन पर आधारित हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक-से-अधिक देश पूंजीवाद से अलग होते जाते हैं और जिसमें क्षयशील पूंजीवाद व विकसमान समाजवाद के बीच संघर्ष का समावेश होता है। यद्यपि साम्यवाद पूंजीवादो-व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए हरसंभव कोशिश करता है किन्तु अपनी खोई हुई ऐतिहासिक पहल को पाने और आधुनिक विश्व के विकास को बदलने में असमर्थ रहता है। मानव जाति के विकास की मुख्य धारा का निर्णय अब विश्व समाजवादी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन द्वारा होता है।

मोबियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में बताया गया है—“हमारा युग, जिसकी मुख्य अंतर्वस्तु पूंजीवाद में समाजवाद की ओर संक्रमण है, दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष का, समाजवादी व राष्ट्रीय मुक्ति जाग्रियों का, समाजवादी व्यवस्था के नष्ट होने और उपनिवेशी व्यवस्था के अंत होने का युग है। यह युग अधिक-से-अधिक जनसमूहों के समाजवाद के मार्ग में संक्रमित होने और विश्व स्तर पर समाजवाद व साम्यवाद के विजयी होने का युग है। वर्तमान युग का प्रमुख कारक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग और इसकी मुख्य रचना विश्व समाजवादी व्यवस्था है।”²

‘पूंजीवाद के आम-संकट’ की धारणा की ‘आर्थिक संकट’ की धारणा में भी मिलाया जाना चाहिए। आर्थिक संकट समय-समय पर नियमित रूप से आने हैं और उनमें से कुछ का इस या उस तरह से पूंजीवादी ढाँचे के अनंत समाधान कर लिया जाता है। हर नया आर्थिक संकट पूर्ववर्ती आर्थिक संकट के बाद के समय में पूंजीवादी उत्पादन-ढाँचे में एकत्र हुए अंतर्विरोधों का विस्फोट होता है। एक निश्चित आर्थिक संकट के समय इन अंतर्विरोधों को अस्वादी रूप से दूर कर दिया जाता है। आर्थिक संकट औद्योगिक-चक्र की एक स्थिति है जो प्रायः तालेतिष्ठ रूप में खोरी अवधि (एक वर्ष में तीन वर्ष तक) के लिए चलती है, इसके बाद पूंजीवादी व्यवस्थावादी व्यवस्था को अस्था रूप से और कमजोर पुनर्स्थापित करने

1. लेनिन, ‘कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) की तानकी विशेष कार्य’, मार्क्स-लेनिन-स्टालिन के चयनित कार्य, भाग 2, पृ. 130।
2. यद्यपि असाध्य, मस्को, 1962, पृ. 449।

दूगने महापुरुष का अंत विचार-महाप्रवाही व्यवस्था के जन्म और उनके मजबूत होने के साथ हुआ। इसके साथ मजबूत बनी व राष्ट्रीय व्यक्ति आरीवनों में अस्ति-शामी उधार आया और मासाम्मावाद की उपनिवेशी व्यवस्था का निर्माण करने हुआ। राष्ट्रों का एक बड़ा समूह, जिसने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वह अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ देशों ने विकास के दौर-पूँजीवादी रास्ते को चुना है और वे व्यापक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सुधार कर रहे हैं। इन देशों के भीतर मार्क्स की पूँजीवादी शोषण संबंधों के विपक्ष संघर्ष चल रहा है। इन देशों की विदेश नीति साम्यवाद विरोधी है।

पूँजीवाद के आम-संकट का तीव्र विनिष्ठ सतत साम्यवादी देशों के भीतरी अंतर्विरोधों का बड़ा जाना और आर्थिक स्थिरता का तीव्र क्षय हो जाना है। यह विकास-दरों के तीव्र उतार-चढ़ाव, अममान आर्थिक विकास, बढ़ती दरों में बार-बार आते सबट, उत्पादन क्षमता का समाप्त बम उपयोग, दीर्घकालीन बेरोजगारी, तेजी से बढ़ती मुद्रास्फूर्ति, अंतराष्ट्रीय मीडिक संबंधों में मजद, वर्ग-व्यवस्था के तीव्रकरण आदि के रूप में प्रकट होना है। राजकीय इजारेदार पूँजीवाद—जो पूँजीवादी व्यवस्था के निर्बल हो जाने और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इजारेदार पूँजीवाद द्वारा राज्य-शक्ति के प्रयोग की इच्छा का परिणाम है, पूँजीवाद के अंतर्विरोधों को दूर करने में असमर्थ है और अंत में उन अंतर्विरोधों की अटिल व उभर बनाना है।

पूँजीवाद के आम-संकट का बीधा प्रमुख सतत पूँजीवादी राजनीति व विचार-धारा का संकट है। पूँजीवादी विचारक—जो इजारेदार पूँजीवाद के हितों को व्यक्त करते हैं, जीवन-मार्ग द्वारा उभारे गए सवालों का जवाब देने में बहमर्ष हैं। वे ऐसे विचार आगे लाने में असमर्थ हैं जो मेहनतकशों का मन जीत सकें। बढ़ते हुए वर्ग-संघर्ष का सामना करने के लिए, कुछ देशों में वित्तीय अस्थिरता कठोर राजनीतिक प्रतिक्रियावाद का सहारा नेता है, वह पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं को समाप्त करके, तानाशाही फ़ासिस्ट अर्ध-फ़ासिस्ट शासनों की स्थापना कर देता है।

पूँजीवादी आम-संकट की ये सभी विशेषताएँ सार-रूप में एक ही प्रक्रिया के विभिन्न रूप हैं। ये आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। पूँजीवाद के आम-संकट की मूलभूत अभिव्यक्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण माधुनिक युग—जो भूमंडलीय स्तर पर पूँजीवादी से समाजवाद और साम्यवाद की ओर क्रान्तिकारी संक्रमण का युग है—की अंतर्वस्तु का अधिक पहला ज्ञान पाने में सहायक होता है।

पूँजीवाद के आम-संकट की अवस्थाएँ—पूँजीवाद के आम-संकट के विकास। विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं और हर अवस्था के अपने विशेष सतत होते हैं।

के आम-संकट की वर्तमान तीसरी अवस्था के प्रमुख लक्षणों का निर्धारण करता है।

तीसरी अवस्था का एक अन्य प्रमुख लक्षण राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में शक्तिशाली नये उभार के कारण उपनिवेशी व्यवस्था का पूर्ण विखंडन है।

तीसरी अवस्था की एक विशिष्टता यह है कि इसका जन्म महायुद्ध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि दो व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व और आधिक-प्रतियोगिता के फलस्वरूप हुआ है। यह तथ्य पूंजीवादी सिद्धांतकारों द्वारा रचित इस मिथक को खंडित कर देता है कि मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद का विनाश युद्ध के द्वारा होगा और इसलिए मार्क्सवाद-लेनिनवादी युद्ध में रुचि रखते हैं। पूंजीवाद का पतन इसके भीतरी परस्पर प्रतिकूल अंतर्विरोधों के कारण होगा, इसलिए समाजवाद तब ही विजयी हो सकता है जब दो व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थिति हो।

आठवें दशक के आरंभ में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के प्रयत्न से अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य की पक्षधर प्रवृत्तियाँ निरंतर मजबूत हुईं। उन वर्षों की विशेषताएँ थीं—समाजवादी समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दृढ़ता, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलता और तनाव-शैथिल्य का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रभावी प्रवृत्ति बन जाना। सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों की समन्वित विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सामान्य स्थिति साने के लिए शान्तिकामी शक्तियों का संघर्ष सफल हुआ।

किन्तु 1980 के दशक के आरंभ में साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होने लगीं। वे स्वतंत्र देशों तथा जन-समूहों को अग्रित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे कस्त्र-दीड़ को बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों के घरेलू मामलों में खुले तौर से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

विश्व के जनगणों को यह अवश्य समझना चाहिए कि परमाणु-युद्ध के स्वाभाविक परिणाम होंगे। आज का अति-आवश्यक कार्य शांति की रक्षा है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रस्तुत केंद्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया था—“शांति की रक्षा करते हुए हम केवल आज जीवित मनुष्यों और अपने बेटे-पानों की रक्षा के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम दुर्बलों भारी पीड़ितों की खुशियों के लिए भी काम कर रहे हैं।”¹ रिपोर्ट में इस दावे के झूठ को प्रष्ट किया गया है कि सोवियत संघ अमेरिका से और बारसा-मध्य के देश नाटो-देशों के ऊपर सैनिक-भेंटना जाने की कोशिश कर रहे हैं। “हमने दूसरे पक्ष पर सैनिक-भेंटना नहीं किया है और न हम ऐसा चाहते हैं। यह हमारी नीति नहीं है, लेकिन इस

1. ‘रिपोर्ट और प्रस्ताव’, केंद्रीय संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस, कस्तन, 23 अक्टूबर—3 मार्च, 1981, पृ. 40।

अपने ऊपर ऐसी श्रेष्ठता पाने की अनुमति भी नहीं देंगे। इस तरह के प्रयत्न और हमसे 'शक्ति की स्थिति' से बातचीत करने की कोशिश पूरी तरह व्यर्थ होगी।"¹ सोवियत विदेश नीति की मुख्य दिशा सदैव युद्ध के खतरे को कम करना और— शस्त्र दौड़ पर रोक लगाना रही है।

1. दस्तावेज और प्रस्ताव—सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस, मास्को, 23 फरवरी-3 मार्च, 1981, पृ० 25-30।

के आध-मंडल की वर्तमान नीमरी अवस्था के प्रमुख मशगलों का निर्धारण करता है।

नीमरी अवस्था का एक अन्य प्रमुख स्रोत राष्ट्रीय मुक्ति कर्षों के शक्तिशाली नये उभार के कारण डार्निनवेगी अवस्था का पूर्ण विघटन है।

नीमरी अवस्था की एक विनिष्ठता यह है कि इसका जन्म महायुद्ध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि दो व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्थिर और अस्थिर-प्रतिक्रिया के पतनवर्धक हुआ है। यह तथ्य पूँजीवादी मिश्रितकारों द्वारा रचित इन त्विक को खंडित कर देना है कि मार्क्सवाद के अनुसार पूँजीवाद का विनाश युद्ध के द्वारा होगा और इसलिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी युद्ध में रुचि रखते हैं। पूँजीवाद का पतन इसके भीतरी परस्पर प्रतिकूल अन्तर्विरोधों के कारण होगा, इसलिए समाजवाद तब ही विजयी हो सकता है जब दो व्यवस्थाओं के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्थिर की स्थिति हो।

आठवें दशक के आरंभ में सोवियत संघ तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों के प्रत्यक्ष से अंतर्राष्ट्रीय तनाव-सौधित्व की पृष्ठभूमि पर प्रवृत्तियाँ निरंतर मजबूर हुईं। उन वर्षों की विशेषताएँ थीं—समाजवादी समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दृढ़ता, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलता और तनाव-सौधित्व का अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की प्रभावी प्रवृत्ति बन जाना। सोवियत संघ व अन्य साम्राज्यवादी देशों की समन्वित विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सामान्य स्थिति साने के लिए शांतिशाली शक्तियों का संघर्ष सफल हुआ।

किन्तु 1980 के दशक के आरंभ में साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होने लगीं। वे स्वतंत्र देशों तथा जन-समूहों को बर्बाद करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे अस्त्र-दौड़ को बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों के बर्बाद मामलों में खुले तौर से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

विश्व के जनमणों को यह अवश्य समझना चाहिए कि परमाणु-युद्ध के क्या गंभीर परिणाम होंगे। आज का अति-आवश्यक कार्य शांति की रक्षा है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रस्तुत केंद्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया था—“शांति की रक्षा करते हुए हम केवल आज जीवित मनुष्यों और अपने बेटे-पोतों की रक्षा के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम दर्जनों प्राचीन पीढ़ियों की धुंधली के लिए भी काम कर रहे हैं।”¹ रिपोर्ट में इस दावे के शूट को प्रकट किया गया है कि सोवियत संघ अमरीका से और बारसा-संधि के देश नाटो-देशों के ऊपर सैनिक-श्रेष्ठता पाने की कोशिश कर रहे हैं। “हमने दूसरे पक्ष पर सैनिक-श्रेष्ठता नहीं चाही है और न हम ऐसा चाहते हैं। यह हमारी नीति नहीं है, लेकिन हम

1. 'दस्तावेज और प्रस्ताव', सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस, मस्को, 1981, पृ. 40।



के आम-संकट की वर्तमान तीसरी अवस्था के प्रमुख लक्षणों का निर्धारण करता है।

तीसरी अवस्था का एक अन्य प्रमुख लक्षण राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में शक्तिशाली नये उभार के कारण उपनिवेशी व्यवस्था का पूर्ण विघटन है।

तीसरी अवस्था की एक विशिष्टता यह है कि इसका जन्म महायुद्ध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि दो व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व और आर्थिक-प्रतियोगिता के फलस्वरूप हुआ है। यह तथ्य पूंजीवादी सिद्धांतकारों द्वारा रचित इस सिद्धांत को खंडित कर देता है कि मानसंवाद के अनुसार पूंजीवाद का विनाश युद्ध के द्वारा होगा और इसलिए मानसंवादी-लेनिनवादी युद्ध में रुचि रखते हैं। पूंजीवाद का पतन इसके भीतरी परस्पर प्रतिकूल अंतर्विरोधों के कारण होगा, इसलिए समाजवाद तब ही विजयी हो सकता है जब दो व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थिति हो।

आठवें दशक के आरंभ में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के प्रयत्न से अंतर्राष्ट्रीय तनाव-सौमित्र्य की पक्षधर प्रवृत्तियाँ निरंतर मजबूत हुईं। उन वर्षों की विशेषताएँ थी—समाजवादी समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दृढ़ता, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलता और तनाव-सौमित्र्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की प्रभावी प्रवृत्ति बन जाना। सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों की समन्वित विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सामान्य स्थिति साने के लिए शक्तिकामी अस्त्रों का संघर्ष सफल हुआ।

चिन्तु 1980 के दशक के आरंभ में साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होने लगीं। ये स्वतंत्र देशों तथा जन-महूरों को ज़ख्मी करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे जलज-दौड़ को बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों के बोनू मामलों में शूने तौर से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

विश्व के जनघनों को यह अवश्य समझना चाहिए कि परमाणु-युद्ध के स्वा-मंजीर परिणाम होंगे। आज का अति-आवश्यक कार्य शांति की रक्षा है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रस्ताव केंद्रीय समिति की राय के द्वारा कहा गया था—“शांति की रक्षा करते हुए हम केवल आज जीवन मनुष्यों को बचाने के लिए शांति की रक्षा के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम दुश्मनों वाली शक्तियों की शक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं।” राय में इस दावे के झूठ को प्रकट किया जा रहा है कि सोवियत संघ अमेरिका से और बारसा-अधि के देश नाटो-देशों के डार-हेंक-खेप्टा जाने की कोशिश कर रहे हैं। “हमने दूसरे पक्ष पर सैनिक-खेप्टा और न हम ऐसा चाहते हैं। यह हमारी नीति नहीं है, लेकिन हम

अपने ऊपर ऐसी खेष्टता पाने की अनुमति भी नहीं देवे। इस तरह के प्रयत्न और हमसे 'शक्ति की स्थिति' से बाताचीत करने की कोशिश पूरी तरह व्यर्थ होगी।”¹ सोवियत विदेश नीति की मुख्य दिशा सदैव युद्ध के खतरे को कम करना और—शस्त्र दौड़ पर रोक लगाना रही है।

विश्व का दो विरोधी सामाजिक-व्यवस्थाओं में विभाजन और उनके बीच संघर्ष

1. हम में महान् अकतूबर समाजवादी क्रांति को विजय और विश्व का दो व्यवस्थाओं में विभाजन

जून की 1917 की महान् अकतूबर क्रांति साम्राज्यवाद की समस्त विश्व-व्यवस्था को परेशान करने वाले अन्तर्विरोधों का तत्समग परिणाम थी। हम में—और यूरोप की सबसे निर्बल कड़ी का और वही साम्राज्यवाद के सभी प्रमुख अन्तर्विरोध 20वीं सदी के आरम्भ में एक पुरुष के रूप में एकत्र हो गये थे—यूरोप के लिए क्रांति यूरोप के मध्य में परिपक्व हुई। हम की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों—उच्च रूप में मकेडोन औद्योगिक उत्पादन, मेहनतकशी का पूरा भ्रम, राजनैतिक अधिकारों का अभाव, राष्ट्रीय अनामध्यमताओं की पूर्ण विनाशिता, सामग्री अर्थ-व्यवस्था के अक्षय और अन्तराष्ट्रीय पूँजी पर निर्भरता—के इसे विश्व-यूरोपवादी व्यवस्था के अन्तर्विरोधों का कोट-विन्दु और साम्राज्यवाद की कड़ी की सबसे निर्बल कड़ी बना दिया था। पहले महापुरुष ने आरम्भ की हमारा विश्व उदात्त हत्या और साम्राज्यवाद के राजनैतिक सामाजिक अन्तर्विरोधों का उत्पादन कर उस कड़ी को तोड़ना प्रारम्भ करा दिया। हम में समाजवादी क्रांति की व्यवस्था के लिए अन्तर्विरोध का अन्तर्विरोध का अन्तर्विरोधों की कोट

उत्पन्न कर प्रथम रूप से क्रांति उत्पन्न देना था, जिसे 20वीं सदी के आरम्भ में उदात्त हत्या और साम्राज्यवाद का अन्तर्विरोध और आरम्भिक निर्बल हत्या का अन्तर्विरोध और अन्तर्विरोध का ही रूप था। पहले महापुरुष के मरण के बाद हम में उदात्त हत्या का ही अन्तर्विरोध हो गया था। वे महापुरुषों के मरण के बाद उदात्त हत्या का ही अन्तर्विरोध हो गया था और अन्तर्विरोध-अन्तर्विरोधों की कड़ी का अन्तर्विरोध

करते हैं : धातु-वस्तुओं के उत्पादन का 80-95 प्रतिशत भाग प्रोद्योगिक सिन्डीकेट के हाथों में संकेद्रित था, कोयला-उद्योग पर पूरी तरह प्रोद्योगिक सिन्डीकेट का आधिपत्य था, दक्षिण रूस के खनिज-सौह उत्पादन के 80 प्रतिशत भाग का नियन्त्रण प्रोद्योगिक सिन्डीकेट करता था, और देश के तांबा उत्पादन का 75 प्रतिशत भाग मेंद सिन्डीकेट द्वारा नियंत्रित था। उच्च-स्तर का यह इकारीकरण रूस की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट था। इसके अलावा रूस के इजारेदार पूंजीवाद में राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के रूप में विकसित होने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती थी। इस प्रकार रूस में उत्पादन का उच्च-स्तरीय समाजीकरण हो गया था जो समाजवादी क्रान्ति के लिए वस्तुनिष्ठ परिस्थितियाँ प्रदान करता था।

इन वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के अलावा आवश्यक आन्तरिक परिस्थितियाँ भी परिपक्व हो गयी थी—मजदूर और विश्व के एक सर्वाधिक जातिवादी मजदूर वर्ग का उदय हो चुका था। रूस में पूंजीवाद के विराम की लगभग आधी शताब्दी में औद्योगिक मजदूर-वर्ग की संख्या में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और शताब्दी के आरम्भ में इनमें से आधे से ज्यादा बड़े उद्योगों में सर्वेक्षित थे, जहाँ मजदूरों में उच्चतम स्तर की राजनैतिक जागरूकता थी। रूसी मजदूर वर्ग सभी बड़े-मध्यमों में फौजदारी हुआ था और सभीजन उच्च-स्तर पर संगठित थे राजनैतिक रूप से बहुत बेगन था। यह सभी प्रकार के शोषण व उत्पीड़न का बहुत दुश्मन था। क्रांती और तांकी में रूसी मजदूर वर्ग के बहुत से शायी—विशेष रूप से मेन्शनका किसान—थे।

इस प्रकार अकतूबर क्रान्ति की विजय रूस के सबसे सामाजिक-आर्थिक विचार की प्रगति के द्वारा निश्चित हुई थी। क्रान्ति की विजय बीगबी शताब्दी की प्रमुख घटना थी। यह ऐसी घटना थी जिसने समस्त विश्व के विकास के मार्ग में परिवर्तन निश्चित कर दिया। समाजवादी अकतूबर क्रान्ति इजारेदार पूंजीवाद के अन्तर्गत वर्ग-समर्थ और सामाजिक विकास का स्वाभाविक परिणाम थी। इसकी विजय में विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य की जन्म दिया। विश्व का सबसे बड़ा देश—और समस्त समस्तका की दृष्टि में तीसरे और कुल औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि में पचासवें स्थान पर था—पूंजीवादी व्यवस्था में बाहर निकल आया। साम्राज्यवादी क्रान्ति ने रूस की जनता को साम्राज्यवादी दुष्ट में बाहर निकाल दिया और उन्हें विदेशी पूंजी द्वारा दास बनाये जाने के भय से बचा लिया।

विश्व-पूंजीवादी व्यवस्था में रूस का अपवाद साम्राज्यवादी विप्लव पूंजी के हितों पर भारी आघात था। अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद ने श्रेष्ठ व सफल होने के साथ औद्योगिक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण बाजार और पूंजी-निवेश का क्षेत्र खो दिया। 1914 में रूस की मजदूर शक्ति पूंजी के 47 प्रतिशत का विदेशी पूंजी का नियन्त्रण था। यह और उत्पादन के मध्यम 60 प्रतिशत, कम-उत्पन्न के

और निर्णयों से अधिक बलशाली एक और शक्ति है। यह शक्ति विश्व के आम आर्थिक संघर्ष है जो उन्हें हमसे संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर करते हैं।”¹ समाजवादी व पूंजीवादी राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, उत्पादक-शक्तियों के विकास व ऐतिहासिक रूप से रचित श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के कारण निर्मित वस्तुनिष्ठ आवश्यकता के रूप में उत्पन्न होता है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का लेनिनवादी सिद्धांत, देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक उपाय के रूप में युद्ध की अस्वीकृति की सबसे पहले मांग करता है। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की पूर्वपिछाई है—प्रत्येक देश (छोटे और बड़े दोनों) की क्षेत्रीय अर्पणता, समानता व सार्वभौमिकता के सिद्धांत की परस्पर स्वीकृति व उसकी परिपासना और अन्य जनगणों के मामलों में अहस्तक्षेप। इसमें, सब राष्ट्रो द्वारा अपने लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार का सम्मान और अनन्यसंसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत द्वारा समाधान तथा इसके साथ पूर्ण समानता व परस्पर लाभ के आधार पर आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग का विकास भी शामिल है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति, जिसका समाजवादी देशों द्वारा पालन किया आ रहा है, उनके अपने हितों को ही प्रकट नहीं करती है बल्कि संपूर्ण रूप में मानव-जाति के हितों को प्रकट करती है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व समाजवादी-व्यवस्था की आर्थिक शक्ति में विकास के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करता है, मजदूर वर्ग के संघर्ष की दशाओं में सुधार करता है और उत्पीड़ित जनगणों के लिए उनके अपने राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष की समस्याओं से निपटने के कार्य को आसान बनाता है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि व युद्ध की आग को भड़काकर साम्राज्यवादियों द्वारा अपने आंतरिक अंतर्विरोधियों पर काबू पाने के प्रयत्नों को रोकता है।

इस नीति का अर्थ दो विरोधी विश्व-व्यवस्थाओं के बीच विरोध की समाप्ति नहीं है। पूंजीपति व सर्वहारा तथा समाजवाद व साम्राज्यवाद के बीच संघर्ष जारी रहेगा। साम्राज्यवादी युद्धों के खतरे के विरुद्ध शांति के लिए संघर्ष इस संघर्ष का अनिवार्य भाग है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जीवन के सभी क्षेत्रों—अर्थव्यवस्था, राजनीति, विचारधारा व संस्कृति—में समाजवाद व पूंजीवाद के बीच द्वंद्व का सर्वाधिक तर्क-संगत और वांछनीय रूप है।

दो व्यवस्थाओं के बीच मुकाबले में आर्थिक-प्रतियोगिता का केन्द्रीय स्थान

1. वी० आई० लेनिन, 'गोबिर्नो की नयी अग्निवस्ती का विवेक', दिसम्बर 23-28, 1921, संकलित रचनाएं, भाग 33, पृ० 155।

औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से गोविन्द सभ विश्व में पाँचवें स्थान से दूसरे स्थान और यूरोप में चौथे स्थान से पहले स्थान पर आ गया था। विश्व के औद्योगिक उत्पादन में इसका भाग बढ़कर दस प्रतिशत हो गया था।

यह सब पूँजीवादी विश्व से आर्थिक प्रतियोगिता के आरम्भिक दो दशकों में (जब तक कि हिटलर की जर्मनी के विश्वामुखातपूर्ण आक्रमण ने गोविन्द सभ की पुनर्देश की रसायन के विमान के लिए अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश नहीं कर दिया) समाजवाद की भारी विजय का सदर्शक है।

2. दो विरोधी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और पूँजीवाद के आम-संकट का गहरा होना

दूसरा महायुद्ध इस युद्ध में भागीदार देशों के लिए भिन्न-भिन्न रूप में समाप्त हुआ। कुछ देश विजयियों में थे, कुछ अन्य पराजितों में। कुछ देश युद्ध में मजबूत होकर निकले, कुछ कमजोर हो गए। समग्र रूप में साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिए युद्ध भारी पराजय सिद्ध हुआ। युद्ध पूँजीवाद को आम-संकट से बाहर निकालने में ही असफल नहीं रहा बल्कि उल्टे उसका परिणाम इस संकट को और अधिक उग्र बनाना रहा।

गोविन्द जनगण की विजय और नाज़ी जर्मनी, फ़ासिस्ट इटली व सैन्यवादी जापान की हार समग्र विश्व के लिए ऐतिहासिक महत्व की कहानी थी। यूरोप और एशिया के बहुत से देशों में समाजवादी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। समाजवाद एक देश की सीमा से बाहर निकलकर विश्व-व्यवस्था बन गया। इस में अकतूबर समाजवादी क्रांति के बाद यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी।

विश्व-समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों—पूर्ण समानता, राष्ट्रीयता-स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, भ्रातृत्वपूर्ण सहयोग और परस्पर सहायता पर आधारित संबंधों की स्थापना की। ये संबंध दोनों प्रकार के हितों—समग्र विश्व-समाजवादी व्यवस्था के हित और वैयक्तिक समाजवादी राज्यों के राष्ट्रीय हितों को स्वीकार करते थे। समाजवादी व्यवस्था के भीतर ये संबंध समाजवादी देशों के एक समान सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक आधारों से और उनके सामुदायिक वर्ग-हित व उद्देश्यों से उत्पन्न होते हैं।

दूसरे महायुद्ध के बाद जिन देशों ने समाजवादी राह स्वीकार की, वे पहले साम्राज्यवादी शोषण के शिकार थे। युद्ध से पहले पोलैंड की औद्योगिक जमापूँजी के दो-तिहाई से अधिक भाग और बुल्गेरिया की बाघी से अधिक व हंगरी की एक-तिहाई संयुक्त-स्टाक पूँजी पर विदेशियों का अधिकार था। विदेशी इजारेदार रुमानिया की कुल औद्योगिक पूँजी के लगभग 50 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण

रखने थे। साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार पूँजीपति इन देशों की राष्ट्रीय भाषा का एक बड़ा हिस्सा अपनी तिजोरियों में भरने के लिए बाहर ले जाते थे।

केन्द्रीय व दक्षिणी पूर्वी यूरोप के अनेक देशों को पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था में प्रस्थान, इन देशों में विदेशी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण और विदेशी-मालादार राज्य के एकाधिकार की स्थापना ने इन देशों के जनमण को विदेशी-अधीनता से बचा लिया। अब एशिया के अनेक देशों ने भी समाजवादी विचार का रास्ता चुन लिया तो साम्राज्यवादी इजारेदारियों को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ। पुराने समाजवादी क्रांति की विजय साम्राज्यवाद को एक और नया आघात था। पूँजीवादी शोषण के क्षेत्र में और अधिक कमी से विश्व-पूँजीवाद आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, पूँजीवादी व्यवस्था में अस्थिरता बढ़ी और साम्राज्यवादी देशों के बीच तथा उन देशों के भीतर भी अंतर्निहित (मौजूद) अंतर्विरोधों में वृद्धि हुई।

आर्थिक प्रतियोगिता के दौरान समाजवाद ने यह दिशा दिया है कि बर्तनक बहुत-से आर्थिक सदस्यों का समावेश है, यह पूँजीवादी की तुलना में अधिक फेड व्यवस्था है (देने, सारणी-1)। समाजवादी उत्पादन की प्रगति के अनेक कारण हैं जिनमें वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति के फलों का प्रयोग भी शामिल है। उपचार विकास-दर अतिम रूप से आर्थिक प्रतियोगिता के परिणामों को निर्धारित करती है। वे यह बताती हैं कि कौन-सी व्यवस्था जनमणना की रचनात्मक ऊर्जा व जनमण द्वारा निर्मित उत्पादन साधनों का अधिक सहजगत रूप से उपयोग कर सकती है और अल्प प्रमाणाँ तरीके से सामाजिक उत्पादन का संयोजन कर सकती है।

सारणी-1 के आँकड़े यह जनमाने हैं कि समाजवादी देशों की औसत वार्षिक विकास-दर पूँजीवादी देशों की तुलना में लगभग दुगुनी रही है। 1950 के आँकड़ों की तुलना में 1979 में समाजवादी देशों में औद्योगिक उत्पादन 14 गुना बढ़ा था जबकि विभिन्न पूँजीवादी देशों में चार गुना था। 1979 में समाजवादी देशों में 1937 के आँकड़ों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन 24 गुना बढ़ा था जबकि इनके अर्थ में पूँजीवादी देशों में औद्योगिक उत्पादन 6.25 गुना ही बढ़ा। दुर्भाग्यवश और यदि हम समूह समाजवादी विश्व के उत्पादन की तुलना 1931 के समाजवादी देशों (अर्थात् सोवियत संघ और जर्मनिया) के उत्पादन से करें तो यह वृद्धि 46 गुना होगी जबकि पूँजीवादी देशों में वृद्धि 5.6 गुना रही। इस कारण 1950 और 1969 के बीच विश्व के औद्योगिक उत्पादन में समाजवादी देशों का हिस्सा दुगुना हो गया। 1950 में यह लगभग 20 प्रतिशत था जो 1973 में 47 प्रतिशत में बढ़ा। इनके साथ समाजवादी देशों का औद्योगिक उत्पादन विश्व के पूँजीवादी देशों के औद्योगिक उत्पादन के 75 प्रतिशत में पहुँच गया है।

सारणी-1
समाजवादी और अन्य देशों में औद्योगिक प्रगति
(1950 के प्रतिशत-प्रनुसार)

वर्ष	समस्त विश्व	समाजवादी देश	दोनों शामिल करते हुए		
			अन्य देश	औद्योगिक पूँजीवादी देश	विकासशील देश
1950	100	100	100	100	100
1955	147	191	135	132	156
1956	156	211	141	138	169
1957	164	234	145	142	183
1958	171	274	143	138	192
1959	192	327	159	155	208
1960	206	354	167	160	233
1965	285	501	227	218	329
1970	388	723	298	284	459
1979	623	14 गुना	421	391	747
औसत					
वार्षिक वृद्धि					
1951-79					
प्रतिशत में					
	6.5	9.5	5.1	4.8	7.2

सोवियत संघ और अमरीका के बीच औद्योगिक प्रतियोगिता का, दो विश्व-व्यवस्थाओं के बीच औद्योगिक प्रतियोगिता में विशेष महत्व है। दोनों देशों के पास आवश्यकतानुसार औद्योगिक व तकनीकी साधन हैं। सोवियत संघ विश्व-समाजवादी व्यवस्था द्वारा उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं के अत्याधिक मात्रा का उत्पादन करता है जबकि अमरीका विश्व के पूँजीवादी उत्पादन के लगभग 40 प्रतिशत का उत्पादन करता है।

महामुद्र के बाद की लगभग सारी वर्षों के दौरान यह बताया है कि वहाँ तक प्रमुख औद्योगिक-महलों की औसत वार्षिक वृद्धि दसों का लगभग है, सोवियत संघ अमरीका में काफी आगे है (देखिए सारणी-2)।

सारणी-2

मद	सोवियत संघ	अमेरिका
राष्ट्रीय आय	7.6	3.5
औद्योगिक उत्पादन	8.9	4.3
वृद्धि	3.2	1.9
कुल माल-बुलाई	7.6	2.4
पूंजी-निवेश	8.4	3.1
औद्योगिक श्रम उत्पादकता	5.8	3.2

आज सोवियत संघ में केवल विकास-दर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रों में कुल उत्पादन भी अमेरिका की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए 1979 में सोवियत संघ में कुछ प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन प्रतिशत अमेरिका की तुलना में इस प्रकार था—तेल (संचयित तैल सहित)—139; इस्पात—117; घनिष्ठ खाद—111, रेल के डीजल व बिजली के इंजन—175; सीमेन्ट—158; सूती वस्त्र—179, और ऊनी वस्त्र—456। सोवियत संघ अब तेल, इस्पात, घनिष्ठ खाद, सीमेन्ट, ऊनी वस्त्र और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में विश्व का नेतृत्व करता है। इससे सोवियत संघ की प्रति व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका की तुलना में आने में ऐतिहासिक विछोड़ के कारण होने के लिए ठोस आधार भूमि प्राप्त होती है।

सोवियत आर्थिक विकास अग्रगामी-दर विश्व-उत्पादन में उसके बड़े हुए भाग की निश्चय करती है। 1979 में सोवियत संघ विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग उत्पादन करता था। चापीय वस्तु में विश्व के ऊर्जा, तेल, रैत, इस्पात और मशीनरी निर्यात के कुल उत्पादन में सोवियत संघ का हिस्सा बढ़ता हुआ है।

विश्व-अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ की स्थिति मजबूत होने के साथ सोवियत संघ की औद्योगिक उत्पादन के अनुपात में भी अनुरूप आता है। अमेरिका की तुलना में वर्ष 1979 में सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन 1913 में 12.5 प्रतिशत, 1950 में 39 प्रतिशत और 1979 में 60 प्रतिशत में अधिक था। 1909 और 1956 के बीच सोवियत संघ का वृद्धि उत्पादन औसत रूप से अमेरिका के उत्पादन के 45 प्रतिशत का 1971-79 में यह औसत लगभग 85 प्रतिशत हो गया। 1979 में सोवियत संघ की औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में 67 प्रतिशत की वृद्धि 1953 में 11 प्रतिशत की।

पिछले दशक में सोवियत संघ ने अपने औद्योगिक उत्पादन के परिमाण को दुगुना कर लिया है। ऐसा करने के लिए ब्रिटेन को 25 वर्ष, पश्चिमी जर्मनी को 18 वर्ष, फ्रांस को 27 वर्ष और अमरीका को 16 वर्ष की जरूरत होती है।

पूँजीवाद के साथ आर्थिक प्रतियोगिता में समाजवाद की विजय की एक मुख्य शर्त उच्चतर श्रम उत्पादकता प्राप्त करना है। इस संबंध में लेनिन ने लिखा है—
“पूँजीवाद पूरी तरह परास्त किया जा सकता है और एक नयी व काफी उच्चतर श्रम-उत्पादकता को प्राप्त करते हुए समाजवाद द्वारा पूरी तरह परास्त किया भी जाएगा।”

विश्व-समाजवादी व्यवस्था के देशों में श्रम-उत्पादकता की दरें विकसित पूँजीवादी देशों की तुलना में तेज गति से बढ़ रही हैं और दोनों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। 1951-79 के बीच सोवियत संघ में औद्योगिक श्रम-उत्पादकता की वार्षिक औसत वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी जबकि अमरीका की वृद्धि-दर 4.2 प्रतिशत थी। (देखिए सारणी-2)

उत्पादन के कुल क्षेत्रों के महत्व के बावजूद आर्थिक विकास के स्तर का मुख्य संदर्भ भौतिक संपदा का प्रतिव्यक्ति उत्पादन है। यद्यपि समाजवादी देश अभी अधिकांश विकसित पूँजीवादी देशों के आर्थिक-विकास के स्तर तक नहीं पहुँच पाये हैं, लेकिन जीवन-स्तरों के अनेक संदर्भों में वे विकसित पूँजीवादी देशों ॥ अभी भी श्रेष्ठतर हैं। समाजवादी समुदाय के देशों में, जहाँ परजीवी उपभोग करनेवाला कोई शोषक-वर्ग नहीं है, राष्ट्रीय आय का उपयोग जनगण के कल्याण-कार्यों में सुधार व समाजवादी-उत्पादन के विस्तार के लिए किया जाता है। समाजवादी समुदाय के देशों में बेरोजगारी नहीं है और वहाँ सिय, जाति अथवा राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए सबको समान वेतन मिलता है। समाज ॥ सभी सदस्यों लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा-सेवाओं की गारंटी है। सोवियत संघ में संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक-कल्याण आदि के अनेक क्षेत्रों में अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। उत्पादन-क्षमता के विस्तार ने समाजवादी देशों को जीवन-स्तरों के कुछ खास संदर्भों में—जैसे प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय, मूलभूत धातु-पदार्थों व औद्योगिक उत्पादों का प्रतिव्यक्ति औसत उपभोग—अधिकांश विकसित पूँजीवादी देशों से आगे निकल जाने में समर्थ बना दिया है। इसका कारण आर्थिक विकास की उच्च दरें और वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं का उपयोग है।

समाजवादी व पूँजीवादी व्यवस्थाएँ वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति के सुफलों के

1. वी० आई० लेनिन, 'एक महत्त्वपूर्ण भूखंड, मोर्चा के पिछले भाग में कम्युनिस्ट बुद्धिमत्ता में कमजोरों की भोरता', संकलित रचनाएँ, भाग 29, पृ० 427 (बड़ेरी में)।

उपयोग की मूलतः भिन्न संभावनाओं को जन्म देती हैं। पूँजीपति वर्ग बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने व अधिकतम लाभ पाने के लिए इन उपलब्धियों का प्रयोग करने की कोशिश करता है। प्रमुख पूँजीवादी देशों में मैन्यू-जोइंगिफिक-समूह मैनिक उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों का अधिक-से-अधिक प्रयोग कर रहा है। इससे भौतिक-सामग्री, धन व वित्तीय संसाधनों का भारी अपव्यय हुआ है और अर्थव्यवस्था में वैषम्य की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा यह स्थिति मुद्रा-स्थिति को जन्म देती है व इन क्रांतिकारी उपलब्धियों के प्रसार को रोकती है।

पूँजीवादी विश्व में वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति वर्तमान सामाजिक-विरोधों के क्षेत्र की वजहनी है और नए विरोध उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक-वक्र की चाहे कोई भी बिगिष्ट अवस्था हो, स्वचालन बड़ी मात्रा में कार्य-भ्रमणों को अनावश्यक बनाकर कम कर रहा है और इस प्रकार बेरोजगारी में वृद्धि कर रहा है। वृष्टि का औद्योगीकरण व धन-उत्पादकता में तीव्र-वृद्धि व्यापक स्तर पर विगानों की बरबादी तथा कष्टदायक व विध्वंसक सामाजिक-भूरीकरण में बुरी हुई है।

विज्ञान और तकनीक के अनेक क्षेत्रों में समाजवादी देश विश्व का नेतृत्व करने हैं। उदाहरण के लिए, इसे अनगिण्त अनुगमन में सोवियत उपलब्धियों, परमाणु-शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग, जमीन-ऊर्जा केंद्र निर्माण में प्रवीणता, सही दूरियों पर जलन उष्ण कोष्पेज, ऊर्जा का सन्तुलन आदि में देखा जा सकता है। सोवियत संघ अद्वयन इत्यादि हमारी तकनीक में विश्व में पहले स्थान पर है और अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक-उत्पत्तियों के संचालन में इसके तकनीकी व आर्थिक परिणाम बरबरीदा की गुणता में उच्चतर है। समाजवादी देशों ने अपनी अर्थ-व्यवस्था में काम करने वाले कुशल कर्मियों की एक विज्ञान सेना तैयार करके वैज्ञानिक-तकनीकी कर्मों को और ज़ावे विकसित करने के लिए ठोस आशाश्रितता की स्थापना कर ली है।

जहाँ तक कोश-कार्य के लिए राष्ट्रीय आय में व्यय के प्रतिफल का सवाल है, सोवियत संघ व बरबरीदा की बरबरीदा कर भी है और उसने पश्चिमी यूरोप के विरुद्ध इनको का 100 प्रतिशत व पश्चिम कोश दिया है। पारम्परिक आर्थिक संचालन के अन्तर्गत बरबरीदा की महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कोश व विकास के लिए राष्ट्रीय आय का व्यय का प्रतिफल प्रतिशत व 100-200 प्रतिशत बढ़ गया है। समाजवादी देशों की महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वैज्ञानिक-तकनीकी के समानुपात कोश व विकास के प्रतिफल का प्रतिशत व 100-200 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे समाजवादी देश अर्थव्यवस्था में बरबरीदा की व विज्ञान-विकास के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बरबरीदा की व विकास के प्रतिफल का प्रतिशत व 100-200 प्रतिशत बढ़ गया है।

परस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् के सदस्य देशों के बीच आर्थिक वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने में 1971 का समाजवादी आर्थिक एकीकरण का व्यापक कार्यक्रम प्रमुख भूमिका अदा करेगा।

वर्तमान समाजवाद की आर्थिक शक्ति में सुस्थिर वृद्धि, विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया को तीव्र करने व पूँजीवाद के आम-संकट को गहरा बनाने का एक प्रमुख कारक है। समाजवादी देशों में जीवन-स्तरो में सुस्थिर वृद्धि, दो सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक विवाद में एक कायल करने वाला तर्क है।

लेनिन ने अपने समय में ही बताया था कि विजयी समाजवाद आर्थिक-विकास में अपनी उपलब्धियों के द्वारा ही विश्व-क्रांति के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा।

साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का संकट और पतन

साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का संकट व पतन पूँजीवाद के आम-संकट का अनिवार्य भाग एवं एक प्रमुख संकेत है। नए देश, जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक समय के विशाल उपनिवेशी साम्राज्यों के खंडहरों के ऊपर प्रकट हुए हैं। विकासशील देशों में से कुछ ने विकास का गैर-पूँजीवादी रास्ता चुना है। इस प्रकार लेनिन का यह पूर्व अनुमान सच हो रहा है कि उपनिवेशी और पराधीन देशों के जनता राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष आरम्भ करने के बाद शोषक व्यवस्था की आधार-शिलाओं के विरुद्ध संघर्ष करने की ओर बढ़ेंगे। उपनिवेशी व्यवस्था का पतन साम्राज्यवाद के लिए एक नया शक्तिशाली आपात या और इसने उसकी राज-नीतिक, आर्थिक स्थितियों को भरपूर मात्रा में निर्वस किया। उपनिवेशी-व्यवस्था का संकट और पतन, विश्व के दो विरोधी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के विभाजन के बाद शुरू होने वाले पूँजीवाद के आम-संकट की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

1. उपनिवेशी व्यवस्था का पतन : पूँजीवाद के आम-संकट की एक अभिव्यक्ति

उपनिवेशी व्यवस्था का संकट उपनिवेशी विश्व में उस संघर्ष के सीधे हो जाने को सूचित करता है जो उपनिवेशी व पराधीन साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को पहले निर्वस बनाना है और फिर उपनिवेशी व्यवस्था के संकट के कारणों की जड़ इसके गहरे आंतरिक बनावट

विरोधों में है, मुख्य रूप से साम्राज्यी देश के साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग तथा पराधीन देशों के जनगण के बीच अंतर्विरोधों में तीव्र वृद्धि और साम्राज्यवाद के उपनिवेशी जुए की व्यवस्था तथा उपनिवेशों में उत्पादक-शक्तियों के बीच द्वंद्व की स्थिति में है। साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा उपनिवेशी देशों का शोषण और जिन आर्थिक संबंधों को वे स्थापित करते हैं, वे स्वयं उपनिवेशी विश्व में उत्पादक-शक्तियों के विकास को रोकते हैं। जिन जनगणों ने प्राचीनकाल से विरव-सभ्यता में मूल्यवान् भौतिक व आध्यात्मिक योगदान दिया है, साम्राज्यवाद के कारण अब वे स्वयं को सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के खंगुल में फँसा पाते हैं और उनके प्रचुर रूप से समृद्ध प्राकृतिक ससाधन हिंसात्मक तरीकों से लूटे जाते हैं।

पराधीन देशों में उपनिवेशी सत्तारों की व्यवस्था के विनाश और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियों की सफलता के लिए बस्तुनिष्ठ ही नहीं, आत्मनिष्ठ स्थितियाँ भी परिपक्व हुईं। पूँजीवाद के विनाश के साथ, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग, राष्ट्रीय बुद्धिजीवी और मजदूर वर्ग का भी निर्माण हुआ। ये वे राजनैतिक शक्तियाँ थीं जो उपनिवेशी शासनों के विरुद्ध कार्य करने के लिए जनगणों को आंदोलित कर सकती थीं।

विदेशी इजारेदारों के कारखानों व बागानों के मजदूर धूम्र मरने लायक ही मजदूरी पाते थे और उन्हें साम्राज्यी देश के मजदूर वर्ग को प्राप्त आर्थिक-राज-नैतिक अधिकारों में कुछ छोटे अधिकार ही दिये गये थे। स्थानीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के कारखानों को विदेशी उत्पादनों से प्रतियोगी सक्षम में आयात प्रतिन समय का सामना करना होता था। इससे राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग में असन्तोष उत्पन्न हुआ। इसका अपवाद स्थानीय पूँजीपति वर्ग का वह हिस्सा था जो मेहनतकों के शोषण में विदेशी पूँजी की मदद करता था। इस समूह—तथाकथित हमाल पूँजीपति वर्ग—ने उपनिवेशी शासन का समर्थन किया।

उपनिवेशी व्यवस्था स्थानीय किसानों की जानू थी, जो उपनिवेशवादी और 'अग्ने' क्योन्गर दोनों से ही शोषित होते थे। इसी कारण किसान वर्ग ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्षम में सक्रिय भाव लिया। हमने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया क्योंकि पराधीन देशों की जनसंख्या में किसान ही सबसे बड़ा भाग है।

कुछ विरागशील देशों में सामुदायिक व्यवस्था के अखंड अन्ध भी मजबूत हैं, उदाहरण के लिए अनेक अफ्रीकी देशों में किसानों द्वारा बुद्धि-वार्ध का आधार सामुदायिक सम्पत्ति है। इस कारण वहाँ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का नेतृत्व व्यक्तिगत प्रजापतिवाद के मस्तरों व सामाजिक समूहों—जैसे राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी, छोटी पूँजी वाले शोष तथा सेवा के प्रतिनिधियों—द्वारा बिना आगा है और सभी सामन-विरोधी व साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियाँ उनके कारणों पर एक-एक हो जाती हैं।

रूस में समाजवादी क्रांति की विजय उपनिवेशी जनगणों के सामने राष्ट्रीय व सामाजिक मुक्ति के लिए संघर्ष करने की एक अपील और उदाहरण थी। इस तथ्य ने कि सोवियत संघ में जातीय प्रश्न का समाधान कर लिया गया है, उपनिवेशी जनगणों को आत्ममुक्ति और उपनिवेशी शोषण के परिणामों पर विजय पाने का रास्ता दिखाया।

उपनिवेशी व पराधीन देशों में, विशेष रूप से पहले महायुद्ध के बाद, नवजात पूँजीवाद का उदय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को सक्रिय बनाने में सहायक हुआ। युद्ध के दिनों में साम्राज्यी देश व उपनिवेशों के बीच आर्थिक संबंध या तो विच्छिन्न हो गये या कम हो गये। और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात तेजी से गिरा। इसने उपनिवेशों में उद्योग के विकास तथा स्थानीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग व सर्वहारा वर्ग के विकास को प्रोत्साहित किया। जैसे ही इसने साम्राज्यवाद को समय रूप में कमजोर किया, युद्ध ने उसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के प्रहारों के सामने अधिक नाबल बना दिया।

रूस की समाजवादी अक्टूबर क्रांति से प्रभावित होकर चीन, भारत और हिन्देशिया में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों की एक लहर आयी। तुर्की में राष्ट्रीय क्रांति हुई, मोरक्को व अफ़ग़ानिस्तान में मुक्ति युद्ध हुए और हिन्द चीन, त्रिपिनीन और कोरिया में जन-विद्रोह हुए। 1921 में मंगोलिया में लोक-क्रांति हुई जिसने सोवियत संघ की प्रत्यक्ष सहायता से समाजवादी समाज का निर्माण आरंभ किया। 1922 में तुर्की में गणतंत्र की घोषणा हुई। मिस्र के जनपण ने भी अपनी स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता के लिए बहादुरी से संघर्ष किया और 1922 में ब्रिटेन मिस्र को आंशिक स्वतंत्रता देने के लिए विवश हुआ। इसी समय ईरान ने भी क्रांति स्वतंत्रता प्राप्त की। उपनिवेशी जुए के विरुद्ध संघर्ष में पराधीन राष्ट्र विजय पहले समाजवादी राज्य के अनुभव व समर्थन पर भरोसा करने में समर्थ थे।

लेकिन पूँजीवाद के आम-संकट के आरंभिक युग में उपनिवेशी व पराधीन देशों में क्रांतिकारी कार्य सदैव वास्तविक स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ने। पर साम्राज्यवादी शक्तियों ने कुछ देशों, जैसे ईरान, सीबिया एवं अन्य, को आंशिक स्वतंत्रता दी, फिर भी वे उन्हें साम्राज्यवाद पर निर्भर बनाये रखने में सफल रहे। 1920 व 1930 के दशक में भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ अधिकांश उपनिवेशी पराधीन देशों में राजनैतिक प्रभुत्व बनाये रखने में सफल रहीं। मजदूर वर्ग मापेल निर्वहता, किसानों की कारंवाइयों की असंगठित प्रवृत्ति और संयुक्त राष्ट्रीय साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा, जो देश-विशेष की सारी राजनैतिक शक्तियाँ सफाई कर सकता था, के अभाव के कारण ही वे ऐसा करने में समर्थ नहीं

मेकिन, ऐसा होने पर भी, इस अवधि के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है। जो उपनिवेशी व पराधीन देश पहले साम्राज्यवाद की शक्तियों

आरक्षित शक्ति थे, वे अब तनावपूर्ण राजनैतिक सघर्षों के क्षेत्र बन गये। इन उपनिवेशी देशों में राष्ट्रीय मुक्ति-सघर्ष के विकास ने यह दिखाया कि इन देशों के खूने शोषण का मुख अब बटन रूप में भूतकाल की पीछ हो गया है और मुक्ति जातियों का युग—कभी उत्पीड़ित रहे जनगणों के आग्रह व विश्व-क्रांतिकारी आंदोलन में उनके शामिल होने का युग—शुरू हो गया है।

दूसरे महायुद्ध के दौरान और युद्ध बाद के आरम्भिक दशकों में अर्थात् पूँजीवाद के आम-संकट की दूसरी अवस्था में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन गुणात्मक रूप से एक नये स्तर तक विकसित हुए। इसने साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था की इमारत भरभराकर गिर पड़ी। साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था के संकट के बाद उसका पतन जाया जो सार रूप में ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशी व पराधीन देशों के उत्पीड़न पर आधारित आर्थिक-राजनैतिक संबंधों का अंत हुआ और भूतपूर्व उपनिवेशों में नये स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई।

दूसरे महायुद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की आगे बढ़ाने वाली धरेलू व अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही परिस्थितियों में अप्रमूल परिवर्तन हुए। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के निरन्तर विकास के लिए यूरोप में फासीवाद पर विजय और एशिया में सैन्यवादी जापान की हार बहुत महत्वपूर्ण थी। सोवियत संघ की विजय में यह विजय दिया कि समाजवाद की भूमि अजेय है और वह साम्राज्यवाद-विरोधी विश्व-संघर्ष का केन्द्रीय स्तंभ है। इसके साथ हिटलरि जर्मनी व सैन्यवादी जापान—अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ—जो सबसे अधिक शर्मनाक डिस्म के जातिवाद तथा राष्ट्रीय उत्पीड़न का समर्थन करती थीं—की हार समकालीन साम्राज्यवाद की संपूर्ण विचारधारा की गंभीर पराजय व मुक्ति के विचारों की विजय को प्रकट करती थी। यूरोप व एशिया के अनेक देशों में समाजवादी जाति की विजय तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न विश्व-समाजवादी व्यवस्था राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के और आगे विकास के लिए निर्णायक महत्व की थी।

पूँजीवाद के आम-संकट की पहली अवस्था में सोवियत संघ उपनिवेशी जनगण को मुख्य रूप से नैतिक व राजनैतिक समर्थन ही दे सका था। नयी स्थिति में, केवल सोवियत संघ ही नहीं, संपूर्ण विश्व-समाजवादी व्यवस्था साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में उपनिवेशी विश्व को सहायता दे रही है। यह सहायता नैतिक व राजनैतिक समर्थन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक व सैनिक सहायता भी शामिल है।

दूसरे महायुद्ध के तुरंत बाद एशिया उपनिवेशी शासनों के विरुद्ध संघर्ष का मुख्य क्षेत्र बन गया। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत के अनेक विभिन्न आन्दोलन

वाद भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता देने के लिए वाध्य हुआ। हिन्देशिया बर्मा, श्रीलंका का गणराज्य और अन्य एशियाई देशों ने भी उपनिवेशी शासनों को उखाड़ दिया। 1944 व 1954 के बीच 15 एशियाई देशों ने, जो सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के भूतपूर्व उपनिवेश थे, स्वतंत्रता प्राप्त की। अफ्रीका में भी उपनिवेशी व्यवस्था का पतन निकट दिखाई दे रहा था। अनेक देशों ने जैसे मिल सूडान, द्यूनेशिया और मोरक्को ने स्वतंत्रता प्राप्त की। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशी विश्व में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने के भूतपूर्व उपनिवेशी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के प्रयत्न असफल रहे।

पूँजीवाद के आम-संकट की आरंभिक तीसरी अवस्था, जो 1950 के दशक उत्तरार्ध में आरम्भ हुई, का मुख्य लक्षण साम्राज्यवाद का और अधिक निर्बल होना था। इसे उपनिवेशी व्यवस्था के निर्णायक पतन उपनिवेशों को पूर्ण राजनैतिक मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए विकासशील देशों के तीव्र संघर्षों ने देखा जा सकता है। एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलता रहा—उस समय मध्य-पूर्व (पश्चिमी एशिया) उपनिवेश-विरोधी संघर्ष का मुख्य केंद्र हो गया था। अरब देशों के संघर्ष ने मध्य-पूर्व व अफ्रीका में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध समग्र संघर्ष पर सकारात्मक प्रभाव डाला। साम्राज्यवाद व इस्त्रायल आक्रमण के विरुद्ध यह संघर्ष, स्वतंत्रता और समाजवाद की विश्वव्यापी शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा करने वाले आम-संघर्ष का भाग था।

अफ्रीका में भी भारी परिवर्तन हुए। अक्टूबर 1960 में 17 अफ्रीकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और 1980 के दशक के आरम्भ में अफ्रीका में 50 से अधिक सार्वभौम देश हो गये थे। गिनी-बिसाऊ, मोजाम्बिक और अंगोला के जनगणतन्त्र कठिन संघर्षों के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। देशभक्त क्रांतिकारी जनवादी संगठनों—मोजाम्बिक की मुक्ति के लिए मोर्चा (फ्रीलिमो), केपवर्दे द्वीप व जिम्बाब्वे के क्रांतिकारी दल और अंगोला की मुक्ति का लोकप्रिय आंदोलन (एम्पी० एल० ए०), जो उपनिवेशी जनगणों के मुक्ति-संघर्ष के हरावत दस्तक दे रहे हैं—के नेतृत्व में इन देशों के जनगणों ने पुर्तगाली साम्राज्यवाद पर भारी प्रहार किया। आतंक और हिंसा से अफ्रीकी देशभक्तों को कुचलने की पुर्तगाल की सत्ता खार व केटानो की फ्रांसिस्ट सरकारों के प्रयत्न पूरी तरह असफल हुए। गिनी-बिसाऊ, मोजाम्बिक और अंगोला के जनगणों के सशस्त्र संघर्ष ने उपनिवेशवादियों को सैन्य-क्षेत्र में ही पराजित नहीं किया, स्वयं पुर्तगाल में भी जनवादी आंदोलन को मजबूत करने में बहुत प्रोत्साहन व सहायता पहुँचायी। और अप्रैल 1974 में फ्रांसिस्ट तानाशाही के उच्छेदन को प्रोत्साहित किया। गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक और अंगोला के जनगणों के लम्बे सशस्त्र संघर्ष में सोवियत संघ ने उन्हें बड़ी सहायता

में नैतिक व भौतिक सहायता दी।

अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति की शक्तियों और उपनिवेशवाद के बीच ऐतिहासिक युद्ध ने महाद्वीप की सीमाओं का दूर तक अतिक्रमण किया। अफ्रीका में उपनिवेशी शासनों को समाप्त करने का संघर्ष, संभवतः विश्व की प्रगतिशील व शांतिकामी शक्तियों के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का आगिक भाग हो गया है।

आये प्रस्तुत आँकड़े, पूँजीवाद के आम-संकट की तीसरी अवस्था में साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था के बढ़ते पतन के सूचक हैं। युद्ध बाद के आर्थिक दशक में एशिया व अफ्रीका के 14 देशों ने स्वयं को उपनिवेशी जुए से मुक्त किया, परवर्ती दशक में अफ्रीका व एशिया के 50 से अधिक देशों ने उनका अनुसरण किया।

साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की लपटें पश्चिमी गोलार्ध में भी फैल गई हैं। वहाँ राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के कुछ विशिष्ट सक्षण हैं। अधिकांश सातीनी अमरीकी देशों ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, किंतु वे साम्राज्यवादी शक्तियों पर आर्थिक निर्भरता की स्थिति में पँस गये। अब उनके जनगण अमरीकी तथा अन्य साम्राज्यवादी हथारेदारियों के विरुद्ध और असली राष्ट्रीय प्रभुसत्ता व आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। क्यूबा के बहादुर जनगण पश्चिमी गोलार्ध में समाजवादी क्रांति करने वाले पहले जनगण थे और क्यूबा की क्रांति असली राष्ट्रीय स्वतंत्रता व सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष में सारे सातीनी अमरीकी जनगण के लिए एक उदाहरण बन गयी। सत्तर के दशक की विशेषता थी—सातीनी अमरीकी जनगण द्वारा अपनी स्वतंत्रता, जनतंत्र व सामाजिक प्रगति को दुरु करने के लिए बड़ी हुई मात्रा में सशस्त्र संघर्ष। उरुग्वे की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रथम सचिव रोडने एरिसमेडी ने बताया है—“क्यूबा की क्रांति द्वारा शुरू किये गये दशक के परिणाम दिखाने हैं कि अमरीका मुक्ति संघर्षों को सफल गति में लगातार ऊपर चढ़ते मार्ग पर विकास करने से रोकने में असफल रहा है।”¹

बिसी में 1970 के राष्ट्रपति-चुनाव में अनेक प्रगतिशील दलों के गठबन्धन के उम्मीदवार साल्वेदोर एम्बे की विजय की लागीनी अमरीका में व्यापक प्रतिबन्धिता हुई। बिसी की लोकप्रिय एगता की सरकार ने अपने तीन वर्ष के शासनकाल में अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राष्ट्रीयकरण किया और विदेशी हथारेदारियों, विशेष रूप से अमरीकन हथारेदारियों की कनिबद्धियों पर रोक लगा दी। विदेशी हथारेदारियों की खानें, बैंक व कारखाने सरकार द्वारा अधिकार में ले

1. बार + एरिसमेडी, 'नेशनल क्रांति और लागीनी अमरीका', जलका, 1973, पृ. 524 (कपी है)।

राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन समकालीन विश्व-क्रान्तिकारी प्रक्रिया का भागिक भाग बन गया है। नये सार्वभौम राज्यों के—जो उपनिवेशी साम्राज्यों के खड्डरों में उत्पन्न हुए हैं, जनगण साम्राज्यवाद की राजनैतिक, आर्थिक व मैनिफेस्ट-सामरिक स्थितियों पर शक्तिशाली प्रहार कर रहे हैं। उपनिवेशी व्यवस्था का पतन और-आर्थिक शोषण, श्रुते बम प्रयोग और सूटमार (जो उपनिवेशी युग की विशेषताएँ थी) के अंग को मूषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय इजारेदार पूँजी अब और अधिक अपने मूलपूर्व उपनिवेशों की श्रमशक्ति व भौतिक साधनों का दृष्टानुसार प्रयोग नहीं कर सकती है। उपनिवेशी दागता की व्यवस्था के पतन का परिणाम मूलभूत शक्तियों के सहसंबंध में भारी परिवर्तन हुआ है। वस्तुनिष्ठ रूप से, राजनैतिक रूप से स्वाधीन राज्य साम्राज्यवाद-विरोधी व क्रान्तिकारी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। नये सार्वभौम राज्यों का भारी बहुमत साम्राज्यवादी तैनिफ-मुक्त में शामिल नहीं है। वे सटखता की नीति का पालन करते हैं और एक नये विश्व-युद्ध को रोकने के समर्थक हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता मूलपूर्व उपनिवेशों के अगमन के लिए आर्थिक आराम-निर्भरता, उच्चतर जीवन-स्तर और अपनी भावनाओं के पुनरुत्थान व विकास के लिए राह खोलती है।

2. गत-उपनिवेशवाद

जब उपनिवेशों में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने उन्हें आर्थिक व राजनैतिक बंधन में बनाये रखने के लिए नये तरीकों व रूपों का प्रयोग शुरू कर दिया। आधुनिक उपनिवेशवाद अर्थात् नव-उपनिवेशवाद विकासशील देशों में साम्राज्यवाद की स्थिति को बनाये रखने व मजबूत करने के लिए आर्थिक, राजनैतिक, विचारधारात्मक व अन्य उपायों की समग्र श्रुधला है। उपनिवेशवाद मूलतः तीर आर्थिक दमन और सूटमार के तरीकों का प्रयोग करता था, नव-उपनिवेशवाद नयी ऐतिहासिक स्थितियों के अनुकूल अधिक सूक्ष्म तरीकों से अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। किन्तु इसका अर्थ अपने दुहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष दबाव (जिसमें विकासशील देशों के मामलों में सशस्त्र हस्तक्षेप भी शामिल है) का त्याग नहीं है। नव-उपनिवेशवाद के ये दोहरे उद्देश्य हैं—एक, विकासशील देशों में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना व उसका विस्तार करना और इजारेदारी शोषण को तीव्र करना; दो, जिन देशों ने स्वयं को उपनिवेशी व्यवस्था से मुक्त कर लिया है, उन्हें विकास के और-पूँजीवादी रास्ते को रोकना और उन्हें विश्व-पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर बनाये

उपनिवेशवाद का एक महत्वपूर्ण रूप है—विकासशील देशों को पूँजी-उत्पत्ति के क्षेत्र में) का निर्माण। इस 'सहायता' का अधिकांश भाग

सा साम्राज्यवाद की आक्रामक योजनाओं, सामरिक खरूरतों और विश्व-समाजवादी व्यवस्था के विकट संघर्ष में विकासशील देशों को अग्रमोर्चा के रूप में बदलने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साम्राज्यवादी, राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था में अपनी प्रभावशाली स्थिति बनाये रखने और इजारेदार के पक्ष में उनका उपयोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उपनिवेशी-व्यवस्था के पतन से पहले उपनिवेशों में पूँजी का निर्यात मुख्य रूप से निजी निवेशों के द्वारा किया जाता था, अब पूँजीवाद के आम-सचट की दूसरी और विशेष रूप से तीसरी अवस्था में राज्य द्वारा नियंत्रित पूँजीवाद का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, विदेशों में अमरीका के राजकीय निवेश 1950 में 11.09 अरब डॉलर से बढ़कर 1978 में 54.2 अरब डॉलर अर्थात् पाँच गुना से अधिक हो गये हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बहुत से विकासशील देशों ने विदेशी निवेशों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप हमारे महायुद्ध के बाद आरंभिक दशकों में निजी इजारेदार पूँजी का प्रवाह सापेक्ष रूप से कम हो गया। मूलतः उपनिवेशों की शोषण का श्रेष्ठ बनाये रखने के लिए पूँजीवादी राज्य इजारेदारों की सहायता के लिए आगे आ गया है।

राजकीय पूँजी के निर्यात के साथ विकासशील देशों को निजी इजारेदार पूँजी का निर्यात अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विकासशील देशों को पूँजी का राजकीय निर्यात निजी निवेश के लिए रास्ता साफ करता है। साम्राज्यवादी देश नये राष्ट्रों को ऋण व अनुदान देने हैं और इसके बदले में विदेशी निजी निवेश के लिए 'अनुकूल वातावरण' बनाये रखने तथा अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय-करण की स्थिति में उनके हितों के लिए गारंटी आदि की माँग करते हैं। विकासशील देशों की निजी पूँजी ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान पा लिया है। 1960-67 में अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से राजकीय पूँजी का प्रभुत्व का लेकिन तब के बाद स्थिति बदल गयी है। 1970 के दशक के अंत में विकासशील देशों में अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान और फ्रांस का निजी निवेश एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका में उनके कुल निवेश का 2 प्रतिशत था।¹

पूँजीवादी अर्थशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूँजी का निर्यात विकासशील देशों में आर्थिक व सांस्कृतिक प्रगति के लिए सहायक है। लेकिन वे इस तथ्य को छुपाते हैं कि विकासशील देशों में निवेश से साम्राज्यवादी राज्यों का इजारेदार पूँजीपति वर्ग को मुनाफा प्राप्ति करना है वह उनके नये निवेश में बाँझी

1 'विकासशील देशों में प्रमुख निजी विदेशी निवेश', कॉन्फ्रंटेशन, जनवरी 1979, पृ. 73-78 (अंग्रेजी में)।

रखा है। अमरीका के अधिष्ठान औरों के अनुसार विकासशील देशों में अमरीका के प्रत्यक्ष निजी निवेश की कुल राशि 1970-78 में 19.2 अरब डॉलर से बढ़कर 40.5 अरब डॉलर अर्थात् 2.7 गुना अधिक हो गयी जबकि इसी अवधि में अमरीका को वार्षिक रूप में भेजा गया अनुकूली मुद्रा मुनाफा 2.9 अरब डॉलर से छप्पाँग सगाकर 8.9 अरब डॉलर अर्थात् 3.1 गुना अधिक हो गया। 1970-78 के बीच विकासशील देशों से अमरीका को मुद्रा मुनाफे के रूप में लगभग 45 अरब डॉलर की राशि भेजी गयी। यह तथ्य कि साम्राज्यवादी इजारेदारियाँ विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा बाहर ले जाती हैं, विकासशील देशों के उत्पादन-शक्तियों के विकास में बाधा डालना है और घरेलू पूँजी के संघर्ष को बढ़ावा देता है। निवेश द्वारा होने वाली आय का भुगतान, विकासशील देशों के भुगतान समुलन में घाटा रहने का मुख्य कारण है। विदेशी इजारेदार पूँजी, खासगीर से अब वह विकासशील देशों में प्रत्यक्ष-निवेश के रूप में प्रवेश करती है, उनकी अर्थ-व्यवस्था के उपनिवेशी ढाँचे को मजबूत करती है और सार्वजनिक-क्षेत्र की वृद्धि को रोकने के साथ-साथ उद्योगों के विषम विकास को बढ़ाती है। देशी निजी अथवा सार्वजनिक पूँजी के नियोजन के साथ मिश्रित कंपनियाँ बनाते समय विदेशी व स्यासीय निवेश के बीच अनुपात के सवाल का फैसला विशिष्ट विकासशील देश की सामाजिक नीति की सकल-दिशा के मानदंड और उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार होता है। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा किसी विशेष विकासशील देश को दी गयी 'सहायता' विशिष्ट दशाओं के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह आर्थिक गुलामी का साधन बन सकती है और इजारेदार पूँजी के निवेश क्षेत्र व बाजारों के विस्तार का मार्ग भी बन सकती है। कुछ अन्य मामलों में 'सहायता' उपयोग नये क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है ताकि बाद में उन्हें विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सके। अनेक उदाहरणों में जन-विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को सहायता देने या राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलनों के विरुद्ध लड़ने के लिए साम्राज्यवादी देशों से राजकीय ऋण और अनुदान सहायता दी जाती है। कुछ खास देशों में, जिन्हें 'सहायता' दी गई है, अमरीका ने सैनिक बट्टे स्थापित कर लिये हैं और सेना तैनात कर दी है। अतः पूँजी का निर्यात चाहे किसी भी रूप में किया जाये, अभी भी सबाई यह है कि यह उपनिवेशी-शोषण का एक प्रमुख तरीका और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को दबाने का साधन है।

इन दिनों, अर्थ के पूँजीवादी-विभाजन की व्यवस्था में शामिल होने के लिए विकासशील देशों को प्रोत्साहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियाँ नव-उपनिवेश-व्यवस्था में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के बीच में औद्योगिक-विकास को नियंत्रित तथा उसका प्रयोग करने दिना-चाहती है। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएँ अधिकाधिक मात्रा

में साम्राज्यवाद पर निर्भर हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय 'इजारेदारियों' विकासशील देशों में नव-निर्मित औद्योगिक-उद्यमों को, एक औद्योगिक-समूह भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग फैली संयोजन इकाई और अन्यत्र निर्मित होने वाले उत्पादों के अलग-अलग हिस्सों की आपूर्ति करने वाला समझती हैं। अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियाँ (अथवा बहुराष्ट्रीय नियम) विकासशील देशों की स्थितियों के अनुरूप बन जाती हैं। यदि उन्होंने खनिज-बोहन (मुख्य रूप से पेट्रोल-तेल) पर से प्रत्यक्ष-नियंत्रण खो दिया है तो उन्होंने निर्माण-उद्योग में घुसपैठ कर ली है। विकासशील देशों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के मुँहोटे के पीछे वे वास्तव में औद्योगिक नव-उपनिवेशवाद का क्रियान्वयन ही कर रहे हैं।

विकासशील देशों व साम्राज्यवाद के बीच व्यापार पर भी नव-उपनिवेशवाद के हाथ की छाप है। उनके बीच विनिमय का असंतुलन न केवल कम ही मही हुआ है, बल्कि बढ़ गया है। विकासशील देशों द्वारा नियंत्रित किये जाने वाले औद्योगिक व कृषिजन्य कच्चे माल की ऊँची कीमतें, पूँजीवादी देशों द्वारा भेजे जाने वाले औद्योगिक सामान की ऊँची कीमतों से पीछे रही हैं। समुस्त राष्ट्र संघ [॥] आँकड़ों के अनुसार कीमतों के स्तरों में इस बढ़ते अंतर के कारण 1960-70 के दशकों के बीच विकासशील देशों को लगभग तीन अरब डॉलर की हानि हुई। यह हानि अब औद्योगिक रूप से विकसित पूँजीवादी देशों द्वारा उन्हें दी जाने वाली मुफ्त सहायता की राशि से अधिक हो गयी है।

कोई भी यह देख सकता है कि विकासशील देशों की सार्वजनिक व निजी पूँजी के बढ़ते निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों के बढ़ते क्रियाकलाप और विकासशील देशों के विदेश व्यापार में बढ़ते असंतुलन के साथ इन देशों से धन बाहर आ रहा है। यह धन मुताफ़ों व लाभार्थों के हस्तान्तरण, ऋण व उधार के पुनर्भुगतान, इजारेदारी मूल्यों के प्रयोग के द्वारा औद्योगिक उत्पादों के कुछ भाग के पुनर्वितरण के रूप में बाहर आ रहा है। युद्ध के बाद धन का यह बहिर्गमन विकासशील देशों में वित्तीय संसाधनों के आगमन से अधिक हो गया है। औद्योगिक-रूप से विकसित देशों के नाम उनके कर्ज में तीव्र वृद्धि इसका अप्रत्यक्ष सूचक है। व्यापार और विकास के लिए समुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन (अंकटाड-UNCTAD) के अनुसार 1979 के शुरू में यह कर्ज 285 अरब डॉलर था।¹

वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति के प्रभाव से, उपनिवेशी पराधीनता से स्वयं को मुक्त करने वाले देशों को उच्च-स्तरीय योग्यता-संपन्न व्यक्तियों की अत्यावश्यक जरूरत होती है। लेकिन साम्राज्यवादी देश विकासशील देशों से उच्च-स्तरीय विशेषज्ञों को बाहर निकालने के लिए बनेक तरह के तरीकों का प्रयोग कर रहे

है। ऐसा होने पर विकासशील देशों को दुहरा मुक्तमान—विशेषज्ञों का और उनके प्रतिष्ठान पर श्रुत किये गये धन का, होता है। यूनेस्को (शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन) के अनुसार 1970 में विकासशील देशों ने धरने कमियों की शिक्षा व प्रतिष्ठान पर लगभग 12 अरब डॉलर खर्च किये। इस कार्य के लिए अन्य देशों ने उन्हें लगभग डेढ़ अरब डॉलर की सहायता मिली जबकि मुश्किल कमियों के बाहर धने जाने से उन्हें लगभग 8-10 अरब डॉलर का मुक्तमान हुआ।

युद्धोत्तर काल की एक विशेषता तथाकथित सामूहिक मंद-उपनिवेशवाद (विकासशील देशों को मुक्तमान बनाये रखने के उद्देश्य में साम्राज्यवादी शक्तियों के संयुक्त-प्रयत्न की व्यवस्था) का प्रकट होना व उसका विनाश है। सामूहिक उपनिवेशवाद का एक रूप विकासशील देशों को शैक्षणिक आर्थिक गुटों, (जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसमें फ्रांस व बेल्जियम के भूतपूर्व उपनिवेश सहायक सदस्य के रूप में शामिल हैं) में शामिल करना है। इन संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निगम अपनी पुरानी उपनिवेशी सुविधाओं को बनाये रखने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं बल्कि नयी विशेष सुविधाएँ पाने की कोशिश भी करते हैं। ताकि वे अफ्रीका के भूतपूर्व उपनिवेश व अर्ध-उपनिवेशी देशों के संसाधनों के संयुक्त शोषण का प्रबंध कर सकें। अफ्रीकी बाजारों में पश्चिमी यूरोप की इजारेदारियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापक प्रवेश देशीय उद्योग को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। अल्प-उत्पत्तियों से लैस छोटे उद्यमों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पाद न तो क्रीम में और न गुणवत्ता में ही बढ़ी यूरोपीय कंपनियों के उत्पादों से होड़ कर पाते हैं। इसके साथ अफ्रीका के विकासशील देशों की एक विशेषता, मूल्यवान औद्योगिक या कृषिजन्य कच्चा माल उत्पादन करनेवाले उन एक या दो क्षेत्रों का तीव्र विकास है, जिनके विकास में आर्थिक-रूप से विकसित पश्चिमी देशों के उद्योगों की सक्रिय दिलचस्पी है। इसके परिणामस्वरूप अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक ओर अभी तक अपनी अनिवार्य 'एक क्रमसी' विशेषता को बचाये हुए हैं, दूसरी ओर वे औद्योगिकीकरण में मंद गति का सामना करती हैं क्योंकि शिशु देशी उद्योग पश्चिमी यूरोप की इजारेदारियों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धिता नहीं कर पाते हैं। अफ्रीकी देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय से मिलने वाले ऋण का निवेश मुख्य रूप से आधार-भूत ढाँचे के विकास और परंपरागत सामान के निर्माण की वृद्धि में करते हैं, बहु-क्षेत्रीय स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाली परियोजनाओं में नहीं करते।

ऋण देने और वित्तीय निवेश करने वाले संगठन जैसे—युननिर्माण व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई० बी० बार० डी०), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई० एम० एफ) तथा अन्य संगठन, सामूहिक उपनिवेशवाद के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। वे मुख्य रूप से निजी इजारेदारियों द्वारा विकासशील देशों को निर्माण की

पयी पूँजी की सुरक्षा की भारंटी देते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रायः उन देशों को ऋण देने हैं जो साम्राज्यवाद को आर्थिक-राजनैतिक छूट देते हैं और जो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोधी हैं उन्हें ऋण देना वे नापसंद करते हैं।

राष्ट्रीय उद्योग के निर्माण के लिए विज्ञान संमाधनों की जरूरत होती है। विकासशील देशों में नयी परियोजनाओं के लिए वित्त-प्रवर्धन मुख्य रूप से राग्य करता है और इससे बजट संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इजारेदार पूँजी के हितों की रक्षा करने वाला संगठन) से सहायता माँगते हैं तो कोष सदैव जल्दी से सहमत नहीं होता। विकासशील देशों में मुद्रा-प्रणाली को 'सापान्य' करने के लिए कोष अक्सर आर्थिक-विकास की दरों व सार्वजनिक खर्च को कम करने की माँग करता है। कोष का तेजस्व अपने सदस्य देशों में औद्योगिकीकरण को हानि पहुँचाने हुए भी वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देने की माँग करता है यद्यपि आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगिकीकरण को सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। आई० डी० आर० डी० भी इन्हीं नीतियों के अनुसार काम करता है।

सैनिक सत्ताशाही और कठपुतली शासनो की स्थापना एक ऐसा तरीका है, विकासशील देशों में अपनी सर्वोच्चता बनावे रखने के लिए साम्राज्यवादी देश जिसका व्यापक प्रयोग करते हैं। जब जन-समूह भ्रष्ट शासकों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो साम्राज्यवादी 'स्वतंत्रता व प्रजातंत्र' के बहाने से मुक्ति-आंदोलनों को बन-प्रयोग से दबाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। अफ्रीका और लातीनी अमरीका के राग्य इस तरह के हस्तक्षेप के हमेशा शिकार रहे हैं। तथ्यों से पूरी तरह प्रकट है कि साम्राज्यवाद ने अपने लुटेरेपन के सारतत्त्व को अभी नहीं छोड़ा है। विकासशील देशों के विरुद्ध प्रत्यक्ष राजनैतिक-आर्थिक व सैनिक दबाव के प्रयोग को छोड़ें बिना आधुनिक उपनिवेशवादी विचारधारात्मक भीतरघात के तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। इन विशेष विचारधारात्मक धारणाओं में से एक 'वर्ग-शांति' और 'भागीदारी' की धारणा प्रमुख है। आधुनिक पूँजीवादी अर्थशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्ग-सहयोग विकासशील देशों में आर्थिक-विकास को तीव्र करेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिकन प्रो० जॉन पी० पावेलसन के अनुसार विकासशील देशों के अभी तक पिछड़े बने रहने का मुख्य कारण उत्पादन में शामिल शोर्षों के बीच परस्पर विश्वास की कमी है। पावेलसन बल देकर कहते हैं—“अल्प विकसित देशों का ऐसा स्पष्ट रूप से परिभाषित समूहों में विभाजन, (जैसे, सेना राजनीतिज्ञ, जमींदार, व्यापारी, भजदूर, किसान, जनजाति, छात्र आदि) जो न केवल एक-दूसरे से संपर्क ही नहीं रखते हैं बल्कि सक्रिय रूप से एक-दूसरे के प्रति नापसंदगी व अविश्वास के भाव रखते हैं तथा भुक्तान पहुँचाने की

हैं। ऐसा होने पर विकासशील
उनके प्रशिक्षण पर खर्च किये गये
संस्कृति के लिए संयुक्त राष्ट्र
देशों ने अपने कमियों की शि
किये। इस कार्य के लिए अन्त
मिली जबकि कुशल कमियों के
का नुकसान हुआ।

मुद्रोत्तर काल की ए
(विकासशील देशों को मुद्रा
समुक्त-प्रयत्न की व्यवस्था)
निवेशवाद का एक रूप टि
आर्थिक समुदाय, जिसमें
आ में शामिल है) में आ
अन्नी पुरानी उपनिवेश
बन्धन नही विशेष मुद्रा
भूतपूर्व उपनिवेश ब
कर सके। अन्नीकी
वस्तुओं का आयात
है। अन्ना-उत्तराण
में और न मुद्रा
इसके साथ अन्नी
या वृद्धिजन्य ब
है, जिनके बिना
दिलचस्पी है।।
मद अन्नी ३
औद्योगिकीकरण
परिष्करी मूरा
देन मूरांरीव
मूरा इव के
लेखक कथ

From the 1950s to the 1980s

attest to the quality of the paper.

[Faint handwritten notes]

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) = \frac{v}{c^2} \frac{dv}{dt}$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

... ..

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

— 111 —

[illegible]

100

... ..

... ..

... and ...

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

... ..

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

गणपतः सदा विजयते ॥

॥ अथ विष्णुसंस्कृतं ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1000

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१००० के लिए हमें मिलेगी १०००

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

1942

... ..

यगो पूँजी की सुरक्षा की भारती देने है। ये अंतर्राष्ट्रीय समूहन प्रायः उन देशों को ऋण देने हैं जो साम्राज्यवाद को आर्थिक-राजनैतिक छूट देने हैं और जो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोधी हैं उन्हें ऋण देना ये नापसंद करते हैं।

राष्ट्रीय उद्योग के निर्माण के लिए विनाश समाधनों की जरूरत होती है। विकासशील देशों में नयी परियोजनाओं के लिए वित्त-प्रबंध मुख्य रूप से राज्य करता है और इससे बहुत सखी वृद्धिनाइसी उत्पन्न होती है। जब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इजारेदार पूँजी के हितों की रक्षा करने वाला समूह) से सहायता मांगते हैं तो कोष सदैव जल्दी से सहमत नहीं होता। विकासशील देशों में मुद्रा-प्रसार को 'सामान्य' करने के लिए कोष अक्सर आर्थिक-विकास की दूरों व सार्वजनिक खर्च को कम करने की माँग करता है। कोष का नेतृत्व अपने सदस्य देशों से औद्योगिकीकरण को हानि पहुँचाते हुए भी वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देने की माँग करता है यद्यपि आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगिकीकरण को सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। आई० बी० आर० डी० भी इन्हीं नीतियों के अनुसार काम करता है।

सैनिक तानाशाही और वृद्धतसी शासनों की स्थापना एक ऐसा तरीका है, विकासशील देशों में अपनी सर्वोच्चता बनाये रखने के लिए साम्राज्यवादी देश वित्तका व्यापक प्रयोग करते हैं। जब जन-समूह भ्रष्ट शासकों से विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो साम्राज्यवादी 'स्वतंत्रता व प्रजातंत्र' के बहाने से मुक्ति-आंदोलनों को बल-प्रयोग से दबाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। अफ्रीका और लातीनी अमरीका के राज्य इस तरह के हस्तक्षेप के हमेशा शिकार रहे हैं। तथ्यों से पूरी तरह प्रकट है कि साम्राज्यवाद ने अपने लुटेरेपन के सारतत्त्व को अभी नहीं छोड़ा है। विकासशील देशों के विरुद्ध प्रत्यक्ष राजनैतिक-आर्थिक व सैनिक दबाव के प्रयोग को छोड़ें बिना आधुनिक उपनिवेशवादी विचारधारात्मक भीतरपात के तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। इन विशेष विचारधारात्मक धारणाओं में से एक 'वर्ग-जाति' और 'भाषीदारी' की धारणा प्रमुख है। आधुनिक पूँजीवादी अर्थशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्ग-सहयोग विकासशील देशों में आर्थिक-विकास को तीव्र करेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिकन प्रो० जान पी० पावेलसन के अनुसार विकासशील देशों के अभी तक पिछड़े बने रहने का मुख्य कारण उत्पादन में शामिल लोगों के बीच परस्पर विश्वास की कमी है। पावेलसन बल देकर कहते हैं—“अल्प विकसित देशों का ऐसे स्पष्ट रूप से परिभाषित समूहों में विभाजन, (जैसे, सेना राजनीतिज्ञ, जमींदार, व्यापारी, मजदूर, किसान, जनजाति, छात्र आदि) जो न केवल एक-दूसरे से संपर्क ही नहीं रखते हैं बल्कि सक्रिय रूप से एक-दूसरे के प्रति नापसंदगी व अविश्वास के भाव रखते हैं”

कोशिश करते हैं, उत्पादन के उपकरणों के तकमंगन विभाजन को रोकना है।¹

विकासशील देशों की सामाजिक-संरचना के पावेस्मान के विभाजन को हमें उसकी बुद्धि के लिए छोड़ देना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वर्ग-विरोधों के स्रोतों का उत्पादन नहीं करता है बल्कि विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति की अनिवार्य शर्तों के रूप में वर्ग-सहयोग की अपील करता है। राष्ट्रीय एकता और राजनैतिक स्थिरता निश्चय ही सामाजिक-आर्थिक विकास की सफलता के लिए सब कही महत्वपूर्ण शर्तें हैं लेकिन नव-उपनिवेशवाद के समर्थक विकासशील व साम्राज्यवादी देशों के बीच मौजूद अंतर्विरोधों को छुटाने की कोशिश करते हैं जबकि साम्राज्यवाद विकासशील देशों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें विकास का धीरे-धीरेवादी रास्ता ग्रहण करने से रोकने में लगा हुआ है।

पूँजीवादी अर्थशास्त्री भागीदारी के सिद्धान्त पर भी बहुत बल देते हैं यद्यपि इसके सारतत्व और, यथादा महत्वपूर्ण यह है कि, इसके तरीकों में हाल में महत्वपूर्ण बदलाव आये हैं। उपनिवेशी व्यवस्था के पतन के बाद के आरंभिक वर्षों में पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों ने यह दावा किया कि विकासशील देश अपने पूर्ववर्ती स्वामी राज्यों के साथ भागीदार बन गये हैं क्योंकि उन्होंने उनके (साम्राज्यवादी देशों के) साथ अपने परंपरागत संबंधों को बनाये रखा है। ब्रिटिश राष्ट्र-कुल संघ, फ्रांसीसी-अफ्रीकन समुदाय तथा अन्य राजनैतिक संगठन, जिनमें सदस्यों की स्थिति असमान स्तर की है, विधिवत बनाये गये और उनका विस्तार किया गया। अमरीका ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अपनी ऐतिहासिक नियति के कारण वह विकासशील देशों का भागीदार है क्योंकि वह भी पहले यूरोपीय उपनिवेश था। चूंकि यह भागीदारी व्यवहार में साम्राज्यवादी शक्तियों पर विकासशील देशों की निर्भरता को बनाये रखने में ही सहायक थी, अतः इसका आकर्षण तेजी से कम हो गया। इसी कारण नव-उपनिवेशवाद के समर्थकों को भागीदारी के सिद्धान्त का आधुनिकीकरण और इसके तरीकों का नवीकरण करना पड़ा।

औद्योगीकरण, कृषि-मुधार, सार्वजनिक-क्षेत्र का निर्माण, आर्थिक नियोजन और श्रम के पुराने अंतर्राष्ट्रीय विभाजन का विनाश—ये सब विकासशील देशों में विश्व-समाजवादी व्यवस्था के अनुभवों से जुड़े हुए हैं, साम्राज्यवादी शक्तियों उनके मूल विरोध का खतरा उठाना प्रायः नापसंद करती हैं। विकासशील देशों में आर्थिक कार्यों के लिए तत्त्वात्मक सहायता देने के झंडे को पहनाते हुए साम्राज्यवादी शक्तियाँ उन्हें पूँजीवादी विकास के उस रास्ते पर धकेल रही हैं जिसमें उनकी अर्थ-

1. जॉन • पी • पावेस्मान, 'आर्थिक विकास की अवस्थाएँ : विकासशील देशों में तत्कालीन प्रवृत्त-व्यवस्था का निर्माण', प्रिन्टन, एन • जे •, 1972, पृ • 33 (नवीं सं.) ।

व्यवस्थाएँ विषय पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से एकीकृत हो जाएँगी। इससे विकासशील देश साम्राज्यवादी देशों पर आर्थिक दृष्टि से और अधिक निर्भर हो जायेंगे।

3. विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट लक्षण

यह तथ्य, कि एशिया, अफ्रीका व लतीनी अमरीका के बहुसंख्यक देशों में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नर सी है, अभी इसका सूचक नहीं है कि विकसित साम्राज्यवादी देशों पर उनकी आर्थिक निर्भरता के संकेतों का मत हो गया है। उपनिवेशवाद की राजनैतिक प्रभुता के विपटन ने भूतपूर्व उपनिवेशी व अर्ध-उप-निवेशी देशों में भिन्न शोषण के स्तर-आर्थिक रूपों को नष्ट करने में सहायता दी। राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद यदि आर्थिक मुक्ति नहीं आती है या उपनिवेशी आर्थिक ढांचा सुरक्षित छोड़ दिया जाता है तो राजनैतिक स्वतंत्रता अधूरी होती है और काल्पनिक हो जाने की हद तक अपना अर्थ खो देती है।

राजनैतिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है हालाँकि यह साम्राज्यवाद की बेड़ियों से भूतपूर्व उपनिवेशी व अर्ध-उपनिवेशी देशों की मुक्ति की ओर पहला कदम ही है। इसका महत्व यह है कि वे विदेशी आधिपत्य से पूर्ण मुक्ति के लिए सघर्ष कर सकते हैं। वर्तमान में उनके राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के मुख्य मुद्दे आर्थिक स्वतंत्रता, विदेशी पूँजी के आधिपत्य व साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उन पर लाये गये लूट-मारपूर्ण संबंधों की व्यवस्था की समाप्ति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना है।

विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ क्या हैं? उनके उत्पादन-संबंध नानाक़ी, अटिन और अंतर्विरोधी हैं। वास्तव में उनमें आर्थिक संबंधों की पूरी श्रृंखला—आदिम आतीय से लेकर आधुनिक पूँजीवादी तक—शामिल है। उनमें बहुत भिन्न प्रकार की आर्थिक संरचनाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के बाद पहले वर्षों में कुछ विकासशील देशों ने विशेष रूप से अफ्रीका के देशों ने, अपने मजबूत जनजातीय व सामुदायिक संबंधों को बनाये रखा। इनमें से कुछ देशों में सामुदायिक स्वामित्व व प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था पर आधारित यह व्यवस्था धीरे-धीरे छोटे स्तर के वस्तु-उत्पादन में विकसित हुई जबकि कुछ अन्य देशों में सामंती अथवा अर्ध-सामंती व्यवस्था में विकसित हुई। इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन पर विदेशी व स्थानीय पूँजी का बड़ा भारी प्रभाव था। इन संरचनाओं के अलावा अधिकांश विकासशील देशों में श्रम-जनिक क्षेत्र का भी विशेष स्थान है। विभिन्न अर्थ-संरचनाओं के बीच संबंध, प्रत्येक देश-विशेष में ऐतिहासिक रूप से निश्चित परिस्थितियों, उत्पादक-शक्तियों के विकास, सामंती संबंधों के अवशेष, विदेशी पूँजी के आधिपत्य की सीमा आदि पर निर्भर है।

विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था की विशेषता एक-कर्मजी विकास है। इसमें संपूर्णराष्ट्रीय-उत्पाद और निर्यात में एक या दो उत्पादन-सामग्री की पूरी प्रधानता होती है। उनकी उद्योग-व्यवस्था अल्पविकसित है। 1980 के आरंभ में उनकी आबादी पूंजीवादी विश्व की आबादी के आधे भाग से ज्यादा थी लेकिन उनका औद्योगिक उत्पादन संपूर्ण पूंजीवादी उत्पादन के दमर्ज भाग से भी कम था। विकासशील देशों में भारी उद्योगों में प्रतिव्यक्ति उत्पादन विकसित पूंजीवादी देशों के उत्पादन का तीसरा भाग है। विकासशील देशों की एक विशेषता मूलतः ग्रामीण कृषि-व्यवस्था है जिसमें आदिम औजारों का प्रयोग होता है। इन देशों में लाभ-प्रद रूप से काम करने वालों का 50 से 90 प्रतिशत भाग कृषि के नाम में लगा हुआ है।

आर्थिक-विकास का निम्न स्तर और बहुसंरचनात्मक अर्थव्यवस्था अटिल सामाजिक बनावटों को निश्चित करती है। इन देशों में ऐसे वर्ग और सामाजिक-संस्तर अब भी बचे हैं जो विकसित पूंजीवादी देशों में काफ़ी पहले समाप्त हो गये थे। इन देशों के पूंजीपति व सर्वहारा पश्चिमी यूरोप एवं अमरीका के पूंजीपति व सर्वहारा से कुछ भिन्न हैं।

एक-कर्मजी अर्थव्यवस्था, अल्प आर्थिक-विकास, आदिम कृषि, अत्यंत कम क्षम-उत्पादकता और स्थानीय सुयोग्य कर्मियों की कमी का परिणाम प्रति-व्यक्ति अल्प-आय हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सभ के आँकड़ों के अनुसार 1980 के दशक के आरंभ में विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति आय औद्योगिक रूप से विकसित पूंजीवादी राज्यों से 14 गुना कम थी, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 6000-7000 डॉलर है, पेट्रोलियम निर्यात नहीं करने वाले विकासशील देशों में यह 350-450 डॉलर है और 29 सबसे कम विकसित देशों में सिर्फ 150 डॉलर है।¹ परिणामस्वरूप विकासशील देशों में जीवन-स्तर अत्यंत नीचे है। जनसंख्या पोषाहार की व्यवस्थित कमी से पीड़ित है। इन देशों में बहुत कम स्कूल व अस्पताल हैं और डॉक्टर व शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। निरक्षरता की दर भी इन देशों में बहुत ऊँची है।

परम्परागत आर्थिक पिछड़ेपन तथा मेहनतकशों की गरीबी व भूख को समाप्त करने के लिए विकासशील देशों को बहुत व्यापक सामाजिक आर्थिक सुधार करने होंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें विदेशी पूंजी की सर्वोच्चता की समाप्ति, अपने देशों का औद्योगिकीकरण, मूलभूत भूमि-सुधारों पर अमल, अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र को मजबूत करना तथा समाजवादी देशों से परस्पर-सामंजसक

1. 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के आँकड़ों की पुस्तिका', परिशिष्ट 1919, पृ० 211
 आबाली में।

मंदगो का विस्तार करना होगा। इन प्रमुख ऊँदों को उठाना इस पर निर्भर है कि विकासशील देश कौन-सा रास्ता ग्रहण करते हैं।

नव-स्वतंत्र देशों के लिए विकास के दो रास्ते—राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की वर्तमान अवस्था में विकसित देश विकास के दो रास्तों—पूंजीवादी और गैर-पूंजीवादी—में से कोई एक चुन सकते हैं। कुछ विकासशील देशों में वर्ग-शक्तियों के सह-संबंध और स्थापित आर्थिक-सामाजिक संरचना के कारण पूंजीवादी विकल्प निरिच्छ हो गया है। वहाँ राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को अवरुद्ध करने और पूंजीवादी विचार के माध्यम से आर्थिक प्रगति को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका अनिवार्य परिणाम पूंजीवाद में अंतर्निहित सामाजिक अंतर्विरोधों में वृद्धि, जैसे अव्यवस्थित आर्थिक विकास, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के हाथों में संपदा का अधिक-से-अधिक केंद्रीकरण और शोषण-वर्ग व मेहनतकशों के जीवन-स्तरों के बीच बढ़ता हुआ होता है।

इतिहास बताता है कि जिन देशों ने पूंजीवादी रास्ता पसंद किया, वे अपने सामने प्रस्तुत एक समस्या का समाधान करने में भी असफल रहे। वे धर्म के अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी विभाजन के अंतर्गत साम्राज्यवादी देशों को कच्चा-माल व कृषि-जन्य पदार्थों के असमान व अधीनस्थ आपूर्ति करने वाले बने रहते हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत विकासशील देश शोषण की समाप्ति, आर्थिक-स्वतंत्रता की प्राप्ति व अन्य कार्य नहीं कर सकते।

राजनैतिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है किंतु राष्ट्रीय मुक्ति का विचार में सिर्फ आर्थिक कदम है। राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद अनेक अनिवार्य जनवादी सुधार आवश्यक हैं, जैसे—उपनिवेशी आर्थिक ढाँचे का विनाश; विदेशी इजारेदार पूंजी के आधिपत्य का अंत; साम्राज्यवादी राजनैतिक नियंत्रण के विविध छुपे रूपों की समाप्ति; स्थानीय शोषक वर्ग व सामाजिक सत्तरों, जो अब भी साम्राज्यवादी प्रभुत्व के लिए सामाजिक आधार-भूमि बनाते हैं (जैसे सामंती जमींदार, साम्राज्यवादपरस्त नौकरशाही नेतृत्व आदि), की आर्थिक स्थितियों का नाश; सामाजिक व राजनैतिक जीवन का जनवादीकरण और राज्य-शक्ति के निकायों पर मेहनतकशों के नियंत्रण की स्थापना। इन कार्यों के आधार पर ही सीधे आर्थिक विराम और प्रगतिशील आर्थिक उपायों (जिनका वर्णन मैं आगे करूँगा) की प्राप्ति संभव है।

सुसंगत रूप से विकसित होतो राष्ट्रीय मुक्ति का विचार ही परिणाम होता है—गैर-पूंजीवादी रास्ते पर प्रगति। यह प्रगति आवश्यक भौतिक व तकनीकी आधारों के निर्माण तथा समाज की वर्गीय व सामाजिक पुनर्संरचना के बाद समाजवाद की ओर परवर्ती-संकल्प के लिए परिस्थितियों की रचना करती है।

जब साम्राज्यवाद का सारे विश्व पर पूरी तरह आधिपत्य था, तब एशिया,

अफ्रीका व सातवीं अमरीका के उपनिवेशी एवं अर्ध-उपनिवेशी देशों में पूँजीवादी-विकास असंभव था। कम में महान् समाजवादी अकनूबर-क्रान्ति की विजय, विश्व समाजवादी व्यवस्था के उदय और आधुनिक विश्व में इसकी बढ़ती भूमिका ने विकसित देशों के लिए विकास के पूँजीवादी रास्ते के द्वार पूरी तरह खोल दिये हैं।

वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक मार्क्स और एंगेल्स ने यह मित्र किया था कि मानवता विकास की निश्चित अवस्थाओं से, जिनको उन्होंने सामाजिक-आर्थिक संरचना कहा, गुजरती है। मार्क्स और एंगेल्स ने जो कुछ प्रतिपादित किया, नयी ऐतिहासिक स्थितियों के अनुसार उसका विकास करते हुए लेनिन ने साम्राज्यवाद के युग में समाजवादी क्रांति के सिद्धांत को, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में समाजवाद की विजय का व्यावहारिक कार्यक्रम भी शामिल है, प्रस्तुत किया। समाजवादी अकनूबर-क्रान्ति तथा अपने उपनिवेश व साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के प्रभाव से पूरब के जनगणों की चेतना में जो उभार आया उसने आर्थिक रूप से पिछड़े देशों, जिनमें पूँजीवाद का विकास नहीं हुआ था और परिपक्व सर्वहारा वर्ग का अभाव था, में सामाजिक मुक्ति के विशिष्ट रास्तों के निर्धारण की आवश्यकता उत्पन्न की। दूसरे शब्दों में यह सवाल उठा कि ये राष्ट्र पूँजीवाद को छोड़ते हुए समाजवाद की ओर बढ़ सकते हैं या नहीं।

लेनिन इस सवाल का जवाब देने वाले पहले मार्क्सवादी थे। उन्होंने कहा—
“क्या हमें इस दावे को सही मानना चाहिए कि पिछड़े देशों (जो अब मुक्ति की राह पर हैं तथा जिनमें युद्ध के बाद प्रगति की ओर कुछ बढ़ाव दिखाई देता है) के लिए आर्थिक विकास की पूँजीवादी अवस्था को पाना अनिवार्य है? हमने इसका उत्तर ‘नहीं’ में दिया।

“...विकसित देशों के सर्वहारा की सहायता से पिछड़े देश पूँजीवादी अवस्था से गुजरे बिना ही सोवियत-व्यवस्था तक और विकास की कुछ विशेष अवस्थाओं को पार करके साम्यवाद तक पहुँच सकते हैं।”

लेनिन के इस प्रमाणीकरण ने कि विकास की पूँजीवादी अवस्था समभव है, आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के जनगणों के सामने, पूँजीवाद का अनुभव किये बिना ही एक नयी शोषण-मुक्ति समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने का परिश्रेय खोल दिया। उन्होंने इन दावों की समर्थि दिखाई कि जिन देशों ने पूँजीवाद द्वारा प्रदत्त पर्याप्त भौतिक-उत्पादन व समाजवाद के लिए आवश्यक अन्य स्थितियों को पाये बिना ही उपनिवेशवाद का जुआ दूर कर दिया है, उन्हें पूँजीवाद की अवस्था ॥

निर्वायें रूप से गुजरना पड़ेगा।

विकास के गैर-मूजीवादी रास्ते का लेनिन का सिद्धांत, रूस के भूतपूर्व पिछड़े नगणों के अनुभव पर आधारित था। बुधारा, अजरबैजान और आर्मेनिया के तन्त्रियत गणराज्यों की स्थापना व दुर्बोकरण की ओर सकेत करते हुए लेनिन ने ताया—“ये गणराज्य इस तथ्य को प्रमाणित व उसकी पुष्टि करते हैं कि सोवियत सरकार के विचार तथा सिद्धांत औद्योगिक रूप से विकसित देशों में ही नहीं, उन शो में ही नहीं जहाँ सर्वहारा-वर्ग जैसा सामाजिक आधार मौजूद है, बल्कि उन शो में भी समझे जाते हैं और तत्काल व्यवहार्य हैं जिनका आधार किसान वर्ग है।”¹ विभिन्न परिस्थितियों के होने पर एक समय पिछड़े जनगणों द्वारा गैर-मूजीवादी रास्ते पर विकास करने की संभावना मंगोलियाई लोक गणराज्य के अनुभव से भी प्रमाणित होती है, जिसने सोवियत-संघ की सहायता से पूँजीवाद को झेड़कर समाजवाद का सफलतापूर्वक निर्माण किया है।

पिछड़े देशों में विकास के गैर-मूजीवादी रास्ते के संबंध में लेनिन ने जो कुछ कहा था, जिन देशों में स्थानीय पूँजीवाद अभी बहुत्वपूर्ण शक्ति नहीं बना है, उन देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की वर्तमान अवस्था में वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन देशों में समाजवाद के निर्माण के लिए भौतिक, तकनीकी, सामाजिक आधारों का अभी भी अभाव है। इन देशों में प्रगतिशील शक्तियाँ राज्य-सत्ता पर विश्वास करते हुए तथा जनगणों के समर्थन से ऐसे मूलगामी मुद्धार कर रही हैं जो समाजवाद में संक्रमण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे।

जिन देशों ने दूसरे महायुद्ध के बाद स्वयं को साम्राज्यवादी गुलामी से मुक्त किया, अनुकूल बाहरी व भीतरी कारकों का सम्मिलन उन देशों में विकास की गैर-मूजीवादी रास्ते की संभावनाओं को अधिक वास्तविक बनाता है। विश्व-समाजवादी व्यवस्था का निर्माण तथा इसकी शक्ति व प्रभाव में वृद्धि, साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का पतन, समय रूप से साम्राज्यवाद का अधिक नियंत्रण हो जाना और भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच सह-अस्तित्व की नीति की सफलता बाहरी कारकों में हैं। समाजवादो देशों से सब क्षेत्रों में सहायता विकासशील देशों को पूँजीवादी आर्थिक-व्यवस्था की पकड़ को तोड़ने या कम-से-कम उस पर निर्भरता की गंभीरता से कमजोर करने का अवसर देती है। विकासशील देशों को राष्ट्रीय-वर्गियों के प्रतिष्ठान, शिष्टा को शोस्ताहन और अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समाजवादी देशों से जो सहायता मिलती है, वह साम्राज्यवादियों को इन देशों पर दबाव डालने के साधनों में बर्धन करती

1. वी. आई. लेनिन, *लेनिनजी की आठवीं अखिब कमी कमेरेन*, रिपब्लिक 22-29, 1920 ई॰, लेनिन रचनाएँ, भाग 31, पृ॰ 490 (अंशों में)।

है। राष्ट्रीय-जनवादी राज्य वह साधन है, जिसके माध्यम से मुक्त हुए देश पूँजीवादी रास्ते पर विकास करते हैं। जहाँ तक इसके वर्गीय सारतत्त्व का प्रश्न है, राष्ट्रीय जनवादी राज्य क्रांतिकारी, साम्राज्यवाद-विरोधी, सामंत-विरोधी और पूँजीवाद-विरोधी शक्तियों के सम्मिलन के हितों को अभिव्यक्त करता है। बहुमत की जनवादी तानाशाही या क्रांतिकारी जनपण की तानाशाही है। प्रकार की राजनैतिक-व्यवस्था वाले देशों ने पूँजीवाद को अस्वीकार कर दिया और ऐसा रास्ता स्वीकार किया है जिसका परिप्रेक्ष्य समाजवादी समाज है।

मये देशों के वीर-पूँजीवादी रास्ते पर विकास के लिए वस्तुनिष्ठ संभावना के मौजूद होने का अर्थ यह नहीं है कि ऐसा अपने आप हो जायेगा। चूंकि इन देशों में मजदूर-वर्ग अभी बहुत कमजोर है और काफ़ी प्रभावशाली नहीं है। अभावामी विकास बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि कौन-सी सामाजिक-शक्तियाँ-साम्राज्यवाद-गमपेक या क्रांतिकारी जनवादी, देश का नेतृत्व करती हैं तथा कि पर—साम्राज्यवादी शक्तियों पर या विश्व समाजवादी व्यवस्था पर, ये शक्तियाँ विजय करती हैं। वीर-पूँजीवादी विकास के लिए आवश्यक ज़रत यह है कि साम्राज्यवादी प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ सपुन हो जाएँ और जनपण आंतरिक प्रतिक्रियात्मक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिक्रियात्मक मोर्चा बनाएँ तथा उन्हें मजबूत करें। राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन की साम्राज्यवाद-विरोधी दिशा और व्यापक रूप से वीर सामाजिक-आर्थिक विच्छेदन को समाप्त करने की इच्छा ही अनेक सामाजिक शक्तियों के समुक्त-राष्ट्रीय मोर्चा के निर्माण के लिए वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों की रचना करती है।

हमें उन विकासशील देशों, जिनमें वीर-पूँजीवादी विकास का मार्ग चुन लिया है, में दिये गये मुख्य आर्थिक-मुद्दारों की परीक्षा करनी चाहिए।

विदेशी इमारतारियों के आधिपत्य की समाप्ति—विदेशी इमारतारियों के आधिपत्य को समाप्त करने वाले राजनैतिक-आर्थिक उपायों की एक व्यवस्था का विशालपन तथा विनाश वीर-पूँजीवादी विकास के लिए मजबूती की एक प्रमुख आवश्यकता है। यह व्यवस्था सामाजिक-आर्थिक मुद्दारों की मुख्य दिशा है क्योंकि यह साम्राज्यवादी-शक्तियों में आर्थिक-व्यवस्था वाले के तर्ज, सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों की हदबंदी और विदेशी-निर्भरता के साथ बहुत निकटता के साथ जुड़ी है।

विकासशील देशों में मज-उत्पत्ति-व्यवस्था के अर्थिक मज अभी भी मजबूत है इसलिए विदेशी इमारतारियों के आधिपत्य के अंत की इच्छा होती है। विदेशी इमारतारियों विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख क्षेत्रों में बहुत मजबूती हुई है और उनके मजबूत मजबूत व्यवस्थाओं का संयुक्त करने हुए जारी मुद्दारे बरत रही है। वे विकासशील देशों को उनके मजबूत विकास के लिए आवश्यक

पूँजी से वंचित कर रही हैं क्योंकि वह आवश्यक पूँजी मुनाफों के रूप में बाहर भेज दी जाती है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगमों के क्रियाकलाप अपने प्राकृतिक व अन्य ससाधनों पर नये देशों की सर्वोच्चता को छति पहुँचाते हैं और उनके पिछड़ेपन को स्थायी बनाते हैं।

विकासशील देशों में विदेशी इजारेदारियों की सर्वोच्चता की समाप्ति का कार्य प्रायः इनके उद्यमों के राष्ट्रीयकरण से शुरू होता है। अल्जीरिया, सीरिया, गिनी, पेरू और अन्य देशों ने राष्ट्रीयकरण के अभियान शुरू किये हैं। उदाहरण के लिए अकेले लातीनी अमरीका में 1970-76 के बीच 163 उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया गया।¹ वेनेजुएला, पेरू, इक्वेडोर, गुयाना और जमेका ने मोटे तौर से अपने खनन व तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। बेनिन के लोकगणराज्य ने विदेशियों को मिली तेल-रियायतों, कपास का उत्पादन व विक्रय, औषधि-उद्योग, विद्युत-ऊर्जा उत्पादन आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। विदेशी इजारेदारियों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण खेती और क्षतिपूर्ति के द्वारा किया गया है। अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष क्षेत्रों में विदेशी पूँजी के निवेश पर रोक लगा कर और उन्हें पूरी तरह से राजकीय उद्यमों का क्षेत्र घोषित करके भी विदेशी इजारेदारियों की गतिविधियों को सीमित किया गया है।

कुछ विवासशील देश विदेशी पूँजी की गतिविधियों को सीमित व नियंत्रित करने के लिए संयुक्त-उद्यमों की स्थापना की नीति पर व्यापक रूप से अमल करते हैं। वे आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूँजी, तकनीकी-प्रवीणता और तकनीकी-कर्मियों का उपयोग करते हैं।

कुछ देशों ने, जिन्होंने गैर-पूँजीवादी विकास का मार्ग चुना है, विदेशी कंपनियों द्वारा मुनाफ़ा बाहर ले जाने पर रोक लगायी है और इसके साथ इन कंपनियों को उच्चतर कर भी देना पड़ता है।

जिन देशों ने आर्थिक-विकास के पूँजीवादी रास्ते को अस्वीकार कर दिया है, उनमें निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण प्रायः बड़ी व्यापक है। उदाहरण के लिए सीरिया ने अपने बड़े व मध्यम उद्यमों का बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीयकरण कर दिया है और कांगो के लोकगणराज्य ने बेचिय-व्यवस्था व बीमा-कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया है। लबानिया में राष्ट्रीयकरण समाजवादी दिशा की और सरकार को प्रोत्साहित करनेवाला मुख्य उपकरण है। यमन के लोकजनवादी गणराज्य, अंगोला, मोझाम्बिक, अफ़ग़ानिस्तान, इथोपिया, मेडागास्कर (मसगासी) तथा अन्य देशों ने निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण करके मूलमामी उपायों का क्रियान्वयन किया है। अपने पहले दशक के अन्त में 1979 में

1. 'विकास-विवाद में बहुराष्ट्रीय निगम', न्यूयॉर्क, 20 मार्च, 1972, पृ. 233।

अंगोला की मंत्रिपरिषद ने सौ में अधिक उन निजी उद्योगों व व्यापारिक उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है जिनके स्वामी देश छोड़कर चले गये थे।

राष्ट्रीयकरण आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने वाला कारक है। अल्जीरिया का सकल घरेलू उत्पादन 1973 के 3000 करोड़ दीनार से बढ़कर 1977 में 7000 करोड़ दीनार हो गया। 1978-79 के वित्तीय वर्ष के लिए इथोपिया का औद्योगिक उत्पादन 35.5 प्रतिशत बढ़ा। अदिम अवाबा के धर्म-शोधन उद्योग में राष्ट्रीयकरण के बाद पाँच वर्षों में उत्पादन लगभग दुगुना हो गया है।

सरकारी क्षेत्र की स्थापना और उसका स्वतंत्र बृद्धिकरण—इजारेदारी आधिपत्य के विरुद्ध विनाशशील देशों के संघर्ष और उनके स्वतंत्र आर्थिक-विकास के लिए सरकारी क्षेत्र अधिक-से-अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इसका निर्माण विदेशी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण व सरकारी उद्यमों की स्थापना, दोनों ही तरीकों से होता है। अल्जीरिया के 90 प्रतिशत औद्योगिक उत्पाद सरकारी-क्षेत्र में बनाये जाते हैं। उवाहुरण के लिए, राज्य संपूर्ण खनन-उद्योग और ऊर्जा व कृषि के सारे उत्पादन का नियंत्रण करता है। 1978 में 100 से अधिक संयंत्र व कारखाने सरकारी क्षेत्र में थे। सीरिया का लगभग 75 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन और कुल मिला कर इसकी राष्ट्रीय आय का 46 प्रतिशत राजकीय क्षेत्र से जुड़ा है। गिनी, तंजानिया, यमन के लोक-जनवादी गणराज्य और अन्य देशों में बहुत से विदेशी उद्यम, बैंक तथा व्यापारिक कंपनियाँ राजकीय संपत्ति बना दी गयी हैं।

सरकारी क्षेत्र के क्रियाकलाप आर्थिक-प्रक्रिया का नियंत्रण, सत्ताधर्मीय संकेंद्रीकरण, अति महत्वपूर्ण उद्योगों का निर्माण और राजकीय कोष में वृद्धि को संभव बनाते हैं। इस सबसे विदेशी पूँजी पर निर्भरता को कमजोर करने में सहायता मिलती है। उन सब देशों में, जिन्होंने विकास के रैर-पूँजीवादी रास्ते को चुना है, सरकारी क्षेत्र जनगण के हित में आर्थिक-विकास को प्रोत्साहित करता है। ये देश जैसे-जैसे इस दिशा में आगे बढ़ते हैं अर्थात् जब मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश जनगण समाज की नेतृत्वकारी शक्ति बन जाते हैं तब सरकारी क्षेत्र समाजवादी स्वामित्व का आधार बन सकता है। इससे ज्ञात होता है कि साम्राज्यवादी विकासशील देश सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध क्यों हैं?

आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए सरकारी क्षेत्र की प्रकृति व सामाजिक कार्य आवश्यक रूप से भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। जहाँ राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग सत्ता में है, वहाँ राजकीय क्षेत्र अनिवार्यतः राजकीय पूँजीवाद होता है। लेकिन ऐसा होने पर भी, विकासशील देशों में भी राजकीय पूँजीवाद राज्य-इजारेदार पूँजीवाद विन्मुक्त नहीं है। विकासशील देशों में नये राज्यों की स्थापना में यह एक प्रवर्तिनीय प्रक्रिया है। इसका जन्म साम्राज्यवाद का विरोध करने का उनकी जड़त से होना है और आर्थिक-विकास के लिए

उनके सपर्प मे यह एक साधन है। सरकारी क्षेत्र के मजबूत होने से केवल उत्पादन सामर्थ्य ही नहीं बढ़ती है, बल्कि सारी सामाजिक-प्रक्रिया का क्रान्तिकरण होता है और यह ग्रँर-पूँजीवादी विकास के लिए आर्थिक आधार-शिला बनता है।

विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण—औद्योगिकीकरण उपनिवेशी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण, आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन पर विजय पाने के लिए एक कारक है।

साम्राज्यवादी इजारेदारियों विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण को रोकने के लिए बड़े सब कुछ कर रही हैं जो वे कर सकती हैं। वे इन देशों को औद्योगिक क्रांति से विकसित पूँजीवादी विश्व के लिए लकड़ी चीरने वालों व पानी खींचने वालों के रूप में बनाये रखने की कोशिश कर रही हैं। पूँजीवादी अर्थशास्त्री, इसके अनुसार विकासशील देशों की सरकार व जनगण को यह समझाने की आशा कर रहे हैं कि उन्हें खनन-उद्योग व उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को बरीक ध्यान देते हुए कुछ विशेष उद्योगों का ही विकास करना चाहिए।

साम्राज्यवाद व आंतरिक प्रतिक्रिया के विरुद्ध सपर्प का तर्क विकासशील देशों के जनवादी क्रान्तिकारी नेताओं को अधिक-से-अधिक व लगातार औद्योगिकीकरण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। औद्योगिकीकरण के बिना पिछड़े हुए क्षेत्रीय आर्थिक-संरचना तथा विदेशी आधिपत्य को समाप्त करना असंभव है और उत्पादन के समस्त क्षेत्रों में उच्च विकास-दर को पाना तथा गरीबी व गान्धेय जनसंख्या के आधिक्य से सफलतापूर्वक सपर्प करना भी असंभव है। औद्योगिकीकरण से महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन होते हैं और उनसे मजदूर-वर्ग की गुणात्मक व सख्यात्मक वृद्धि होती है।

आज को दुनिया में विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण का अर्थ है—अत्यधिक प्रभावी व प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र तथा उत्पादन-पद्धतियों पर आधारित राष्ट्रीय, भौतिक एवं तकनीकी आधारों का निर्माण, तकनीकी व आर्थिक स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों का प्रयोग, आर्थिक पिछड़ेपन पर विजय और पुरानी उपनिवेशी-व्यवस्था की पुनर्संरचना। ये सब उपाय एक साथ मिलकर विकासशील देशों में विदेशी इजारेदारों के आधिपत्य तथा उत्पादन के सामंती रूपों को ज़रूरत में सीमित और पूरी तरह समाप्त करना संभव बनाते हैं। औद्योगिकीकरण आर्थिक-स्वतंत्रता पाने और सामाजिक-संरचना में सुधार करने का रास्ता है।

विकासशील देशों ने कुछ हद तक 'राष्ट्रीय-उद्योगों' की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली है। 1971 की तुलना में 1979 में उनका कुल उत्पादन 5.6 गुना अधिक था जबकि विकसित पूँजीवादी देशों में यह 3.6 गुना अधिक था। उच्चतम विकास-दर ऊर्जा, धातु, रसायन और मशीन-निर्माण उद्योगों में थी।

बहुत भिन्न-भिन्न आर्थिक परिस्थितियाँ होने के कारण विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण एक समान नहीं हो सकता। किसी एक देश में अर्थव्यवस्था के किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रगति आर्थिक विकास के स्तर तथा प्राप्य प्राकृतिक-संसाधनों पर निर्भर है। लेकिन सभी विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण के लिए आधुनिक मशीनों पर आधारित विज्ञान कारखानों, सयंत्रों आदि के निर्माण की जरूरत होती है।

औद्योगिकीकरण उत्पादक-शक्तियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। किन्तु सिकंदर औद्योगिकीकरण विकासशील देशों के हितों की जरूरी रूप में पूर्ति नहीं करता है। उनके हितों की पूर्ति ऐसा औद्योगिकीकरण करना है जो सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाता है व निजी पूँजी को सीमित करता है, जो विदेशी इजारेदारियों की स्थिति को कमजोर करता है व राष्ट्रीय उद्योग को मजबूत बनाता है, जो उच्चतर जीवन-स्तरों को और अंत में ग्रैंड-पूँजीवादी रास्ते पर विकास को प्रोत्साहित करता है। समाजवादी दिशा की ओर उन्मुख देशों की अर्थव्यवस्थाएँ ठीक इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं।

विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका संचित-कोष सीमित होता है और उत्पादन के अधिकतर साधनों पर विदेशी इजारेदारियों का स्वामित्व होता है। इससे इजारेदारियों को मुनाफ़ा बाहर भेजने के माध्यम से विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में एक बड़े हिस्से का दोहन करने का अवसर मिल जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के केन्द्र की गणनाओं के अनुसार यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो ये इजारेदार 1980 के दशक के अंत तक विकासशील व पूँजीवादी दोनों तरह के देशों में उत्पादन के 40 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण करने लगेंगे।

विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण में इस तथ्य से भी बाधा आती है कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्व-पूँजीवादी संरचनाएँ अभी भी मौजूद हैं। इसी तरह बमीदारों, उनके नौकर-चाकर तथा जनसंख्या के अन्य मेहनत नहीं करने वाले हिस्सों द्वारा परजीवी उपभोग से राष्ट्रीय राजस्व में कमी आने से भी औद्योगिकीकरण में बाधा आती है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण संकुचित घरेलू बाजार, अल्प प्रभावी भाग और सांस्कृतिक विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण के निम्न स्तर से भी औद्योगिकीकरण अवग्रह होता है।

विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण की मुख्य समस्या वित्त-प्रवाह के लिए स्रोत तलाश करना है। विदेशी निवेश, यदि वे सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर किए जाने हैं और उनके साथ अन्य शर्तें नहीं जुड़ी होती हैं तो, एक तरीका है। लेकिन विकासशील देशों में उद्योग-निर्माण की वित्त-व्यवस्था के प्रमुख स्रोत घरेलू संसाधन हैं। इनमें विदेशी पूँजी व विदेशी व्यापारिक इजारेदारियों का राष्ट्रीय-

करण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, विश्व बाजार में उचित कीमत अथवा तकनीकी उपकरणों के बदले में अपने उत्पादों की विप्री, बजट-राशियों के उपयोग पर बढोर नियंत्रण स्थापित करके संसाधनों का संरक्षण और प्रगतिशील बराधान के द्वारा एकत्रित संपत्तिशाली वर्गों की आय का एक भाग—शामिल है।

समाजवादी देशों से सभी प्रकार का सहयोग, जिसमें मशीन व उपकरणों का आयात और विशाल उद्यमों के निर्माण व राष्ट्रीय बर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल शर्तों पर सहायता शामिल है, विकासशील देशों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से आर्थिक-सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

कृषि-सुधार—भूमि-सुधार विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का एक मुख्य साधन है और इसके बिना पिछड़ेपन को दूर करना असंभव है। प्रबंध के पूर्व पूँजीवादी रूप और इसके साथ भूमिहीन व भूमि प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले लाखों-करोड़ों किसान, छाछ समस्या, बरेलू बाजार के अभी तक संकीर्ण रहने और औद्योगिक विकास के समग्र-स्तर के अभी तक नीचे बने रहने मुख्य कारण है। कृषि व उद्योग के समग्र स्तर को ऊपर उठाने तथा किसानों के जीवन-स्तर में सुधार करने का उपाय भूमि-स्वामित्व के पुराने रूप व भूमि-प्रबंध के कम उत्पादकता वाले रूपों की समाप्ति, किसानों को सारी भूमि का वितरण, कृषि को तकनीकी ढंग से ळैस करना और सहकारी व राजकीय क्लामों का संगठन है। कृषि संबंधों में परिवर्तन करने में विकासशील देश आर्थिक पिछड़ेपन पर विजय पाने, सचित निधियों के स्रोतों में वृद्धि तथा विस्तार करने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति व आर्थिक-स्वतंत्रता की राह खोलने में समर्थ होंगे।

पिछले दो दशकों में अनेक विकासशील देशों ने भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन किया है। उन देशों में, जिनमें विकास के पूँजीवादी रास्ते को चुना है, ये सुधार आवश्यक रूप से अधूरे व सीमित थे। अधिकांश भूमि अभी भी बड़े जमींदारों के हाथों में केन्द्रित है, जिन्हें किसान सपान देते हैं और अधिकांश किसान अभी भी भूमिहीन व भूमि पाने के इच्छुक हैं। भूमि-सुधार का अर्थ प्रायः सबसे खराब व कृषि के लिए अयोग्य भूमि को ऊँची कीमत पर खरीद कर जमींदारों स्वामित्व को नगण्य रूप में सीमित करना भर रहा है। यह भूमि पूँजीवादी ढंग की कृषि में लगे हुए संपत्तिशाली-वर्ग के हिस्से के द्वारा ही खरीदी जा सकती है जबकि दरिद्रतम किसानों को भूमि की अभी भी बेहद जरूरत है। व्यवहार ने दिखाया है कि कुछ विकासशील देशों में भूमि-सुधार के नाम पर जमींदारों की भूमि को आंशिक रूप में ही जमा किया गया है और किसान उस भूमि के लिए सरकार को ऊँचा क्षति-पूर्ति-शुल्क देते हैं। पूँजीवाद की ओर उन्मुख विकासशील देशों का राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग मेहनतकश किसानों के हित में कृषि समस्या का समाधान करने में असमर्थ है।

लेकिन जिन विकासशील देशों में विकास का गैर-पूँजीवादी रास्ता चुना है,

उनमें स्थिति भिन्न है। उनमें से अनेक सामंजसिकता भूमि-मुधारों में अत्यंत सु-गमन रहे हैं और वे सामंजी भूमि-स्वामित्व को गल्ट कर चुके हैं। कृषि-क्षेत्र में काम करने वाली विदेशी कर्मियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है या उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है और राज्य के आर्थिक व सङ्गठनात्मक दोनों तरह के समर्थन से कृषि सहकारी समितियों को काफी दृढ़ तक विकसित किया गया है। उदाहरण के लिए, अल्जीरिया में 1962 में कृषि-कानून की प्रथम अवस्था में विदेशियों की 20 लाख हेक्टर में अधिक भूमि 2000 राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारी समितियों को दे दी गई। नवम्बर 1971 के आरम्भ में देश ने 'कृषि-कानून पर कानून' बनाया जिसने समस्त बिना जुनी भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया और निजी रूप से रखी जाने वाली भूमि के आकार को सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप किसानों को 15 लाख हेक्टर भूमि मिली जिसने उन्हें कृषि-सहकारी समितियों में सम्मिलित होने में सहायता दी। अस्सी के दशक के आरम्भ में समस्त कृषि-योग्य भूमि के आधे से अधिक भाग को राष्ट्रीय व सहकारी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था। यमन के लोक जनवादी गणराज्य ने मूलवामी भूमि-मुधारों को पूरा कर लिया है। मूलपूर्व अमीर, मुत्तगान तथा उनके मंत्रियों की भूमि व संपत्ति बिना किसी भी तरह के मुआवजे के जब्त कर ली गयी है और कृषि मजदूर, भूमि के भूछे व भूमिहीन किसानों में बांट दी गई है। 1979 के आरम्भ में यमन में 39 उत्पादन-सहकारी समितियाँ थी जिनका समस्त कृषि-योग्य भूमि के 75 प्रतिशत पर नियंत्रण था। इथोपिया में जमीनदारों, माइरी-वर्ग और सम्प्राट व उनके परिवार की सारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अन्य विकासशील देशों ने भी, जिन्होंने विकास के गैर-यूजीवादी रास्ते को चुना है, मूलवामी भूमि-मुधारों को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण उपाम किये हैं।

कृषि-मुधारों का क्षेत्र व गति संबंधित देश की राज्य-व्यक्ति तथा सामाजिक-संरचना पर निर्भर होती है। किसी भी विकासशील देश ने अभी तक अपने भूमि-मुधारों को पूरा नहीं किया है अथवा कृषि-प्रश्न का पूरा समाधान नहीं किया है। फिर भी, जो कदम उठाये गये हैं, उन्होंने निश्चय ही जमींदारी-स्वामित्व को निर्वल किया है तथा मेहनतकश किसानों व कृषि-मजदूरों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया है और कुछ देशों में मजदूर-वर्ग व किसानों के बीच गठबन्धन को मजबूत किया है। राज्य-कार्यों के तन्त्र का निर्माण और सहकारी क्रान्तियों का सङ्गठन वे प्रमुख तरीके हैं, जिन पर चलकर विकासशील देश आर्थिक विकास के गैर-यूजीवादी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं।

सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों का विकासशील देशों के साथ सहयोग—विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ेपन तथा समाजवादी मूल्यों पर

निर्भरता के ऊपर विजय पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने वाले आंतरिक कारकों के साथ बाहरी परिस्थितियाँ—मुख्य रूप से विश्व-समाजवादी व्यवस्था का प्रभाव, दूसरा प्रमुख कारक है। विश्व-समाजवादी व्यवस्था के देश विकास-शील देशों को अधिक-से-अधिक आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। साम्राज्यवाद व अव्यवस्थितवाद के विरुद्ध तथा शांति के लिए संघर्ष में विश्व-समाजवादी व्यवस्था तथा राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन के समान हित इस सहयोग के वस्तुनिष्ठ आधार हैं।

भूतपूर्व उपनिवेशों व पराधीन राष्ट्रों के साथ आर्थिक संबंधों पर साम्राज्यवाद की हजारेदारी नष्ट हो गई है। इससे विकसित देश अपनी आर्थिक-स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गुणात्मक रूप से नये सिद्धांतों की स्थापना में समर्थ हो गये हैं।

पूँजीवादी विचारक समाजवादी देशों के साथ आर्थिक संबंधों के महत्व को और इस सहयोग तथा साम्राज्यवादी देशों, विकासशील देशों के साथ जिनके आर्थिक संबंध उन्हें पूँजीवादी रास्ते पर निर्देशित करने के लिए लक्षित हैं ताकि वे विकासशील देशों का शोषण जारी रख सकें, के अव्यवस्थितवादी कार्यों के बीच के मूलभूत अंतर को मलिन करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

समाजवादी व विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। सोवियत संघ ने उन्हें जो कुल राशि दी है उसका 77 प्रतिशत उद्योग में निवेश किया गया है जबकि पूँजीवादी सहायता का सिर्फ 28 प्रतिशत इस कार्य में प्रयोग किया गया। साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपनी 'सहायता' का उपयोग आर्थिक व राजनैतिक दबाव डालने, अपनी हजारेदारियों के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने और प्रगतिशील शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में मदद करने के लिए करती हैं। विकासशील देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों में पूँजीवादी-शक्तियाँ अव्यवस्थित उद्देश्यों को आगे बढ़ाती हैं जबकि समाजवादी देश बराबरी के सहयोग के सिद्धांत ने निर्देशित होने हैं।

समाजवादी देशों ने विकासशील विश्व को जो ऋण व सहायता प्रदान की है, वे उपनिवेशवाद की विरासत को मिटाने, ऋण पाने वालों की अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना करने और औद्योगिक-समूहों का निर्माण के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी सहायता प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। साम्राज्यवादी शक्तियों की उधारी से अलग, उनके साथ कोई राजनैतिक, सैनिक या आर्थिक शर्तें नहीं होती हैं। वे आर्थिक-स्वतंत्रता के लिए परिस्थितियों का निर्माण करते हुए प्रमुख रूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र को मजबूत करने में सहायता देते हैं। पूँजीवादी उधारों का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध निजी कंपनियों की स्थिति को मजबूत करना है। समाजवादी देश अनुकूल शर्तों पर

उधार देने हैं। सोवियत सघ 2-3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है जिसका पुनर्भुगतान प्रायः 12 वर्ष में करना होता है। पुनर्भुगतान उपकरणों की सुपुर्दगी के पूरा होने के एक वर्ष बाद शुरू होता है। इससे विकासशील देशों को नयी सुविधाओं को चालू करने तथा उनसे आय प्राप्त करने का समय मिल जाता है जिससे वे उधार व ब्याज का पुनर्भुगतान करने में ही समर्थ नहीं हो जाते हैं बल्कि उन्हें नि शुल्क पूंजी भी मिलती है। नियमतः उधार परंपरागत नियमन योग्य सामान अथवा नवनिर्मित उद्योगों के उत्पादों में खुदया जाता है।

समाजवादी देश जो आर्थिक व तकनीकी सहायता देने हैं वह विकसमशील देशों की अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र का निर्माण करने व उसे मजबूत करने, आर्थिक-विकास की दरों को बढ़ाने, साम्राज्यवादी इशारेदारियों के विस्तार के विरुद्ध उनकी रक्षा करने और इसके साथ जीवन-स्तरों को ऊँचा करने तथा उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

समाजवादी देश अब एशिया, अफ्रीका व सातीनी अमेरिका के 60 से अधिक देशों को आर्थिक व तकनीकी सहायता देने हैं और 1500 करोड़ से अधिक की दीर्घकालीन उधार सहायता दे चुके हैं जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक सोवियत सघ ने दिया है। इन समाघनों ने 4400 से अधिक औद्योगिक उद्यमों व मध्य आधि-परियोजनाओं के लिए (जिनमें 200 मशीन-निर्माण व धातु-समाधि करने में संयंत्र, 230 तेल-गोधन व रसायन उद्योग और कृषि-उत्पाद, ग्राह्य व उप-भोजना सामान बनाने वाले 1120 कारखाने शामिल हैं) वित्त-व्यवस्था की है। विकासशील देशों में समाजवादी देशों की सहायता ने जो लोह-धातु संबंध बने हैं या बन रहे हैं, वे तीन करोड़ टन इस्पात का वार्षिक उत्पादन करने हैं। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् के सदस्यों ने जिन ऊर्जा-केन्द्रों को बनाने में सहायता दी है या दे रहे हैं, उनकी स्थापित क्षमता अब 160 लाख किलोवाट से अधिक है। यह क्षमता इनकी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करने में गयवे हैं जो प्रतिवर्ष 250 लाख टन तेल, बाजार में जिसकी कीमत अब 500 करोड़ डॉलर है, की बचत करेगी।

समाजवादी देश जिन उद्यमों के निर्माण में सहायता देने हैं, वे राज्य की पूरी संपत्ति बन जाते हैं। इनमें आर्थिक-नियोजन की पुनर्विभागों का निर्माण होता है।

सोवियत सघ विकासशील देशों के साथ पारस्परिक लाभदायक साधारण पर आधि व तकनीकी सहयोग करता है। विकासशील देशों को नयी आर्थिक-उत्पाद, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है और इससे अधिक रोचक वृद्ध उपकरण जीवन-स्तरों को प्रोत्साहन मिलता है। बरने में सोवियत सघ अपनी वस्तु की वस्तुओं जैसे, कपड़े, कनिष्ठ धातु के साधन, तेल, ईंधन, रेडियो, कपड, प्राकृतिक रबर, पटसन, चावल, चाय, कॉफी, कॉका, तेल,

पत्र आदि प्राप्त करना है।

सैज्ञानिक तकनीकी क्षमियों व अन्य विशेषज्ञों और कुशल श्रमिकों के प्रशिक्षण में समाजवादी देशों की सहायता और इसके साथ तकनीकी-ज्ञान में उनकी साझेदारी भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् के देश लगभग 4 लाख तकनीकी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण में सहायता दे चुके हैं और लगभग 40 हजार युवा-जन समाजवादी देशों में उच्चतर शिक्षा पूरी कर चुके हैं और लगभग इतने ही अध्ययन जारी रहे हुए हैं।

उनिवर्सिटी निर्भरता में मुक्त हुए देशों की समाजवादी देश उनकी व्यापकपूर्ण भाषों के लिए राजनैतिक समर्थन ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के आधारों की रचना व उनकी बजटरी के लिए प्रत्यक्ष सहायता भी दे रहे हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में लियोनिद ब्रेज्नेव ने कहा था—“अब यह बिल्कुल साफ है कि विश्व में वर्ग-शक्तियों के वर्तमान सह-संबंधों के रहने मुक्त हुए देश साम्राज्यवादी देशों के निर्दोशों का विरोध करने और व्यापकपूर्ण अर्थानुसंगी स्तर के आर्थिक-संबंधों को प्राप्त करने में पूरी तरह समर्थ है। यह भी साफ है कि जर्मन और जनपक्ष की रक्षा के सामान्य संबंध में उनके पहले से ही काफी योगदान के और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाने की सम्भावना है।”¹

समाजवादी देश विकासशील देशों की सहायता उनकी रक्षा-सामर्थ्य को बढ़ाकर देने के लिए कर रहे हैं ताकि वे साम्राज्यवादी शक्तियों तथा उनके समर्थकों के आक्रमण और सैनिक दबाव का मुकाबला कर सकें। सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देश किसी प्रकार की विशेष भूमिदा, राजनीतिक प्रभुता या सैनिक झूठे नहीं चाहते हैं। इसका अवाटन्य प्रमाण अंगोला और इथियोपिया की घटनाओं में दिखता है जहाँ सोवियत संघ तथा ब्रूसा की सहायता में आक्रमण-कारियों की हड़तालों को विफल कर उन्हें बापस लाने की विवश कर दिया। यह भी निरानुपूर्विक समझौतों के अंतर्गत सोवियत संघ के बादलों के अनुकूल ही नहीं है अन्तर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के भी अनुकूल है।

अंगोला की लार्सेन्स सरकार के अनुरोध पर ब्रूसा की सेना की उपस्थिति के साथ अंगोला की रक्षा करने में सोवियत सहायता भी एक स्थिरता लाते घातकार था। दोनों सरकारों के ऐसी स्थिति में देश की स्वतंत्रता को बढ़ाकर देने और उसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सहायता दी है अर्थात् दक्षिण अफ्रीका के अपमानवादी अब भी अपनी आक्रमणकारी वादवाहिया जारी रहे हैं।

¹ ए०००-०००० ब्रेज्नेव, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारी की 26वीं कांग्रेस की रिपोर्ट में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम, सोवियत संघ के अर्थ-व्यवस्था के विकास, 1976, पृ० 221 (पेरिस में)।

आकाश में अंगोसा घन बनवायी कर रहे हैं और नार्मीनिया (जिन पर उन्हें ज़री भी अधिकार किया हुआ है और जिनका से भी उपग्रह के लिए अद्भुत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं) में नागरिक कर्मियों पर मोताबारी कर रहे हैं।

दूसरा उदाहरण इथोपिया को समाजवादी देशों की गहारा है। 1973 में और आज, दोनों ही बार इस गहारा ने अजीरा के बीच प्रदेश में राजनीतिक स्थिति को सामान्य बनाने में मदद की और अब भी मदद कर रही है।

अजीरा, एरिया और मालीनी अमरीका में राष्ट्रीय मुक्ति मंचों में बहुत होना जा रहा है और नयी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में 'मोबियस हस्तियों' तथा 'मोबियस गार्ड' की दृष्टि-बधा को स्वयं साम्यवादियों ने नष्ट कर दिया है। इन घटनाओं में प्रगतिशील कल्पना हम बात से पूरी तरह अवगत है कि ये कल्पना-कथाएँ उन लोगों द्वारा मढ़ी जाती हैं जिन्हें अपने विचारों को बढ़ाने के लिए बढ़ाने की जरूरत है ताकि वे जाति, समाजवाद तथा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विरुद्ध संघर्ष करने और जिन देशों ने उपनिवेशी जुआ उगार फेंका है, उन देशों में राष्ट्रों के संघर्ष व मूढमार की नंद-उपनिवेशी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विकासशील देशों का अद्भुत के रूप में इस्तेमाल कर सके।

विकासशील विश्व के सामने प्रस्तुत अत्यंत महत्वपूर्ण मापसों—उपनिवेशी विरामत के अंत, नव-उपनिवेशवाद की श्रेणियों से बाहर निकलने, आर्थिक निष्ठे-पन पर विजय पाने और अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद की समाप्ति के कार्य को बढ़ाने के लिए समाजवादी देश मूलतः नये राजनैतिक तरीकों को प्रतिपादित करने में सक्रिय रहे हैं।

सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों ने राष्ट्रों के आर्थिक अधिकार व कर्तव्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था की स्थापना के घोषणापत्र की प्रगतिशील अंतर्बस्तु तथा साम्राज्यवाद-विरोधी दिशा का समर्थन किया है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रस्तुत केन्द्रीय-समिति की रपट में इस पर बल दिया गया है कि अब से पार्टी विकासशील देशों के साथ सोवियत संघ के सहयोग को विकसित करने और विश्व-समाजवाद व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बीच संबंधों को मजबूत करने की नीति पर दृढ़ता से चलेगी। यह बताया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन दस्तावेजों में निहित सिद्धांतों का समर्थन करने से काफ़ी पहले ही समाजवादी देशों ने उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस बीच साम्राज्यवादी शक्तियों की नीति विश्व-सूत्रीवादी अर्थव्यवस्था में अपने विशेष सुविधा-प्राप्त स्थान को सुरक्षित रखने, विकासशील देशों को इस व्यवस्था के भीतर बनाये रखने तथा उनके और अधिक माना में शोषण की

दशाओं का निर्माण करने की ओर निर्देशित रही है।—

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पुनर्संरचना सबसे पहले हम पर निर्भर है कि विकास-शील देश आर्थिक क्षेत्र में नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध किस प्रकार सुसंगत सघर्ष करते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी-सर्वोच्चता की रक्षा किस सुसंगत रूप से करते हैं और अपनी भूमि में काम करने वाली साम्राज्यवादी इजारेदारियों पर किस सुसंगत तरीके से नियंत्रण करते हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई अस्थिरता और गतिहीनता

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता तथा गतिहीनता पूँजीवाद के आम-संकट का एक विशिष्ट लक्षण है और यह पूँजीवाद द्वारा अपनी शक्तियों के पूर्ण उपयोग में असमर्थता में स्पष्ट होता है। यह साम्राज्यवाद के भीतर की एक आन्तरिक प्रक्रिया है, जिसका सारतत्त्व यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन-संबंध अपने सापेक्ष प्रगतिशील चरित्र को खो चुके हैं और विकास के एक उपकरण की जगह सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध करने वाले प्रमुख कारक के रूप में बस गये हैं। इजारेदारी आधिपत्य पूँजीवाद में अस्थिरता तथा गतिहीनता बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के साथ इजारेदारी के सभी रूप गतिहीनता की प्रवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं।

1. उत्पादन-क्षमताओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग

अपनी उत्पादक-शक्तियों के पूर्ण उपयोग में पूँजीवाद की असमर्थता औद्योगिक उद्यमों में स्थायी अपूर्ण-उपयोग के तथ्य से तीव्रता के साथ स्पष्ट होती है। पूर्व-इजारेदार पूँजीवाद तथा आरंभिक साम्राज्यवाद (प्रथम महायुद्ध से पहले) के समय में औद्योगिक-उद्यमों में व्यापक अपूर्ण-उपयोग केवल आर्थिक संकट के समय ही दिखनायी देता था। पूँजीवाद के आम-संकट के युग में यह पूँजीवाद का स्थिर एवं दीर्घकालिक लक्षण बन गया है और इसे आर्थिक-चक्र की सभी अवस्थाओं में—संकट व मंदी के समय तथा अर्थव्यवस्था की सक्रियता व आगे बढ़ने के समय—देखा जा सकता है।

पूँजीवादी विश्व में उत्पादन-क्षमताओं का स्थायी अपूर्ण उपयोग इस तथ्य में चित्रित होता है कि तकनीकी प्रगति के द्वारा उत्पन्न औद्योगिक-उत्पत्ति के विकास

के माप विदेशी व घरेलू बाजार का परिलम्बन समानांतर रूप में होता है। वस्तुओं के विक्रय का सामना सापेक्ष रूप से सीमित प्रभावी माँग और बढ़ती हुई भूमण्डलीय प्रतियोगिता से होता है। विकास-दरों के ऊँचा होने के समय भी उत्पादन पूर्ण-समय के 90 प्रतिशत से अधिक कभी-कभी ही होता है। उत्पादन की औसत 75-80 प्रतिशत रहती है जबकि कभी-कभी तो कुछ उद्योगों में उत्पादन 40-50 प्रतिशत ही रह जाता है।

दो महायुद्धों के बीच के सारे समय में अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य पूँजीवादी देशों के उद्योगों में अपनी क्षमता के 50-66 प्रतिशत तक काम किया। हमारे शत्रुओं में, पूँजीवादी विश्व के उद्योगों ने वास्तव में जितना उत्पादन किया, समान उत्पादन संयंत्रों की सहायता से वे डेढ़ गुना से दो गुना तक अधिक निर्माण कर सकते थे। आर्थिक संकट के समय अपूर्ण-उपयोग और भी ज्यादा था। उन्ने बड़े पूँजीवादी देश अमरीका में दीर्घकालिक अपूर्ण-उपयोग विशेष रूप से सामर्थ्यजनक रहा है, जहाँ कि अर्थव्यवस्था में उभार के समय भी उत्पादन कुल क्षमता से बहुत कम रहा। उदाहरण के लिए ब्रिक्स सन्धान के अनुसार 1925-29 में उत्तम उपकरणों के सिर्फ 80-82 प्रतिशत का उपयोग हुआ। 1948-53 में अमेरिका के निर्माण-उद्योग की उत्पादन-क्षमताओं के 92-95 प्रतिशत और 1954-66 में 75-91 प्रतिशत सामर्थ्य का उपयोग हुआ। 1972-1973 के अपवाद के अलावा 1967 से 1975 तक के समय में अमेरिका के निर्माण-उद्योग में अपूर्ण-उपयोग की बढ़ती हुई प्रकृति दिखाई दी। 1975 में औद्योगिक उपकरणों में 1986 के 91.1 प्रतिशत की तुलना में 73.6 प्रतिशत सामर्थ्य का उपयोग किया। 1975 में, जिस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक गिरावट दिखाई दी, युद्ध के बाद सबसे कम 70.9 प्रतिशत सामर्थ्य का उपयोग हुआ। उसके वर्षों में उत्पादन धीरे-धीरे अधिक सामर्थ्य की ओर बढ़ा। लेकिन उद्योगों में उभार के समय भी (1977-78) उत्पादन-क्षमता का लगभग 17 प्रतिशत भाग बेचकर रहा।

विभिन्न पूँजीवादी देशों के निर्माण-उद्योगों में 10-15 प्रतिशत और इससे अधिक क्षमता का अनुपयोग प्रत्येक 7-10 वर्ष की अवधि में एक वर्ष के उत्पादन में प्रतिबिम्बित होता है।

अमेरिकन अर्थशास्त्री ए० एच० हानमेन ने बताया है—“विभिन्न दो अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय उत्पादन का मेला सम्पूर्ण रोजगार के स्तर में 50 बार बँटकर पड़ता है।”

1 ए० एच० हानमेन, “युद्धोत्तर अमरीकी अर्थव्यवस्था : विकास और समस्याएँ”, दृश्य-श्रवण संशोधन एवं प्रसारण, न्यूयॉर्क, 1964, पृ० 93

उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण उपयोग पूँजीवादी पुनरुत्पादन को अवरोध करता है, क्योंकि इनमें बाधक-भुगतान की प्रक्रिया मंद व उत्पादन के साधनों पर की जाने वाली मीन कम हो जाती है तथा बाजार-सामर्थ्य गिर जाती है, जिनके फलस्वरूप पड़ने मानव-शक्ति और फिर उपभोक्ता-वस्तुओं की मीन कम होने लगती है। इसके साथ मौद्रिक-पूँजी का उत्पादन-पूँजी में परिवर्तन और जमा पूँजी का नवीकरण कठिन हो जाता है जिससे नवीन उद्यमों के निर्माण व पानु उद्यमों के विस्तार की प्रेरणाएँ कम होने लगती हैं।

इस प्रकार पूँजीवाद में अंतर्निहित दो विरोधी प्रवृत्तियाँ—(जिन्हें लेनिन ने बनाया था)—उत्पादक-शक्तियों का तीव्र विकास और उनकी अभिवृद्धि में रुकावट—आज भी काम कर रही है। उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग, प्रौद्योगिक प्रगति और पूँजीवादी विश्व में इसके उपयोग की दक्षताओं के बीच अंतर्विरोध का सुस्पष्ट प्रमाण है।

पूँजीवादी विश्व में उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के गतिहीन होने का सूचक है जो उत्पादक-शक्तियों के एक प्रमुख घटक अर्थात् उत्पादन के साधनों के व्यवस्थित रूप से कम उपयोग को सूचित करता है। इसके साथ यह स्थिर पूँजी के नवीकरण को मन्द करता है। यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आंतरिक अस्थिरता का एक प्रमुख कारक है।

2. बहुसंख्य बेरोजगारी की पुरानी बीमारी

बेरोजगारी पूँजीवादी उत्पादन का अनिवार्य संगी है। प्रथम महायुद्ध से पहले बेरोजगारी प्रमुख रूप से आर्थिक-संकट के समय महत्वपूर्ण रूप में बढ़ती थी और अर्थव्यवस्था में उभार व चक्रीय पुनरुत्थान के समय कम हो जाती थी। लेकिन जैसे-जैसे पूँजीवाद का आम-संकट प्रकट होने लगा, बेरोजगारी पूँजीवादी पुनरुत्पादन के अर्थव्यवस्था की सभी अवस्थाओं में अवश्यभावी हो गयी। उत्पादन-समताओं के स्थायी रूप में कम समता पर संभालन के साथ थप के दीर्घकालिक अल्प-उपयोग की प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। ये दोनों, अपनी उत्पादन-समताओं के सम्पूर्ण तथा प्रभावकारी उपयोग करने में आधुनिक पूँजीवाद की असमर्थता की सूचक हैं।

पूँजीवादी देशों के आधिकारिक आँकड़े बेरोजगारों की वास्तविक संख्याओं को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं क्योंकि इनमें सप्ताह के कुछ भाग ही में करने वाले या अंशकालिक काम करने वाले, शिक्षा पूरी करके काम की तलाश करने वाले युवक और बेरोजगारी के साधनों को धी चूकने वाले मजदूर शामिल नहीं होते हैं।

औद्योगिक रूप से विकसित पूँजीवादी विश्व में आज बेरोजगारी की दर अत्यन्त ऊँची है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार ही 1978 में पूँजीवादी विश्व के देशों में बेरोजगारी की दर 150 लाख अथवा कुल सक्रिय श्रम-शक्ति के 5.5

प्रतिशत से भी अधिक थी। यह 1960 के दशक में औसत बेरोजगारी के स्तर से दुगुने से भी अधिक है। अमरीका में, कामों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, 80 के दशक के आरम्भ में बेरोजगारी बहुत विकट सामाजिक-आर्थिक समस्या बनी हुई थी। 1978 में अमरीका में बेरोजगारी की संख्या 65 लाख अर्थात् कुल सक्रिय श्रम-शक्ति का 6 प्रतिशत थी। पश्चिमी जर्मनी में 1974-78 के बीच लगभग 80 मजदूर तथा कार्यालय-कर्मचारी एक या दूसरी तरह से बेरोजगारी के शिकार हुए। जापान में 1978 में बेरोजगारी की दर युद्ध के बाद के उसके इतिहास में सबसे ज्यादा थी। सिके उस वर्ष में पूरी तरह बेरोजगारी की संख्या में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह संख्या बढ़कर 12 लाख 60 हजार हो गयी।¹

बेरोजगारी श्रम-शक्ति के सभी भागों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से सामान्य श्रमियों व नौजवानों और जानीय भेदभाव के शिकार लोगों को प्रभावित करती है। साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में अमरीका में नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर औसत से तीन गुना ज्यादा रही है। 1978 के अंत में, 16 व 19 वर्ष के बीच के 14 प्रतिशत से अधिक नौजवान बेरोजगार थे जबकि कुल बेरोजगारी की संख्या 6 प्रतिशत थी और बाले व अन्य रंगों के जनगणों के बीच बेरोजगारी की दर 34.6 प्रतिशत थी। इसके साथ कुछ बहुत विकसित पूँजीवादी देश नयी उच्च तकनीक वाले उद्योगों से जुड़े नये ध्यावसायिक कार्यों के लिए कुशल मजदूरों को संगीन कमी का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति से जुड़े प्रौद्योगिक व सरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करती है।

जो एक या दूसरे कारण से उत्तम शिक्षा पाने में असमर्थ रहे हैं, वे ही सिके बेरोजगारी के शिकार नहीं हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त तथा उच्चस्तरीय कुशल विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या भी आज काम से बाहर है। 1979 में अमरीका में निम्न ध्यावसायिक वर्ष में बेरोजगारों की संख्या की तुलना में उच्चतर शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञ अधिक संख्या में बेरोजगार थे। उच्चतर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर अन्य देशों में भी इसी प्रकार रही थी। अमरीका के समाचारपत्रों की रपट के अनुसार 1953-65 में बेरोजगारी से हुए नुकसान की राशि 500-700 अरब डॉलर अर्थात् प्रति वर्ष 39 से 54 अरब डॉलर के बीच थी। बेरोजगारी से मेहनतगारों की कुशलता की हानि भी होती है। यह श्रम-शक्ति का अवमूल्यन करती है, नये उद्योगों को कुशल-कर्मों प्रदान करने की समस्या को बढ़ावा देती है और पूँजीवादी समाज में सामाजिक झड़ों को तीव्र करता है।

पूँजीवादी उद्योगों में दीर्घकालिक अपूर्ण-उपयोग के समान दीर्घकालिक

1. 'आम-जीवनों की वार्षिक पुस्तक, 1978; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन, 1978, पृ. 241-289 (अंग्रेजी में)।

बेरोजगारी का तथ्य भी यह बतलाता है कि पूँजीवादी समाज की उत्पादक शक्तियों के उपयोग में आधुनिक पूँजीवाद असमर्थ है और यह उनके विकास में रकावट बन गया है।

3. अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण

आधुनिक पूँजीवाद की शक्तिहीनता और परजोविता की सबसे अनर्थकारी अभिव्यक्ति अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण और शस्त्र-दौड़ है। अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि विज्ञान और तकनीक का प्रयोग जीवन-स्तर व काम की अवस्थाओं में सुधार करने तथा समाज के निर्माण करने के लिए न किया जाकर सामूहिक-विनाश के साधन उत्पन्न करने के लिए किया जाने लगता है।

सैन्यवाद इजारेदारी आधिपत्य तथा साम्राज्यवाद के सारतत्व में निहित है। लेनिन ने लिखा है—“साम्राज्यवाद” अपनी मूलभूत आर्थिक विशेषताओं के कारण, शान्ति व स्वतंत्रता के लिए म्यूनतम पसंद और सैन्यवाद के अधिकतम व सार्वभौम विकास के द्वारा पहचाना जाता है।”¹ समाजवादी क्रांति से बरते हुए ब्रिटीश अलग-अलग (साम्राज्यवादी देशों में शासकीय विभिन्नता) सैन्यकरण का उपयोग उत्पीड़ित व शोषित मेहनतकशों के आर्थिक-राजनीतिक संघर्ष को दबाने और अपनी सर्वोच्चता को दीर्घजीवी बनाने के लिए करता है।

दुमरी और साम्राज्यवाद के युग की विशेषता ब्रिटीश गुटों तथा देशों के बीच बाजारों, कच्चे साम के स्रोत और पूँजीनिवेश के क्षेत्रों के लिए तीखा संघर्ष होता है और यह संघर्ष मजदूर संघर्ष व किसानों को बढ़ाता है।

सैन्यवाद, इजारेदारी पूँजीवाद में आर्थिक रूप से अननिहित उसकी विशेषता है जो विश्व को विभाजित करने के लिए साम्राज्यवादी संघर्ष और मजदूर-वर्ग एवं जनवादी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सैनिक-दमन की इच्छा में निर्धारित होता है। इस संबंध में लेनिन ने लिखा है—“आधुनिक सैन्यवाद पूँजीवाद का वर्तमान है। अपने दोनों कर्णों में—पूँजीवादी देशों द्वारा अपने बाहरी संघर्षों में बहुलक सैनिक-क्षमता के रूप में—और सर्वदूर के आर्थिक, राजनीतिक व दूर प्रसार के आंदोलनों के दमन के लिए सामक-वर्ग के हाथ में अस्त्र के रूप में—यह पूँजीवाद की मजदूर-वर्ग अभिव्यक्ति है।”²

सैन्यवाद के आर्थिक कार्यात्मक मान-संज्ञ की दृष्टि से अभिव्यक्ति साम्राज्य-

1. ए. ए. लेनिन, ‘साम्राज्यवाद और वर्ग संघर्ष’, ‘संग्रहित रचनाएँ’, भाग 23, पृ. 172 (1917 ई.)।

2. ए. ए. लेनिन, ‘साम्राज्यवाद और वर्ग संघर्ष’, ‘संग्रहित रचनाएँ’, भाग 23, पृ. 172 (1917 ई.)।

के युग में विशेष तीव्रता के साथ देखी जा सकती है। पूँजीवाद के आम-सकट अंतर्गत साम्राज्यवादी देशों का बढ़ता हुआ सैन्यवाद प्रमुख रूप से समाजवादी मुदाय और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के विरुद्ध होता है। सैन्यवाद के विकास के इन राजनैतिक ही नहीं, व्यापिक कारण भी हैं—शस्त्र-दौड़ एक ऐसा तरीका जिससे इजारेदार आश्चर्यजनक रूप में धनी हो जाते हैं। यह उनके लिए एकदम सैन्य-उद्योगों के निश्चित करता है जिनसे साखों का मुनाफा होता है। राज्य हीनरी का एक विशाल सैन्य-शक्ति के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आय (प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष कर, राज्य-ऋण, सामरिक महत्व के रूढ़िवादी मान पर नियंत्रण आदि) के परिवर्तन में किया जाता है।

अर्थव्यवस्था के सैन्यकरण का परिणाम अस्त्र-शास्त्र और सेना पर खर्च में तब वृद्धि होता है। उदाहरण के लिए नाटो-संघ के देश, बीस के दशक में तब विश्व सैनिक-उद्देश्यों के लिए जितना खर्च करता था, उससे 40 गुना अधिक कर सकते हैं। मंदन के सामरिक-अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार 949-79 में नाटो देशों का सैनिक खर्च 2700 अरब डॉलर था। पूँजीवादी देशों में सैनिक खर्च लगातार बढ़ रहा है—अस्सी के दशक के आरम्भ में यह खर्च 100 अरब डॉलर वार्षिक हो गया था। यह स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में 150 गुना और शिक्षा पर खर्च से 50 गुना ज्यादा है। 1978 में अमेरिका नाटो-देशों में अस्त्र-दौड़ पर 190 अरब डॉलर खर्च किये थे।¹

अमेरिका में, जो साम्राज्यवाद का प्रमुख राजनैतिक व सैनिक केन्द्र है, सैनिक-खर्च में तीव्र-वृद्धि एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण संदर्भ है। 1861-65 के गृह-युद्ध के समय और 1930 के दशक तक प्रत्यक्ष सैनिक खर्च प्रायः देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होता था। 1922-37 के बीच वार्षिक पुनः खर्च एक अरब डॉलर से कम था। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद के वर्षों में अमेरिका के सैनिक खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जैसा कि इन संख्याओं में दिखाई देता है—1949 में 13.5 अरब डॉलर, 1968 में 79.6 अरब डॉलर और 1980 में 146.2 अरब डॉलर।² इसका अर्थ यह है कि पेंटागन का प्रतिव्यक्ति खर्च 1913 में 2.25 डॉलर, 1952 में लगभग 250 डॉलर और 1980 में 600 डॉलर था।

पूँजीवादी विश्व में सैनिक-तैयारियाँ अप्रत्याशित शान्तिशासीन स्तर पर पहुँच गयी हैं। अस्सी के दशक के आरम्भ में विरहित पूँजीवादी देशों की सेनाओं में 140 लाख आदमी सेवाएँ थे, इनमें से एक करोड़ नाटो देशों की सेवाओं में

1. 'सैन्य व्यय 1978-79', पृष्ठ 1, 1979, पृष्ठ 33-39।

2. 'सैन्य राज्य अमेरिका का संकल्पन वनट : विलीव वर्ष 1981', पृष्ठ 70-71।

थे। इनके अलावा किन्ने ही लाखों व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सैनिक-उत्पादन में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए अमरीका के शस्त्र-उद्योग में 60 लाख व्यक्ति काम करते हैं। विकसित पूँजीवादी देशों के निर्माण-उद्योगों में काम करने वालों की कुल संख्या के लगभग एक-चौथाई सबसे श्रेष्ठ कार्यकुशल मजदूर और लाखों वैज्ञानिक व अनुभवी इंजीनियर सैनिक-औद्योगिक-मशीनों के लिए काम करते हैं।

साम्राज्यवादी देशों में विज्ञान के विकास को काफी हद तक प्रतिक्रियावादी आक्रामक उद्देश्यों के अधीन कर दिया गया है। अस्ती के दशक के आरंभ में अमरीका में मोक्ष एवं विकास के कुल खर्च का लगभग 75 प्रतिशत सैन्यकरण में संबंधित था। युद्ध-उद्योग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से पूँजी, कुशल श्रमिक, कच्चा माल तथा उपकरण अपनी ओर खींचता है।

सैन्यकरण विकास को मद करने और उत्पादक शक्तियों को नष्ट करने वाला एक प्रमुख कारक है। यह तथ्य कि सैन्यवाद अर्थनीति व राजनीति का आर्थिक घटक बन गया है, इसका सुस्पष्ट प्रमाण है कि पूँजीवाद के अस्तित्व का बने रहना कुल मिलाकर मानवता की सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण हितों की दृष्टि से अनंगत है। ऐसा होने पर ही पूँजीवादी अर्थशास्त्री मेहनतकशों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण सिर्फ आर्थिक-संकट पर ही नहीं, पूँजीवाद के आम-संकट पर भी विजय पाने में सहायक हो सकता है। सिमोन बुजनेत्स, प्रसिद्ध पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों में एक, कहते हैं कि युद्ध, चाहे सशस्त्र हो या शीत, उस देश को, आर्थिक-विकास के मद होने के कारण जिसने अपनी आर्थिक स्थिति खो दी हो, ऐसी प्रेरणा दे सकता है कि उसके विकास की प्रवृत्तियाँ पहचान से परे बढल जाएँ। एस्किन एच० हानसेन भी लगभग यही दुहराता है जब वह यह दावा करता है कि सैनिक-खर्च ने अमरीका को गरीब नहीं बनाया है। यद्यपि सैनिक उत्पादन का विस्तार, विशेष रूप से आरंभ में, अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक प्रोत्साहित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप से सैन्यवाद, भारी मात्रा में भौतिक व मानवीय संसाधनों तथा राष्ट्रीय आय के अधिकांश भाग को सैनिक खर्चरतों में खींचकर विस्तारित पुनरुत्पादन के आधार को नष्ट करता है।

आर्थिक दृष्टि से सैनिक-उत्पादन और सशस्त्र सेनाओं का रख-रखाव सामाजिक-उत्पादन के एक बड़े भाग का अनुत्पादक व्यय है। सैनिक उत्पादन को असैन्य उद्योगों की कीमत पर बढ़ाया जाता है। इससे असैन्य उद्योगों की वृद्धि-दर कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय का जो भाग सैनिक-उद्देश्यों पर खर्च किया जाता है, उस अर्थव्यवस्था में पुनः नहीं लगाया जाता। सैनिक-उत्पाद उत्पादन के तत्त्वों की वस्तु अथवा मूल्य के रूप में क्षतिप्रति नहीं करते हैं। संसाधनों की भारी मात्रा को अनुत्पादक सैनिक-खर्चरतों में लगाकर सैन्यकरण

समय अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर को कम करने हुए संसाधनों के परिमाण को, जिसे उत्पादक-सचय के लिए काम में लाया जा सकता है, कम करता है। अल्पविकसित देशों में अर्थव्यवस्था आने देशों में पूँजी-सचय और आर्थिक-विकास की दर कम हो रही है। पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों के दावे के विपरीत संन्यकरण नागरिक-उत्पादकों को हानि पहुँचाकर किया जाता है और इसका परिणाम जीवन-स्तरों में ह्रास और दीर्घकालिक बेरोजगारी होता है।

राष्ट्र-दौड़ अधिक ऊँचे सैनिक खर्च और इसके परिणामस्वरूप अधिक ऊँचे करों को जन्म देती है और ये कर उपभोक्ता गण-शक्ति में कमी करते हैं। साम्राज्यवादी देशों में विशाल सैनिक खर्च भारी बजट घाटा, राजकीय ऋणों में वृद्धि और कागजी-मुद्रा के बढ़ते निस्सरण को जन्म देते हैं। इसका परिणाम होता है—अल्पमूल्यन, अपूर्व मुद्रा-स्फीति और वास्तविक मजदूरी में कमी। मुद्रा-स्फीति की दर में मजदूरी की तुलना में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ती हैं और इसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रीय आय में मजदूरों के भाग को कम करने की कीमत पर पूँजीपतियों के मुनाफे बढ़ते हैं। मुद्रा-स्फीति पूँजीपतियों के हित में राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण और मेहनतकशों को सूटने का एक तरीका है। परिणामस्वरूप, सैनिक-खर्चों में वृद्धि अर्थव्यवस्था कैसे भी की जाए, अंत में उसका सारा भार मेहनतकशों के कंधों पर आता है। इसके साथ यह हज़ारेदारों को धनवान बनने में भी सहायता देता है।

4. आर्थिक-संकट

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता एक अवधि बाद बार-बार आने वाली अति-उत्पादन के संकटों—जो बढ़ी हुई उत्पादक-शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए पूँजीवाद की असमर्थता एवं पूँजीवादी सामाजिक-संरचना की अल्पकालीनता के बहुत तीव्रता से स्पष्ट करते हैं, के रूपों में स्वयं को प्रकट करती है। इस संकट में लेनिन ने निम्ना है—“संकट यह दिखाता है कि यदि भूमि, कारखाना, मशीन आदि पर कुछ छोटे से निजी स्वामियों का कब्जा नहीं हो जोकि जनगण की शरीर से लाखों के मुनाफे निचोड़ते हैं, तो बाधुनिक समाज समस्त मेहनतकशों की जीवन-दशाओं में सुधार करने के लिए अपार भाषा में वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।”¹

पूँजीवाद के प्रमुख अंतर्विरोध—उत्पादन की सामाजिक प्रकृति तथा इस परिणामों को पाने के निजी पूँजीवादी रूप के बीच अंतर्विरोध में वृद्धि हो जाने के आम-संकट की अवस्था में, इसके आर्थिक-घटकों में परिवर्तन हो गया है। ये घटकों छोटे हो गये हैं, इसके परिणामस्वरूप संकट बार-बार व शीघ्र आने लगे हैं और

1. वी०आई० लेनिन, ‘संकट की दिशाएँ’; संकलित रचनाएँ, भाग 5, पृ० 81 (अंग्रेजी में)

अधिक गहरे व विनाशक हो गये हैं, तथा पूँजीवाद के आम-संकट से पहले की तुलना में अब सुधार के दौर में भी उत्पादन-वृद्धि कम सघन होती है।

दो महायुद्धों के बीच पूँजीवाद की आम-संकट की पहली अवस्था में पूँजीवादी विश्व में अति उत्पादन के तीन चक्रो-आर्थिक-संकट आये—1919-20 में, 1929-33 में और 1937-38 में। पूँजीवाद के आम-संकट से पहले जहाँ दो संकटों के बीच सबसे लंबा अंतराल 12 वर्ष का था, आम-संकट की पहली अवस्था में यह घटकर 7-8 वर्ष हो गया।

पूँजीवाद के आम-संकट की पहली अवस्था में, आर्थिक-संकटों ने पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को काफी प्रभावित किया और उनकी विनाशक शक्ति पहले के आर्थिक-संकटों से बहुत ज्यादा थी। सबसे गंभीर संकट, जिसका पूँजीवाद ने अभी तक अनुभव किया है, 1929-33 का संकट था। बाद में आने वाली मंदी के साथ मिलकर यह 5-7 वर्ष तक रहा और इसने उत्पादक-शक्तियों का अभूतपूर्व विनाश किया। उदाहरण के लिए अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में 202 धन-भट्टियाँ लोदी गयीं। इसके साथ अमरीका में 104 लाख एकड़ में कटाव नष्ट की गयी और 64 लाख सूअरों की हत्या की गयी।

द्वारा महायुद्ध शुरू होने के पहले के समय के समान युद्ध-बाद के वर्षों में भी पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था बार-बार आर्थिक-संकटों से प्रभावित हुई। युद्ध-बाद का पहला संकट 1948-49 में आया जिसने मुख्य रूप से अमरीका तथा कनाडा की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया और इन देशों में उत्पादन क्रमशः 18.2 व 12.3 प्रतिशत कम हो गया। चूँकि युद्ध-बाद के आरम्भिक वर्षों में अमरीका व कनाडा पूँजीवादी विश्व के कुछ औद्योगिक उत्पादों के आधे से अधिक भाग का उत्पादन करने में, अतः उनके उत्पादन में कमी से समग्र पूँजीवादी विश्व का औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हुआ।

बाद के वर्षों में विश्व-पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और अधिक क्षतिग्रस्त हो गयी। 1957-58 के आर्थिक-संकट के समय आठ देशों—अमरीका, कनाडा, जपान, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस में उत्पादन का सम्पूर्ण ह्रास हुआ और इसके बाद पूँजीवादी विश्व में गयी आर्थिक उथल-पुथल हुई।

1974-75 का विश्व-आर्थिक-संकट युद्ध-बाद के पूँजीवादी पुनरुत्थान में कुछ विशेष स्थान रखता है। इसने सभी विकसित पूँजीवादी देशों को प्रभावित किया और इसकी नज़रार्द बनीरना निर्ज 1930 के दशक की मंदी में तुलनीय थी। युद्ध-बाद की अवधि में उन्नत अति-विकसित राजकीय इकाइयों की अर्थव्यवस्था की उथल-पुथल में दिख गयी। 1975 के दूसरे चतुर्थांश में जपान में 20.2, ब्रिटेन में 15.3, फ्रांस में 14.8, इटली में 13.5 और ब्रिटेन में 10.6 प्रतिशत उत्पादन का ह्रास हुआ। उत्पादन-कटौती और क्षमता में भारी कम उत्पादन के

परिणामस्वरूप बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई। अधिभुन और दो के अनुसार 1975 के मध्य में विश्वमिश्र पूँजीवादी देशों में 150 लाख व्यक्ति पूरी तरह बेरोजगार थे। इस मध्य में वे अपजीवन बेरोजगार शामिल नहीं हैं, जिन्होंने किसी प्रकार के काम पाने की सारी आशा छो दी है। बेरोजगारी ने विदेशी मजदूर, राष्ट्रीय अल्प-संख्यक तथा बुद्ध व नौजवानों पर विशेष रूप से कठोर प्रहार किया।

1974-75 के विश्व-आर्थिक-संकट और 1980 में शुरू हुए नये गंभीर संकट ने हमला और अधिक विश्वमनीय माध्य प्रस्तुत किया कि पूँजीवादी सिद्धांत पूँजीवाद के अनर्गल आर्थिक-संकटों को समाप्त करने की आशा नहीं रख सकते। इस संकट ने विश्व-पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निरंतर बढ़ती अस्थिरता का भी और अधिक विश्वमनीय प्रमाण प्रस्तुत किया है। मुशारवादियों तथा पूँजीवादी विचारकों द्वारा गढ़ा गया एक प्रमुख मिथक—यह कि वर्तमान पूँजीवाद संकटों का निवारण करने में समर्थ है—शक्ति हो गया है। पूँजीवाद की अस्थिरता अधिक-से-अधिक प्रकट होनी आ रही है।

5. बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति और तीव्र वर्ग-मध्य

मुद्रा-स्फीति, जो आर्थिक-विकास की बढ़ती अस्थिरता की एक बहुत विशिष्ट अभिव्यक्ति है, वर्तमान में पूँजीवाद की एक प्रमुख समस्या है। पहले मुद्रा-स्फीति मुख्य रूप से मुद्रा और मुद्रा-वाद की आर्थिक-अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ती थी, मात्र पूँजीवादी उत्पादन-वृद्धि की दर अवस्था में मुद्रा-स्फीति की दर अत्यधिक ऊँची है।

मुद्रा-स्फीति सामान्यतः बचत-पाटा से उत्पन्न होती है। अब पूँजीवादी राज्य कर, श्रृंखला आदि के द्वारा अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने में असमर्थ होकर, विशेषतः मुद्रा और आर्थिक उच्च-गुण के बाद, अत्यधिक मात्रा में कागजी-मुद्रा छापने लगता है, जब परिणामस्वरूप यह मुद्रा स्वयं, वास्तु में विदेशी-मुद्राओं की तुलना में तेजी से कीमत खोने लगती है। उत्पादन में गिरावट के कारण, अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक खरच से बहुत अधिक कागजी-मुद्रा से मुद्रा-वितरण की प्रणालियाँ जनि-मनुष्य हो सकती हैं, जिसका अर्थ यह होता है अतिरिक्त बैंक-मुद्रा छापे बिना भी धन की कीमत कम होने लगती है। पूँजीवाद के आम-संकट और इसके अंतर्विरोधों की संपूर्ण-वृद्धि के समय, जब स्वयं को वितरण से हटा लिया जाता है और उधार धन स्वयं से परिवर्तनीय नहीं रह जाता है, मुद्रा-स्फीति साधारण और दीर्घकालिक हो जाती है।

पूँजीवाद के आम-संकट के समय मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहित करने वाले बहुत-से कारक सक्रिय हो जाते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली है सैन्यवाद, जो मुद्रा के समय और मुद्रा-वाद की आर्थिक दुर्घटना में ही नहीं, शक्तिकाल में पूँजीवादी अर्थ-

व्यवस्था के सामान्य विकास के समय भी मुद्रा-स्फीति के संज को प्रोत्साहित करना है। शस्त्र-दौड़ सैनिक-उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय आय के अनुत्पादक उपयोग को और सामाजिक-मर्यादा के एक भाग की प्रत्यक्ष हानि को बढ़ाती है। शस्त्र-दौड़ के कारण शस्त्र-उत्पादक क्षेत्रों में और सैनिक-सेवा में लगे व्यक्तियों के पाम अधिक-से-अधिक धन जाने लगता है। इसका परिणाम होता है किसी प्रकार के अनुकूल वस्तु-समर्पण के बिना ही बाणजी-मुद्रा की राशि में वृद्धि। उच्चतर सैनिक-व्यय पूँजीवादी देशों के बजट-घाटा और बढ़ते हुए राज्य-ऋणों का प्रमुख कारण है। कर और ऋणों के अतिरिक्त मुद्रा-स्फीति सैनिक-व्ययों के लिए वित्त-व्यवस्था का एक तरीका है।

बढ़ती मुद्रा-स्फीति आधुनिक पूँजीवादी विश्व की विशेषता है जिसका निरंतर चढ़ती कीमतों और तेजी से दोड़ती मुद्रा-स्फीति (जिसके समय कीमतें तेजी से उत्तरोत्तर बढ़ती हैं) से स्पष्ट होता है। उत्पादन में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी (जिसे अब गतिहीनता कहा जाता है) के साथ मुद्रा-स्फीति 1960 के दशक से पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की नयी परिघटना हो गयी है। 1974-75 के संकट के समय यह प्रवृत्ति विशेष रूप से स्पष्ट थी जबकि उत्पादन में ह्रास व बेरोजगारी में वृद्धि के साथ कीमतों व मुद्रा-स्फीति में भी वृद्धि हुई थी। आज इजारेदारों की नीतियाँ ही, आर्थिक-संकट के दिनों में, कीमतों में वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि संकट के दिनों में भी वस्तुओं के मूल्यों को उच्च-स्तर पर बनाये रखने के लिए वे राज्य की सहायता-प्राप्त अनेक उपायों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ आर्थिक-संकट को नियंत्रित करने के लिए पूँजीवादी राज्य द्वारा उठाये गये कुछ कदम भी उच्चतर कीमतों को प्रोत्साहित करते हैं।

मुद्रा-स्फीति का पूँजीवादी पुनरुत्पादन पर भारी प्रभाव होता है। एक तरफ यह कुछ हद तक उत्पादन की गति को तेज करती है लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक-संकट को भी बढ़ावा देती है। मुद्रा-स्फीतिजन्य तेजी के समय निगम अतिरिक्त मुनाफ़ा कमाने व निवेश में वृद्धि करने के लिए अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा देते हैं। इससे उत्पादन के साधनों के बाजार का विस्तार व उत्पादक-पूँजी का संघर्ष होने लगता है, परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों तथा उपभोक्ता उपकरणों का अधिक उत्पादन होता है। फिर भी राज्य-इजारेदार पूँजीवाद के उपायों की व्यवस्था मेहनतकारों की श्रम-शक्ति बढ़ाने में सहायक नहीं होती। परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति उत्पादक-पूँजी के संघर्ष को सुविधापूर्ण बनाते और उत्पादन व अन्तिम उपयोग के बीच अंतर को बढ़ाते हुए पूँजीवादी-पुनरुत्पादन में अंतर्विरोधों को तीव्र करती है। इस प्रकार लगातार जारी मुद्रा-स्फीति, आर्थिक-सामाजिक को तीव्र करते हुए पूँजीवादी-पुनरुत्पादन की अस्थायी प्रेरक शक्ति की उमका अवरोध बन जाती है।

मुद्रा-स्फीति का सारणत्व यह है कि इसमें मजदूर-वर्ग और सारे मेहनतकारों

की कीमत पर प्रभावी शोषक-वर्ग के हित में राष्ट्रीय आय का अनुप्रेषण शामिल है। नाममात्र की मजदूरी की तुलना में कीमतों का उपादा से जोड़े में बढ़ती है। वास्तविक मजदूरी में ह्रास के समानुपात में पूँजीवादी उत्पादन की मात्रा में ह्रास होता है, इसमें मेहनतगर्जों के शोषण में वृद्धि होती है। मुद्रा-स्फीति शोषण का एक छूपा हुआ तरीका है। इसका प्रयोग एक पूँजीपति व्यक्ति नहीं, बल्कि राज्य-तंत्र की सहायता से पूँजीपति-वर्ग करता है। इसके साथ अपने लाभ के लिए पूँजीवादी राज्य, मुख्य रूप से मेहनतगर्जों को हानि पहुँचाने हुए मुद्रा-स्फीति के द्वारा अनेक वस्तुओं को वितरण से हटा लेता है। मुद्रा-स्फीति का भार पैशन-याताओं की शामिल करते हुए सभी मेहनतगर्जों के कंधों पर आता है क्योंकि कीमतों में वृद्धि के बावजूद पैशन या तो पुराने स्तर पर रुकी रहती है या कीमतों की तुलना में उतनी ज्यादा और उनकी तेजी से नहीं बढ़ती है।

मसूर के दशक के बाद मुद्रा-स्फीति की दरें बहुत बढ़ गयी हैं और कीमतों में तीव्र वृद्धि एक स्थायी परिपटना बन गयी है। 1974-75 का आर्थिक संकट, विशेष रूप से बाद की गहरी व दीर्घकालिक गतिहीनता की विशिष्टता लगभग सभी धनी वस्तुओं में जैसे खाद्य-पदार्थ व रोजमर्रा की सेवाओं की कीमतों में उच्चतर वृद्धि थी। उदाहरण के लिए 1979 में आवश्यक वस्तुओं की कीमत अमरीका में 80, कनाडा में 90, ब्रिटेन में लगभग 200, फ्रांस में 100, इटली में लगभग 200, जापान में 100 से अधिक और जर्मनी में 70 प्रतिशत अधिक की थी।¹ नाममात्र की मजदूरी की तुलना में कीमतों में वृद्धि बहुत तेज थी और युद्ध के बाद के वर्षों में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में मजदूर-वर्ग की तन्त्र-शक्ति में ह्रास हुआ। यू० एस० न्यूक एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में 1977-78 में ही उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस मसूमे में 1977 में अमेरिकियों ने जिन मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए 7 डॉलर खर्च किये थे, उसी के लिए 1978 में उन्हें 11 डॉलर खर्च करने पड़े।²

मुद्रा-स्फीति पूँजीवादी देशों में लाखों मनुष्यों की आर्थिक स्थितियों को बिगाड़ती है और उनके भविष्य पर संदेह की छाया डालती है। मेहनतक पूँजीवादी राज्यों द्वारा किसी तरह के नेतन-नियंत्रण से जब उपभोक्ता वस्तुओं व कीमत लगातार बढ़ रही हो तब 'मजदूरी-बाम' की कोशिशों से—खास तौर पर चिंतित होते हैं।

मुद्रा-स्फीति अब मुद्रा-संकट के, जो स्वयं को राष्ट्रीय मुद्रा के अवमूल्यन तथा अधिकांश पूँजीवादी देशों द्वारा अनुभव किये जाने वाले व्यापार व भुगतान

1. मुख्य आर्थिक संदर्भक, जनवरी, 1980।

2. यू० एस० न्यूक एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, मार्च 13, 1978।

विगड़ने मनुष्य के मन में घट्ट कर रहा है, लगातार विभिन्न होने के कारण नीव हो रही है। पूँजीवादी सरकारें, मुख्य रूप से मेहनतकों के मूलभूत हितों की कीमत पर अपने आर्थिक संसाधन व विशेषी बाजारों तथा राज्य व मनुष्य के बीच मौद्रिक-मनुष्य जाने की कोशिश कर रही है। मेहनतकों के लिए इसका अर्थ है नती किटानाइयाँ क्योंकि इन नीति में मजदूरी पर रोक और उपभोग में कटौतियाँ शामिल होती हैं।

आर्थिक अभिवर्तन के अलावा, पूँजीवाद के आम-जगह की वर्तमान अवस्था की विशेषता पूँजीवादी राजनीति-व्यवस्था में अमूलपूर्ण अभिवर्तन भी है। पूँजीवादी देशों में सरकारों के बार-बार परिवर्तन साधारण बात है। संघीय बहुमत, जिन पर सामंतीय विनिष्ट बर्तन नियमन: विधायक करना है, साधारणतः महत्वहीन और अविवशनीय हो गया है।

आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक पूँजीवादी राजनीति शास्त्री पूँजीवादी राजनीति-व्यवस्था में सौर-उत्पन्न अविवर्तन को दूर करने की आवश्यकता का प्रायः बढ़ते रूप में उल्लेख करते हैं। जुलाई, 1979 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने अमरीका की स्थिति के बारे में यह कहा था—“यह विश्वास का गश्त है। यह ऐसा सच है जो हमारी राष्ट्रीय इच्छा-शक्ति के प्राण-तत्व, ठीक हृदय और आत्मा पर प्रहार करता है और अमरीका की राजनीतिक-सामाजिक चुनाव को नष्ट करने की धमकी दे रहा है।”

विगड़ती हुई जीवन-दशाएँ और मुद्रा-स्थिति व आर्थिक संकट के तारे मार को मेहनतकों के कंधों पर डालने की पूँजीवादी इजारेदारों की इच्छा ने पूँजीवादी विश्व में मेहनतकों के मजबूत प्रतिरोध को बढ़ाया है। आधुनिक पूँजीवादी समाज के आर्थिक-सामाजिक मुद्दों का सामना करने में पूँजीवादी देशों की सरकारों की असमर्थता ने वर्गीय अंतर्विरोधों को तीव्र कर दिया है।

हड़तालें मेहनतकों के असंतोष का एक प्रमुख संदर्भ हैं। पृष्ठ 77 पर दी गयी सारणी उनकी वृद्धि को स्पष्ट करती है।

1970 के दशक में हड़तालों के प्रमुख संकलन, उनका बेहतर संगठन और व्यापक चरित्र थे। मेहनतकों द्वारा अधिक-से-अधिक कार्यवाहियों की गयीं, जिनमें एक उद्यम के ढाँचे से आगे बढ़कर समस्त उद्योगों को घेरने वाली आर्थिक-मार्गें शामिल थी और वे राजनीतिक कार्यवाहियों के रूप में विकसित हो गयीं। शोषण के विरुद्ध प्रतिवाद, इजारेदारी आधिपत्य के खिलाफ तथा आधारभूत सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के लिए संघर्ष का एक संघटक हिस्सा हो गया। 1970 के दशक में सभी हड़तालों हुई और उनमें समाज के विभिन्न क्षेत्र व्यापक रूप में

सारणी-3
प्रमुख पूँजीवादी देशों में हड़तालें

वर्ष	हड़तालों की संख्या	हड़तालियों की संख्या	हड़ताल के मानव-दिनों की संख्या
1970	21,456	12,788,000	110,570,000
1971	24,585	15,974,000	93,847,000
1972	21,588	14,138,000	87,193,000
1973	25,870	17,702,000	74,204,000
1974	29,051	20,106,000	106,233,000
1975	23,518	22,988,000	87,286,000
1976	23,193	29,420,000	88,960,000
1977	23,479	14,148,000	68,705,000
1978	33,840	25,254,000	99,262,000

स्रोत—धर्म-और-कर्म की वापिसी—1978, संयुक्त राष्ट्रसंघ 1979

शामिल हुए। मजदूर-वर्ग की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ी, साथ ही मेहनतकशों के हितों तथा वास्तविक राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष के हराबस दस्तों के रूप में उसकी भूमिका भी बढ़ी।

हड़ताली कार्रवाहियों की निरन्तरता एवं बढ़ता हुआ व्यापक चरित्र, मेहनत-कशों की अधिक बढ़ी एकता, संघर्ष के रूपों की विविधता और राजनैतिक दिशा-वाली नयी माँगों का उठाया जाना—1970 के दशक में हड़ताली-आन्दोलन के ये महत्वपूर्ण घटक थे।

हड़तालियों ने वेतन में कटौती के बिना काम के कम घंटों, पूरी मजदूरी के बराबर बेरोजगारी भत्ता, प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी आदि की माँग की। शस्त्र-निर्माण करने वाले उद्योगों को नागरिक उत्पादन में बदलवाने के लिए मेहनतकशों का आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिकंदर सार्थक रूप में बढ़े हुए नये काम ही उत्पन्न नहीं करेगा बल्कि शस्त्र-दोड़ पर भारी मात्रा में खर्च किये जाने वाले संसाधनों में कुछ हद तक कटौती करेगा ताकि उनका उपयोग जनगण की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सके।

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का विकास

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का जन्म और विकास, पूंजीवाद के आम-सकट तथा पूंजीवादी विश्व की राजनीति; अर्थनीति वव सामाजिक-संरचना में बहुत व्यापक परिवर्तनों से अभिन्न जुड़े हुए हैं। राज्य-इजारेदार पूंजीवाद स्वयं को, नयी विश्व-स्थिति—दो व्यवस्थाओं के बीच वर्तमान संघर्ष की दशाओं तथा वैज्ञानिक-प्रौद्योगिक क्रांति के अनुकूल ढाल रहा है।

1. इजारेदार पूंजीवाद का राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के रूप में विकास

पूंजीवाद के आंतरिक नियमों के परिणाम-स्वरूप इजारेदार पूंजीवाद ने पहले महायुद्ध के समय राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के रूप में, जो इसकी अंतिम अवस्था—साम्राज्यवादी अवस्था—की विशेषता है, विकसित होना शुरू किया।

साम्राज्यवाद के अपने अध्ययन में सेनिन ने यह स्थापित किया कि पूंजीवाद अहस्तक्षेपकारी पूंजीवाद से इजारेदार-पूंजीवाद की ओर तथा इजारेदार पूंजीवाद से राज्य-इजारेदार पूंजीवाद की ओर बढ़ गया है। इजारेदार पूंजीवाद तथा राज्य की संयुक्त शक्ति राज्य-इजारेदार पूंजीवाद की विशेषता है।

पूंजीवादी राज्य अर्थनीति या अर्थव्यवस्था में सभी विमुख नहीं रहा है, यद्यपि पूंजीवादी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की प्रकृति और शक्ति एक समान नहीं रहे हैं। इजारेदार पूंजीवाद में पहले की अवधि में राज्य मौद्रिक-क्षमता, उद्योग और श्रमों की व्यवस्था के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता था। राज्य ने पूंजीपतियों को भू-संपत्ति और आर्थिक सहायता दी तथा नैतिक सपन्न, जमानदार, रेल एवं संचार-सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रायः बिना-प्रबन्ध दिया। फिर भी, तब अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप वसा ५११

जा था और अर्थव्यवस्था के वैयक्तिक-स्रोतों को ही प्रभावित करता था। मुक्त योगिता तथा पूँजीवादी उत्पादन की विचरी व असंबद्ध प्रकृति, पूँजीवादी-वस्था के कार्य करने की तत्कालीन दशाओं को बनाये रखते हुए, राज्य की एक भूमिका को सीमित करती थी। पूँजीपति राज्य से पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता देने की आशा रखते थे, जिसे (उनके शब्दों में) 'रात का प्रहरी' बनने तक सीमित ला चाहिए।

साम्राज्यवाद के युग में और विशेष रूप से पूँजीवाद के आम-संकट के समय राज्य का हस्तक्षेप संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैल गया है तथा व्यवस्थित गहरा हो गया है। आधुनिक राज्य अनेक आर्थिक कार्य करता है और स्वयं एक शक्तिशाली आर्थिक ताकत हो गया है। यह पूँजीवादी-गुनरत्थान की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है तथा समस्त उद्योगों में उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी है। अर्थव्यवस्था में इसका स्थान बड़े मालिक, उपभोक्ता, श्रमदाता व कर्जदारों के है।

साम्राज्यवाद के युग में इजारेदार पूँजीपति-वर्ग सारे समाज में प्रबलशक्ति बन गया है। पूँजीपति-वर्ग के आंतरिक प्रतियोगी संबंधों में राज्य की सहस्यता राज्यतंत्र में शासकीय विशिष्ट वर्ग के आधिपत्यवाद में बदल गयी है जो बड़े वृत्तीय पूँजीपतियों के हितों की उत्साह के साथ रक्षा करता है। इस प्रकार राज्य इजारेदार पूँजीपति-वर्ग के कारोबार की व्यवस्था करने वाली समिति बन गया है।

पूँजीवादी-इजारेदारियों और राज्यतंत्र मुख्य रूप से निजी संघों के द्वारा बनकर एक व निकटता से अंतर्बंधित हो गये हैं। इन संघों में सरकारी मंत्रियों सहित उच्च-अधिकारी व्यापारिक दुनिया से अपने सम्बन्धों को मजबूत करते हैं और निगमों के बोर्डों में साध के पद प्राप्त करते हैं। इजारेदार ऐसे उच्च अर्थनिक अधिकारियों को, जो राज्य-तंत्र के रहस्यों से भली प्रकार परिचित होते हैं और सरकार सरीक़ों से उसे प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, भीषता से नौकरी देते हैं। इससे भी आगे इजारेदार, जो राज्यतंत्र की बड़ी हुई आर्थिक-राजनैतिक शक्ति से अच्छी तरह परिचित हैं, महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर बन्दा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने सेवकों के माध्यम से राज्य-तंत्र के जाल में घुस जाते हैं। राज्य-तंत्र को प्रभावित करने के लिए निगम विविध प्रकार के व्यापारिक-समूहों, जन-संगठनों और पूँजीवादी राजनैतिक दलों के अधिकारियों का प्रयोग करते हैं। निजी संघों के अलावा राज्य के आर्थिक क्रियाकलाप भी राज्य व इजारेदारों के परस्पर विलयन के महत्वपूर्ण रूप हैं।

राज्य-इजारेदार पूँजीवाद का सारतत्त्व यह है कि पूँजीवादी राज्य की शक्ति इजारेदारों के साथ एक तंत्र में संयुक्त हो जाती है। यह तंत्र इजारेदार पूँजी के

निम्न अधिनियम संभव मुनाफ़ा निश्चित करने के लिए काम करता है और माप ही जनवारी व मजदूर आन्दोलनों तथा राष्ट्रीय मुक्ति मण्डलों के दमन के लिए अवसर प्रदान करता है। यह सर्व भूतपूर्व उनिवेगो व पराधीन देशों के समस्त जनताओं को अपने राजनैतिक-आर्थिक हितों के अधीन करने के लिए और समाजवादी विचार के विरुद्ध सहाई से इजारेदारों के पक्ष में भी काम करता है। मात्र राज्य-इजारेदार पूँजीवाद का प्रमुख उद्देश्य पूँजीवादी-व्यवस्था की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सपर्यं करना है।

राज्य-इजारेदार पूँजीवाद की आर्थिक उत्पाति पूँजी के उच्चस्तरीय संकेन्द्रण व इजारीकरण और अपने अत्यन्त अन्तर्विरोधी व विरोधपूर्ण रूप में पूँजीवादी-उत्पादन के समाजीकरण पर आधारित है। उत्पादन के उच्चस्तरीय संकेन्द्रण और समापूँजी के हिस्सों में वृद्धि होने के कारण विज्ञान मात्रा में निरंतर की ज़रूरत होती है। कुछ उद्योगों में विस्तारित उत्पादन के लिए वैयक्तिक पूँजीपतियों के ही नहीं, निगमों के संगठन भी अव्याप्य हो जाते हैं। तब राज्य पूँजी के संकेन्द्रण को प्रोत्साहित करने और मोघ व विकास की परियोजनाओं के लिए (खास तौर से उन क्षेत्रों के लिए जहाँ परिणाम मद गति से मिलने हैं तथा विज्ञान संसाधनों की ज़रूरत होती है) वित्त-निवेश करने में उनकी सहायता करता है।

पूँजीवादी उत्पादन के इजारीकरण व समाजीकरण से वैयक्त्य में वृद्धि होती है। इजारेदार अर्थव्यवस्था के अतिनामकारी क्षेत्रों पर दबका कर लेते हैं और फिर आधुनिक वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक आधारों पर उनका तेज़ी से विस्तार करते हैं। वे क्षेत्र, जिनमें कम मुनाफ़ा होता है, विकास में पीछे रह जाते हैं। किन्तु सामाजिक पूँजी के पुनरुत्पादन के लिए अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में एक निश्चित सम्बन्ध की ज़रूरत होती है। अलाभप्रद क्षेत्रों अथवा जो क्षेत्र विशेष लाभप्रद नहीं हैं उनमें प्रवेश करके तथा अलाभकारी परियोजनाओं में वित्त-निवेश करके राज्य देश के आर्थिक ढाँचे में निश्चित परिवर्तन करता है और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है।

इजारेदारियों की सर्वोच्चता उत्पादन व उपभोग के बीच अंतर्विरोध को बढ़ाती है और मान-उत्पादों की समस्या को गंभीर बना देती है। वित्तीय अल्पतंत्र राजकीय भाग, विशेष रूप से सैनिक-उपयोग में काम आने वाले उत्पादों की माँग को बढ़ाकर बाज़ार की सामर्थ्य में वृद्धि करने का तथा इन अंतर्विरोधियों का समाधान करने का प्रयत्न करता है।

उत्पादन का समाजीकरण निजी पूँजीवादी स्वामित्व की सीमाओं से आगे बढ़ गया है और पूँजीवादी-सम्बन्धों को तोड़ने की ज़रूरत को निर्देशित कर रहा है। लेकिन इजारेदार पूँजी विस्तारित उत्पादन-शक्तियों पर मजबूत अधिकार पाने और निजी पूँजीवादी स्वामित्व को बनाये रखने के लिए राज्यतन्त्र का उपयोग

करती है।

इजारेदार पूँजीवाद राज्य-इजारेदार पूँजीवाद में क्यों विकसित होता है, इसके कारण केवल साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता तथा वर्गीय व सामाजिक अंतर्विरोधों की वृद्धि में भी है। राज्य पूँजी व श्रम के बीच सम्बन्धों में हस्तक्षेप करता है और इजारेदारों को मजदूर-वर्ग व कुल मिलाकर मेहनतकों पर बड़ा-बड़ाकर आर्थिक तथा राजनैतिक दबाव डालने की छूट देने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक कानूनों का प्रयोग करता है।

इजारेदार पूँजीपति-वर्ग उपनिवेशी व पराधीन देशों में अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग करता है और राज्य की शक्ति के माध्यम से विकासशील देशों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करता है।

इस प्रकार पूँजी व उत्पादन के संकेन्द्रण में भीमकाय वृद्धि, इजारेदारों की बढ़ती हुई शक्ति और साम्राज्यवाद के आर्थिक-राजनैतिक अंतर्विरोधों का तीव्र रूप में गभीर होना—ये सब राज्य-इजारेदार पूँजीवाद के विकास के घटक हैं। इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय व जातिरिक्त कारणों तथा साम्राज्यवाद की राजनीति व अर्थनीतियों में नयी परिघटना के कारण में राज्य-इजारेदार पूँजीवाद, विशेष रूप से पूँजीवाद के आम-संकट की तीसरी अवस्था में आये बड़ा।

राज्य-इजारेदार पूँजीवाद का बढ़ता हुआ तीव्र विकास उत्पादक-शक्तियों के और अधिक विकसित हो जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। केंद्रीकृत समन्वय और शोध व विकास के लिए विराट संसाधनों की जरूरत होती है, इस कारण इजारेदार पूँजी राज्य की सहायता का आश्रय लेती है। वैज्ञानिक व औद्योगिक क्रांति ने भी अर्थव्यवस्था के संकेन्द्रण व इजारीकरण के मजबूत करने में सहायता दी है। उत्पादन का समाजीकरण ऐसे स्तर पर पहुँच गया है जब राज्य आर्थिक-जीवन के सभी पक्षों में प्रत्यक्ष भाग लेना जरूरी समझने लगा है। राज्य के इस प्रकार शामिल हुए बिना आधुनिक उत्पादक-शक्तियाँ अधिक समय काम नहीं कर सकती।

दूसरा महत्वपूर्ण कारक बढ़ता हुआ वर्ग-मुद्द है जो साम्राज्यवादियों को चाल चलने तथा मजदूर वर्ग व समग्र रूप से मेहनतकों को कुछ छूट देने के लिए विवश करता है। मेहनतकों पर दबाव डालने के लिए पूँजीपति-वर्ग राज्य के विधानों का प्रयोग करने की कोशिश करता है और अर्थव्यवस्था के राजकीय नियंत्रण के द्वारा वर्ग-विरोधों पर परदा डालने तथा अराजकता, संकट व बेरोजगारी जैसी सामाजिक रूप से खतरनाक परिघटनाओं को रोकने की कोशिश करता है।

साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का अंत, इजारेदार पूँजीवाद के राज्य-इजारेदार पूँजीवाद के रूप में विकास को तीव्र करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। विदेशी अल्पतंत्र विकासशील देशों में अपनी आर्थिक सर्वोच्चता को बनाये रखने और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को दबाने के लिए राज्य-तंत्र का बढ़ता हुआ

व्यापक उपयोग कर रहा है। अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य साम्राज्यवादी देश औद्योगिक रूप से अविकसित अनेक देशों में अभी भी अपने सैनिक व सैनिक अड्डे बनाये हुए हैं और 'आर्थिक-सहायता' के बहाने से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं।

विश्व-समाजवादी व्यवस्था के उदय ने साम्राज्यवाद की स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया है। राज्य-तंत्र से सहायता प्राप्त करके वित्तीय अल्पतंत्र कुछ देशों के पूँजीवाद से अलग हो जाने से साम्राज्यवादी विश्व पर पड़े नकारात्मक परिणामों को निम्नप्रभावित करने, समाजवाद के मुकाबले आर्थिक प्रतिযোগिता में डटे रहने, उत्पादन-धरों को तेज करने और कुल मिलाकर पूँजीवादी व्यवस्था को बचाये रखने के लिए अपनी सारी क्षमता को सामंजस्य करने की कोशिश कर रहा है।

2. राज्य-इजारेदार पूँजीवाद के प्रमुख रूप

राज्य-इजारेदार पूँजीवाद के सुस्पष्ट सङ्गण हैं जो प्रत्येक देश-विशेष की ऐतिहासिक रूप से विद्यमान आंतरिक व बाह्य-दशाओं पर निर्भर होते हैं। लेकिन अब हमें अधिकतर देशों में अंतर्निहित प्रमुख रूपों की विवेचना करनी चाहिए।

राज्य-स्वामित्व और राज्य-स्वाधार में बुद्धि—पूँजीवादी-व्यवस्था इन्हीं के भीतर राज्य-स्वामित्व का विकास और उसके दुर्दुर्करण के विविध रूप राज्य-इजारेदार पूँजीवाद के विकास की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। किन्तु राज्य-स्वामित्व का क्षेत्र समान नहीं है तथा आंतरिक व बाहरी कारकों पर निर्भर होता है। फिर भी, सामान्य रूप से मुख्यतः औद्योगिक, परिवहन, बैंकिंग तथा अन्य उद्यमों के राज्य-स्वामित्व के रूप में प्रगट होने हुए, पूँजीवाद के आम-संगठ के दौरान राज्य-स्वामित्व बढ़ा है। ब्रिटेन में कोयला उद्योग, रेल, गैस-व्यवस्था और ऊर्ध्व-नीच राज्य के अधीन हैं। फ्रांस में धूम उत्पादन के लगभग 15 प्रतिशत का उत्पादन सरकारी क्षेत्र करता है—उद्घरण उद्योग का 80 प्रतिशत, लगभग सारा कोयला उद्योग और ऊर्ध्व उत्पादन राज्य के हाथों में केन्द्रित है। पश्चिमी जर्मनी में लगभग 25 प्रतिशत केन्द्र-पूँजी राज्य के पास है।

पूँजीवाद के अन्तर्गत राज्य-स्वामित्व अपनी इसी पूँजीवादी-प्रवृत्ति बचवा करती सामाजिक आर्थिक प्रवृत्ति को मजबूत करता है और यह किसी भी तरह शोच-स्वामित्व नहीं है। पूँजीवाद के अन्तर्गत राज्य-स्वामित्व का चरित्र पूँजीवादी राज्य के बर्तमान सामाजिक के द्वारा निर्धारित होता है। यह सामान्य में पूँजीवादी सराज होता है क्योंकि यह राज्य-स्वामित्व का प्रयोग करने वाले पूँजीपति वर्ग के अन्तर्गत होता है और टकराती श्रम के शोषण के माध्यम के रूप में काम करता है।

राज्य-इजारेदार स्वामित्व का निर्माण उत्पादन के साधनों के मजदूरीकरण के

द्वारा होना है। इसका निर्माण राज्य द्वारा प्रदत्त धन से नये उद्योगों की स्थापना, कुछ उद्यमों अथवा संपूर्ण उद्योग के राष्ट्रीयकरण और इसके साथ राज्य द्वारा पूँजी-वादी स्वामित्व की कपनियों के शेयर खरीदने से होता है।

राज्य-बजट में वित्त-निवेश के माध्यम से नये उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का बड़ा हुआ परिमाण इजारेदारी हितों का खटन नहीं करता है। इसके विपरीत राज्य-संपत्ति इजारेदारों को साम्य पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय आय एवं अतिरिक्त मूल्य के पुनर्वितरण के एक हथियार के रूप में प्रमुख भूमिका अदा करती है। जैसा पहले बताया गया है, राज्य प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में निवेश करता है जिन्हें विशेष रूप से बड़े निवेश की जरूरत होती है और जिनसे बहुत निम्न भविष्य में आय की संभावना नहीं होती है। इससे भी आगे, जब शोध व विकास की बेहद महँगी परियोजनाएँ एक बार पूरी हो जाती हैं और जमा पूँजी के रूप में लगाये गये आरम्भिक निवेश की क्षति-पूर्ति हो जाती है तो अनेक मामलों में, राजकीय उद्यम बहुत अनुकूल शर्तों पर इजारेदार पूँजीपतियों को सौटा दिये जाते हैं अथवा ठेके पर दे दिये जाते हैं। परमाणु एवं अतिरिक्त उद्योग और आज के ऊर्जा उद्योग के विकास का प्रतिमान यही है।

सरकारी निवासों द्वारा निजी निगमों के शेयरों की खरीद के द्वारा भी राज्य संपत्ति प्राप्त करता है। इसके समानांतर दूसरी प्रवृत्ति भी है—राजकीय निगमों द्वारा निजी उद्यमों को अपने शेयरों की बिक्री। राज्य एवं इजारेदारों के समुक्त उद्यम भी दिखायी देते हैं और इससे यह तथ्य स्पष्टता से प्रमाणित होता है कि उत्पादन के साधनों का राज्य स्वामित्व अनिवार्यतः पूँजीवादी स्वामित्व है।

प्रायः मालिकों की क्षति-पूर्ति करते हुए निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण एक बुरा तरीका है जिससे राज्य संपत्ति उत्पन्न होती है। आधुनिक सुधारवाद के वैचारिक समर्थक यह समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूँजीवादी उत्पादन स्वयं के सन्नि के भीतर राष्ट्रीयकरण समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए तत्प्राकृतिक रूप में राह खोलता है। लेकिन वास्तव में, कुछ उद्यमों अथवा समस्त उद्योग का भी पूँजीवादी राष्ट्रीयकरण पूँजीवादी-व्यवस्था के चरित्र को नहीं बदलता है। उद्यम राज्य-पूँजीवादी हो जाते हैं और उनका सामाजिक सारतत्त्व रती भर नहीं बदलता क्योंकि विरोधमूलक वर्ग-संबंध और पूँजीवादी-शोषण समाज में जारी रहता है।

पूँजीवादी राष्ट्रीयकरण प्रायः इजारेदारों के तात्कालिक अथवा दीर्घकालिक हितों से जुड़ी आवश्यकताओं का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए प्रयोगिकी पिछड़ेपन के कारण दिवालियापन का सामना करने वाले और प्रतियोगिता में असमर्थ हो जाने वाले उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण बढ़ते हुए सामाजिक अंतर्विरोध, युद्ध या आर्थिक-संकट के समय मजदूर-वर्ग के दबाव का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन अंतिम रूप से पूँजीवादी—राष्ट्रीय-

करण की मूलभूत प्रेरक शक्ति इजारेदारी—आधिपत्य की व्यवस्था को मजबूत करना, निजी संपत्ति की वित्तीय मारों व दिवानियापन से रक्षा करना और कुन मिलकर पूँजीवादी-व्यवस्था की स्थिति को दृढ़ करना है। दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा कुछ अन्य पश्चिमी यूरोप के देशों में राष्ट्रीयकरण इन्हीं उद्देश्यों की ओर निर्दिष्ट था।

ऐसा होने पर भी, इजारेदार पूँजीपति वर्ग भीतर में सरकारी-क्षेत्र की वृद्धि को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। इजारेदार व्यापक राष्ट्रीयकरण से भयभीत है (जैसे कि उन्हें यह भय है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में अन्य तरीकों से बनी हुई राज्य-संपत्ति के साथ प्रतियोगिता में प्रबल सिद्ध हो सकती है) क्योंकि उत्पादन के साधनों का व्यापक समाजीकरण पूँजीपति वर्ग की आवश्यकता को सिद्ध करता है। इसलिए पूँजीवाद के अंतर्गत राज्य-संपत्ति, चाहे वह किसी भी प्रकार उत्पन्न हो, स्वामित्व का सामान्य प्रचलित रूप नहीं बन पायेगी।

इस मान्यता का कि इजारेदारों को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत क्षेत्र का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, यह अर्थ नहीं है सर्वहारा वर्ग को राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए। पूँजीवादी समाजीकरण में इन्तारमक अंतर्विरोध निहित हैं। एक तरफ इजारेदार पूँजीपति वर्ग अपनी सर्वोच्चता को मजबूत करने व मेहनतकशों पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीयकरण का उपयोग करता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण वास्तव में उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के सिद्धांत को हानि पहुँचाता है और यह दिखलाता है कि बिना पूँजीपतियों के भी सामाजिक विकास संभव है। इसी कारण, पूँजीवादी देशों में कम्युनिस्ट तथा मजदूर दल जनवादी राष्ट्रीयकरण (भासिकों की हरेखाना विधे बिना और मजदूरों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के साथ प्रबंध का राजकीय नियमों को हस्तान्तरण) के बारे को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के राष्ट्रीयकरण की माँग भी समाजवादी नहीं है (यद्यपि प्रगतिशीलता की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है) क्योंकि इसने पूँजीवादी व्यवस्था की प्रकृति नहीं बदलती है।

पूँजीवादी राज्य द्वारा राष्ट्रीय आय के भाग का वितरण और पुनर्वितरण—राज्य-इजारेदार पूँजीवाद के विकास के साथ पूँजीवादी राज्य राष्ट्रीय आय का बड़ा हुआ हिस्सा पाने लगता है। राष्ट्रीय आय के इस बड़े हिस्सा का, बड़े-व्यापार को लाभ पहुँचाने के लिए राज्य द्वारा पुनर्वितरण पूँजीवादी पुनरुत्पादन का एक विशेष मसल और इजारेदारों को समृद्ध करने का एक प्रमुख तरीका बन गया है। राष्ट्रीय-आय के पुनर्वितरण के तंत्र में सबसे प्रमुख तत्व राज्य खर्च है जो विभिन्न क्षेत्रों से (प्रमुख रूप से करारोपण के द्वारा) मौद्रिक-साधनों का संचय करता है।

राज्य-खर्च के माध्यम ॥ राष्ट्रीय आय ने पुनर्वितरण के लिए आधिप उतो-

सबसे अर्थान् इजारेदारों को विभिन्न प्रकार के अनुदानों एवं आर्थिक सहायता भी व्यापक प्रयोग दिया जाता है। प्रत्यक्ष सहायता के साथ-साथ इजारेदारों राज्य-बजट में अत्यल्पतः भी—मुख्य रूप से नये उपकरण पर कर-रियायत, शीघ्र हुए धनित्र-समाधनों पर करीयता कम के आधार पर करारोपण, व्यापार-हित उद्योग, उत्पादों की आपूर्ति से पहले अक्षिप्त भुगतान आदि के रूप में अनुराग प्राप्त करते हैं। राज्य-शोध एवं विज्ञान परियोजनाओं के लिए भी बड़े स्तर पर वित्त-व्यय करवा जाता है। राज्य निजी निगमों द्वारा वैज्ञानिक शोध, जिसमें सैन्य-शोध भी शामिल है, में भी भारी मात्रा में निवेश करता है। कमस्वरूप इजारेदारियों की तकनीक, निपुणता और वैज्ञानिक उपसम्पत्तियों का अधिकांश मूल्य चुकाने के लिए मोचनविधि के प्रयोग का अवसर अपने लिए प्राप्त कर सकती है।

अधिकांश राष्ट्रीय-आय के व्यय की व्यवस्था करने हुए पूँजीवादी देशों की सरकारें राज्य-बजट द्वारा विनीय मसाधनों का व्यापक पुनर्वितरण करती हैं। मजदूर तथा छोटे स्तर के वस्तु-निर्माता जो कुछ पैसा करते हैं और जो कर के रूप में राज्य-बजट में आता है, उसका एक बड़ा भाग इजारेदारियों के लिए अनिवार्य लाभ का स्रोत बन जाता है।

अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण—युद्ध के बाद आर्थिक सैनिक-व्यय बहुत से पूँजीवादी देशों की विशेषता रही है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा सैन्यीकरण पूँजीवाद के आम-संवत के बहुरा होने का सदस्य है। यह विश्व-समाजवादी व्यवस्था के विकास, साम्राज्यवाद की उपनिवेशी-व्यवस्था का पतन और विश्व के क्रांतिकारी व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में आए उभार के परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी-आधिपत्य क्षेत्र के सिकुड़ने की प्रतिक्रिया है। पूँजीवादी देशों में अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण को तेज करने के लिए, राजनैतिक स्थितियों के निर्माण को प्रति-क्रियावादी केन्द्रों द्वारा पालित-पौषित 'शीत-युद्ध' के वातावरण ने प्रोत्साहित किया।

अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण राज्य-इजारेदार पूँजीवाद की व्यवस्था का और आगे विकास करता है। प्रमुख साम्राज्यवादी देशों में इस व्यवस्था के नाभिक केन्द्र सैन्य-औद्योगिक-समूह हैं जिनमें सैनिक-उत्पादों का निर्माण करने वाली इजारेदारियाँ, सैन्य-शक्ति के प्रतिनिधि, राज्य-संघ के उच्च-अधिकारी, सैनिक-शोध व विकास में जुड़े कुछ बुद्धिजीवी, मजदूर-संघों के कुछ नेता आदि शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण का उत्तम पर गहरा तथा प्रतिकूल प्रभाव होता है। सैनिक क्षेत्र का विकास अर्थनीतियों द्वारा नहीं, सैनिक एवं राजनैतिक कारणों से निर्धारित होता है। यह विकास अनिवार्यतः अग्रमान व अनियमित होता है और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को अस्थिर करता है। आम तौर से उन साम्राज्यवादी देशों में आर्थिक-विकास की दर न्यून होती है, सैनिक व्यय जिनके सफल

राष्ट्रीय उत्पाद के बड़े हिस्से का उपयोग कर लेता है।

सैन्यीकरण का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य इजारेदार पूर्वी लिए भारी मुनाफ़ा निश्चिन करना है। सैन्य-औद्योगिक निगमों द्वारा प्राप्त किये मुनाफ़े की औमन-दर, अन्य गभी निगमों द्वारा प्राप्त औमन मुनाफ़े की काफी ऊँची है। अमेरिका के वित्तीय अधिकरण के सेवा के अनुसार निर्माण-उद्योग में मुनाफ़े का कुल मानक 20 प्रतिशत की सीमा में घटता-बढ़ता रहा जबकि उसी समय सैनिक ठेकों पर काम करने वाले निगमों ने 100 प्रतिशत तक मुनाफ़ा कमाया।

साम्राज्यवादी देशों की सरकारें सैन्यीकरण का प्रयोग आर्थिक बिलाम को प्रभावित करने वाले उपकरण के रूप में करती हैं। सैनिक तकनीक बहुत जल्द पुरानी हो जाती है। इसलिए शस्त्रों का सगमम लगाना पुनर्स्थापन जरूरी होता है। इसमें सैन्य-औद्योगिक निगमों की ओर ठेकों तथा विस्मयकारी मुनाफ़ों का नियमित प्रवाह बना रहता है।

अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण आर्थिक स्थिति और औद्योगिक चक्र को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है। सैनिक-उत्पादन में सरचनात्मक परिवर्तन तथा उसका एव उसके अनुकूल शस्त्र-बाजार का विस्तार व संकुचन आर्थिक-चक्र की वित्तीय अवस्थाओं के आगमन, प्रकृति और दीर्घता को प्रभावित करता है। यद्यपि ये परिवर्तन पूँजीवादी पुनरुत्पादन के राष्ट्रीय विकास के स्वतः प्रवर्तित नियमों को रद्द नहीं करते हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण एक ऐसा कारक है जो पूँजीवाद के प्रमुख अंतर्विरोध—उत्पादन की सामाजिक प्रकृति तथा उसका फल प्राप्त करने के निजी पूँजीवादी रूप के बीच का अंतर्विरोध—को और अधिक तीक्ष्ण व गहरा बनाता है। उस प्रसंग में उत्पादन तथा उपभोग के बीच बढ़ती विसंगति ध्यान देने योग्य है। उच्चतर सैनिक-धन्य का परिणाम उच्चतर कर होते हैं और यह व्यय मेहनतकशों के उपभोग में बाधा डालता है, कुछ मामलों में तो उसमें पूर्ण हाथ भी करता है। भौतिक संसाधन व मानव-शक्ति के काफी अंश का अनुप्रेषण लोक-आवास, परिवहन, संचार की जरूरतों को सतुष्ट करने, पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था में उन्नति की सम्भावनाओं को संकुचित करता है। इसी वजह से अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण सामाजिक सुरक्षा को क्षति पहुँचाता है और लोक-सेवकों के वेतनों को कम करता है।

सैनिक व्यय की पूर्ति करने के लिए राज्य कागजी-मुद्रा की स्फीति-मात्रा में निकासी सहित अनेक तरह के मौद्रिक-स्रोतों का उपयोग करता है। सैन्यीकरण और मुद्रा की तैयारियाँ साम्राज्यवादी देशों के राज्य-बजटों एवं भुगतान-संतुलन में घाटा होने के प्रमुख कारण हैं। सैन्यीकरण मौद्रिक-वित्तीय संकट को भी बढ़ाता है। यह अबाधित शस्त्र दौड़ की—जो सैनिक-उत्पादन की मात्रा को विराट रूप

मे बढ़ाती है—कीमत और पूँजीवाद के क्षय की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का राज्य-इजारेदारी नियंत्रण—यहाँ हमारा आशय आर्थिक-संकट को हल्का करने, आर्थिक-विकास की दरो को स्थिर करने व बढ़ाने, उत्पादन के संकेन्द्रण को तीव्र करने, अर्थव्यवस्था में सरचनात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने और निश्चित सामाजिक-समस्याओं से निपटने के लिए किए गए सरकारी उपायों के समस्त समूह से है।

दोनों महायुद्धों के समय अर्थव्यवस्था का बड़ोर राज्य-नियंत्रण प्रभावी था। किन्तु यह केवल युद्धकालीन उपाय नहीं था, दोनों महायुद्धों के बीच के समय में भी (विशेष रूप से 1929-33 के आर्थिक-संकट के समय) पूँजीवादी देशों में अर्थ-व्यवस्था का राज्य नियंत्रण मौजूद था। हाल के दशकों में साम्राज्यवादी देशों के आर्थिक विकास में यह स्थायी उपादान रहा है।

आधुनिक विश्व में राज्य-इजारेदारी नियंत्रण का क्षेत्र और गहराई दोनों बढ़ गये हैं। अधिकांश साम्राज्यवादी देशों में आर्थिक-नियंत्रण के विरोध-निकाय और संस्थाएँ काम कर रही हैं। नियंत्रण के बहुत से उपाय सीधे उत्पादन की ओर लक्षित हैं तथा वे संचय व उपभोग के बीच संबंधों और सामाजिक-आर्थिक आधार-भूत ढाँचे के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं।

राज्य-इजारेदारी-नियंत्रण को स्थापित करने के अनेक उपाय हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उत्प्रेक्षक राजकीय निवेश है। इन निवेशों में कोई भी राजकीय-निर्माण उद्योग, कच्चा काल व ऊर्जा-संसाधनों के विकास, यातायात, आवास व नगरीय निर्माण के लिए निवेश और पिछले दो दशकों में शोध व विकास के लिए निवेश को छूट सकता है। सारे साम्राज्यवादी देशों का एक लक्षण कुल निवेश में राज्य का हिस्सा बढ़ना है। राज्य संस्थाओं और कम्पनियों की मँग निजी निवेश की मात्रा तथा दिशा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। इसके अलावा प्रायः राज्य विविध प्रकार के कर लाभ, बड़े हुए मूल्य-ह्रास-भक्त आदि के द्वारा निजी निवेश को प्रोत्साहन देता है।

कृषि-उत्पादों की मँग, आपूर्ति तथा कीमतों को नियमबद्ध करके और फिर कृषि-उत्पादन के ढाँचे पर इसके प्रभाव के माध्यम से राज्य भी नियंत्रक-गति-विधियों का कृषि-क्षेत्र में भी विस्तार होता है। कृषि-क्षेत्र में उत्पादन व पूँजी के संकेन्द्रण को प्रोत्साहित करके पूँजीवादी राज्य प्रायः कृषि योग्य भूमि के आकार को कम करने की नीति पर चलता है। कृषि-मूल्यों के एक निश्चित-स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य-संबन्धन किसानों से उनका अतिरिक्त उत्पादन खरीद लेते हैं। वे कृषि तथा पशु-पालन में सरचनात्मक परिवर्तन के लिए वित्त-व्यवस्था करने के अनेक तरीके काम में लाते हैं और भूमि-प्रबन्ध के प्रश्नों में भी हस्तक्षेप करते हैं। कुल मिलाकर कृषि-क्षेत्र में राजकीय-उपायों की व्यवस्था उत्पादन के

साधनों के निजी स्वामित्व के आधारों को प्रभावित नहीं करती है। वह अंगरक्षणा और प्रतियोगिता को समाप्त नहीं कर सकती जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अनिवार्य गुण-धर्म हैं।

सांघाज्यवादी देशों की सरकारें सामाजिक-आर्थिक अनिवार्यताओं के कारण अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नियोजित करती हैं। वैज्ञानिक प्रौद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादक-शक्तियों का बढ़ा हुआ समाजीकरण, पूँजीवादी पुनरुत्पादन के अंत-विरोधों में और अधिक वृद्धि तथा दो विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष—ये सब विकास कार्यक्रमों को पूरा करने एवं उनका विस्तार करने की जरूरत उत्पन्न करते हैं। इजारेदार पूँजीपतियों की रणनीति का भी निश्चित महत्व है जो बढ़ते हुए सामाजिक द्वन्द्वों की स्थिति में अपनी सर्वोच्चता को इस तरह के उपायों से बनाये रखने की कोशिश करते हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का नियोजन आर्थिक जीवन का एक स्थायी उपादान बनता जा रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति की दरो को स्थिर बनाने व ऊपर उठाने के लिए पूँजीवादी पुनरुत्पादन को प्रभावित करना, औद्योगिक सतुलन प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना आदि है। दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से निवेश परियोजनाओं और साथ ही भावी अनुमानों को बनाते समय राष्ट्रीय लेखाविधि तथा निवेश व निर्गम सार-णियों की प्रणाली और जटिल समष्टि अर्थसांस्थीय प्रतिमानों का व्यापक प्रयोग किया जाता है।

राज्य-इजारेदार कार्य नियोजन को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नियोजन के समान नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों की सामाजिक-आर्थिक आधार-भित्ताएँ पूरी तरह भिन्न हैं। पूँजीवादी देशों में कार्य-नियोजन का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थ-व्यवस्था के केवल राजकीय क्षेत्र पर होता है। जहाँ तक निजी कंपनियों का संबंध है, सरकार का आर्थिक कार्य-नियोजन सिर्फ अनुमति के रूप तक सीमित रहता है। वह किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं होता। पश्चिमी यूरोप में आर्थिक विकास के अधिकांश स्वीकृत कार्यक्रम कभी भी संपूर्ण रूप में पूरे नहीं हुए। निजी स्वामित्व और मुनाफे की खोज, जो पूँजीवाद की प्रेरक शक्तियाँ हैं, वास्तविक वैज्ञानिक नियोजन को बाधित करती हैं जो कि विभिन्न उद्योगों के बीच तथा समग्र अर्थ-व्यवस्था में भी सही सतुलन स्थापित कर सकती है।

राज्य-इजारेदारी नियंत्रण और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का कार्य-नियोजन अनिवार्यतः वर्गीय-प्रकृति के हैं। वे सबसे पहले कुल मिश्रकर इजारेदार पूँजीपतियों के हितों को पूरा करते हैं और व्यवहार में बहुधा उनका प्रयोग मेहनतकों के जीवन-स्तर व अधिकारों पर प्रहार करने के लिए किया जाता है। राज्य-इजारेदारी नियंत्रण पूँजीवाद में अंतर्निहित संकट तथा उसकी अन्तर्गत पद्धति का अंग

नहीं कर सकता और न ही वह पूँजीवाद की अनवरत आर्थिक-वृद्धि को धुनिश्चित कर सकता है क्योंकि वह पूँजीवाद के स्वतः प्रसूत चरित्र एवं उत्पादन के विषम अनुपाती विभाज को समाप्त नहीं कर सकता। वह पूँजीवादी समाज के उन सामाजिक अंतर्विरोधों को सुसज्जाने में भी असमर्थ है जो उग्र होकर राज्य को गिरा, मजदूरों के लिए विशेष प्रशिक्षण, 'शरीबी के विरुद्ध युद्ध' आदि उपाय अपनाने को प्रेरित करने हैं। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होने का तथ्य यह बतलाता है कि आधुनिक पूँजीवाद की गतियाँ अब इस व्यवस्था के उत्पादन संबंधों की प्रोब्लेम्स की शीर्षा के अनुकूल नहीं रह गई हैं और आर्थिक संगठन के अधिक प्रगतिशील समाजवाद विद्वानों की दृष्टि में परिवर्तन चाहती है।

3. राज्य-इजारेदार पूँजीवाद और समाजवाद के लिए परिस्थितियों का निर्माण

उत्पादक-शक्तियों का विकास स्वाभाविक रूप में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जब पूँजीवादी उत्पादन अधिक-से-अधिक समाजीकृत हो जाता है। राज्य-इजारेदार पूँजीवाद इस प्रक्रिया को तेज करता है। उत्पादन के सर्वेक्षण को प्रोत्साहन, सरकारी क्षेत्र का विस्तार और राष्ट्रीय आय के अधिप्राधिक प्रशिक्षण का केंद्रित उपयोग पूँजीवादी पुनरुत्पादन को प्रभावित करता है। ये सब साफ-साफ समाजीकरण के विभिन्न घटक हैं। इस बीच लाभ का अधिग्रहण निजी ही बना रहता है। लाखों-करोड़ों व्यक्तियों के श्रम में उत्पादित संपदा का अधिवांश भाग इजारेदार पूँजीवति-वर्ग द्वारा हृदय लिया जाता है जबकि समाजीकृत उत्पादन की वस्तुनिष्ठ आवश्यकता यह होती है कि वह संपदा समग्र रूप में समाज की सम्पत्ति बन जाये। इस प्रकार पूँजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया स्वयं अनिवार्य रूप से पूँजीवादी-व्यवस्था के विनाश की आवश्यकता के परिधाम तक पहुँच जाती है।

लेनिन ने राज्य-इजारेदार पूँजीवाद का विश्लेषण किया और यह बताया कि पूँजीवादी-उत्पादन के समाजीकरण के समय आदिश-जीवन को नियंत्रित करने वाले राज्य-जब का जाल विकसित होता है। इस तरह का उपयोग मजदूर-वर्ग समाजवादी-उत्पादन को संगठित करने के लिए कर सकता है। लेनिन ने राज्य-इजारेदार पूँजीवाद में इस तथ्य का भारी सादय देखा कि पूँजीवादी-व्यवस्था समाजवादी जाति के लिए घुरी तरह परिपक्व हो चली है और इसमें उन्होंने अंतिम ऐतिहासिक महत्त्व का यह निष्कर्ष निकाला—“राज्य इजारेदार पूँजीवाद समाजवाद की परिपुर्ण औद्योगिक तैयारी है, समाजवाद की देहरी है, इतिहास की नर्सरी

पूँजीवादी राजनीति और विचारधारा का बढ़ता हुआ संकट

पूँजीवाद के आम-संकट का गहरा होना, समग्र राजनैतिक प्रतिक्रियावाद की अभूतपूर्व तीव्रता, पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं की अरबीइति और पूँजीवादी विचारधारा के गहन संकट के रूप में प्रकट होता है।

1. पूँजीवादी देशों में बढ़ा हुआ राजनैतिक प्रतिक्रियावाद

पूँजीवाद के आम-संकट के समय पूँजीवादी देशों में राजनैतिक प्रतिक्रियावाद का तेज हो जाना, बार-बार होने वाली महत्वपूर्ण परिघटना है। अगली सशोष्णता को बनाये रखने के लिए इन्हें इन्हें पूँजी मालिकता को उन जनवादी अधिकारों से बचाने की कोशिश करती है, जो मजदूर-वर्ग की अनेक पीढ़ियों के दृढ़-निश्चयी सपनों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए थे। पूँजीवाद के आम-संकट के अंतर्गत राजनैतिक प्रतिक्रियावाद की उभरता प्रजातन्त्र-विरोधी व क्रांतिवाद सामानों के रूप में पूरी तरह प्रकट होती है।

प्रजातन्त्र में प्रतिक्रियावाद की और परिवर्तन साम्राज्यवाद की चेतना व विवेक, दोनों ही नीतियों की विशेषता है। चेतना नीति में प्रतिक्रियावादी रीति विदेशनीति में भी आकाश-दिशा को निर्धारित करती है। यही यह जान है जिसमें कोई भी साम्राज्यवाद के आन्तरिक व बाह्यी कार्यों में अविभाज्य सम्बन्ध, जो इन्हें इन्हें पूँजी के माध्यम से अनुसारित निर्धारित होता है, को पटकाव लगता है। रीति में निष्ठा है—चेतना व विदेशनीति, दोनों में साम्राज्यवाद प्रजातन्त्र के उन्मूलन का तथा प्रतिक्रियावाद की ओर उन्मुख होने का प्रयास करता है। इस अर्थ में साम्राज्यवाद विदेश-संकट में प्रजातन्त्र के साम्राज्यवाद का निषेध है, जहाँ प्रजातन्त्र का

निवेष्ट...¹

पूँजीवाद के आम-संकट के साथ दृजारेदार पूँजीपति वर्ग में बढ़ती हुई प्रजा-तन्त्र-विरोधी आकांक्षाओं का विकास हुआ। इसका कारण यह था कि सर्वहारा और पूँजीपति वर्ग के बीच अंतर्विरोध उच्च बिंदु तक पहुँच गया था और उसने पूँजीपति वर्ग की सर्वोच्चता के लिए सीधा खतरा उत्पन्न कर दिया था। साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग पूँजीवादी प्रजातन्त्र के पुराने तरीके से अब अधिक समय शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पूँजीवादी प्रजातन्त्र तथा संसदवाद को भाँसो कम करना अथवा पूरी तरह भट्ट करना शुरू कर दिया। सेनिन ने लिखा है कि पहले महापुद्ग की विशेषता थी—“...पूँजीवादी संसदवाद और पूँजीवादी प्रजातन्त्र के पतन की शुद्धता...”² यह वास्तव में राजनीति तथा विचारधारा के क्षेत्र में पूँजीवाद के आम-संकट की शुद्धता थी।

पूँजीवाद के आम-संकट के दौरान साम्राज्यवादी पूँजीपति-वर्ग द्वारा संसदवाद तथा पूँजीवादी प्रजातन्त्र के स्वाय की इच्छा, तीव्र वर्ग-संघर्ष, पूँजीवाद की स्थिति में बढ़ता हुआ कटान, और समाजवाद से (जिसकी अस्तित्व बढ़ती आ रही है) भय का परिणाम है। इन परिस्थितियों में साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के बढ़ते विनाश को पूँजीवादी-प्रजातन्त्र के तरीकों से अधिक समय नहीं रोक पाता। क्रासीवाद प्रतिक्रियावाद का सर्वाधिक भयानक परिणाम है। यह दृजारेदार पूँजीपति वर्ग की तानाशाही का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी रूप है जिसे पूँजीपति वर्ग मेहनतकों के क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के एक साधन के रूप में समाज पर थोपता है। यह पूँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा के बीच सर्वाधिक तीव्र संघर्ष के दौरान उत्पन्न होता है जबकि पूँजीपति वर्ग पुराने संसदीय तरीकों से अधिक समय तक अपनी सत्ता बनाये रखने में असमर्थ होकर आतंकवादी तानाशाही, मजदूर वर्ग व समस्त जनवादी आंदोलन के दमन और उत्तेजक सामाजिक लफ्फाड़ी का सहारा लेता है। क्रासीवाद साम्राज्यवादी देशों के वित्तीय अल्पतन्त्र के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी व आक्रमक-सेनों की खुली तानाशाही है। यह धरेलू मामलों में जनवादी अधिवार व स्वतंत्रताओं को छत्त करके पूँजीवादी-व्यवस्थाओं को बनाये रखने का प्रयत्न करता है और अंधराष्ट्रवादी विदेशनीति का अनुसरण करता है। क्रासीवादी तानाशाहों की आंतरिक नीति के मूलतत्त्व कम्युनिस्ट एवं मजदूर दलों की समाप्ति, मजदूर-संघ व अन्य प्रगतिशील जनवादी संघठनों का नाश और आधारभूत पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं को नष्ट करना है।

1. वी. आई. सेनिन, 'आत्मन्याय का विधुष और साम्राज्यवादी वर्चस्व', संकलित रचनाएँ, भाग 23, पृ. 43 (बन्नेको में)।

2. वी. आई. सेनिन, 'लेनन ने कहा कि हमारे देश में एक राज्य के अन्तर्गत एक राज्य में...'।

पहले बहादुर के बाद नुरो के अधिकारों काय में परिवर्तनी उभार
 कुचनने की कोशिश में हजारेदार पूंजीपति वर्ग ने अनेक देशों में सरकार बना
 बहादुर अधिकारवादी तरीकों, सामाजिक तथा आर्थिकों का बदला दिया। वेदु
 करने के बहादुर मरु कर दिने बने, बाने विरोध को निर्धमता से दबा दिया व
 बहादुर मरु बहादुर अधिकार बढ़ कर दिने बने, जनताओं को पूरी तरह हजारे
 पूंजी के शोषणकारी बाजों के अधिकार कर दिया गया, समाज के सर्वश्रेष्ठ लोगों
 के व हजारे अधिकारों में बहादुर दिया गया और आर्थिक बहादुरा विरुद्ध हो गई

कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग कमरे में नियुक्ति हुई और
अलग अलग विभाग के विशेष महत्व प्राप्त कारिगारी सर्वसाधारण कर्मचारियों की
की तुलना करने के लिए अलग अलग कमरे में नियुक्ति करनी थी। कुछ देनों
कर्मचारियों की अलग अलग विभाग में नियुक्ति करने के आदेशों के द्वारा विभिन्न विभागों
में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति करने का आदेश और कभी
कभी के कुछ कर्मचारियों को अलग अलग कमरे में नियुक्ति करने के आदेशों के द्वारा अलग अलग
कर्मचारियों के अलग अलग कमरे में नियुक्ति करने के आदेशों के द्वारा।

[illegible][illegible]

知、仁、勇三者，天下之達德也。知者，所以居仁由義之方也；仁者，所以成己成物之道也；勇者，所以行其志而無懼者也。三者皆天賦之性，不可離而一者也。

जर्मनी में 1920 के दशक के आरम्भ में क्रासीवादी संगठन प्रबल हुए। 1920 में जर्मनी को राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर पार्टी बनी। जर्मनी के इजारेदार पूंजीपति वर्ग ने नाज़ियों को भारी वित्तीय सहायता दी। 1929-33 के विश्व आर्थिक संकट के दिनों में जीवन-स्तर में भयंकर गिरावट ने नाज़ियों को अपनी उत्तेजक सन्देशवादी में जनगण को (खास तौर में मध्यवर्गीय क्षेत्रों को) प्रभावित करने में सहायता दी। नाज़ियों द्वारा सत्ता पर कब्जे की प्रतिक्रियावादी सामाजिक जनवादी नेताओं के विश्वासघात से भी मदद मिली। 1929-33 के आर्थिक संकट के दिनों में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकांशों के लिए मेहनतकशों के संपर्क तथा वर्गीय अंतर्विरोधों के तीव्र हो जाने में जर्मन-पूँजीवाद के अस्तित्व की ही खतरा उत्पन्न हो गया था। इजारेदार पूंजीपति वर्ग ने अपनी सत्ता को बचाये रखने के लिए वित्तीय पूँजी की आत्मबचाव की सानाशाही स्थापित कर दी। पुनरुत्थानवादी मार्क्सवाद वाले छोटी पूँजी के मामलों में भी जर्मनी में क्रासीवाद का समर्थन किया। इस स्थिति में क्रासीवाद ने मजदूर-वर्ग के क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचल दिया।

1933 में जर्मनी के प्रभावशाली वित्तीय वर्ग तथा विदेशी इजारेदार पूँजी से सहायता पाकर हिटलर के क्रासीवादी दल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और वृषित सानाशाही स्थापित कर दी। जर्मनी में सत्ता पर नाज़ियों द्वारा अधिकार को सिर्फ सामाजिक-जनवादियों के विश्वासघात और मजदूर वर्ग की कमजोरी का चिह्न ही नहीं समझा जाना चाहिए, वह पूँजीपति वर्ग की निर्बलता का भी चिह्न था जो संसदवाद तथा पूँजीवादी प्रभुत्व के पुराने तरीके से अधिक समय शासन करने में समर्थ नहीं रह गया था।

दूसरे महायुद्ध का अंत क्रासीवादी शक्तियों की पराजय से हुआ, लेकिन क्रासीवाद में संपर्क नहीं छोड़ा। अनेक साम्राज्यवादी देशों में वित्तीय अल्पमत ने सशस्त्र अनुचरों की मंडली का संगठन करके तथा उनके चालाकीपूर्ण उपयोग से क्रासीवादी शासनों की स्थापना कर दी। यद्यपि जर्मनी एवं इटली का वृषित क्रासीवाद पराजित हो गया किन्तु बहुत से देशों में क्रासीवादी शासन नये रूपों में पुनर्जीवित होने लगे। कुछ पूँजीवादी देशों में नव-क्रासीवादी संगठन खुले रूप में काम कर रहे हैं।

समाचार-पत्रों के अनुसार पश्चिमी जर्मनी में 100 ॥ अधिक नव-नाज़ी तथा रसिपपदी संगठन काम कर रहे हैं। ये सब 1964 में बने नव-क्रासीवादी जर्मनी के राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल से सम्बन्धित हैं। इसके नेतृत्व का संगठन लगभग पूरी तरह ॥ पूर्व-नाज़ियों से हुआ है। पश्चिमी जर्मनी के पुनरुत्थानवादी एवं नव-नाज़ी शक्तियों के प्रकटा एटोल्क बान बाहेन ने स्वयं को पशुहरार घोषित कर दिया है। आइये धार्यक, साराङ्क-समकाली मित्राङ्क और पश्चिमी की रसिपपदीयों के सम्बन्ध

पर राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल निश्चय ही नव-नाज़ी दल है। यह जर्मन जनतंत्र के साथ निरुद्ध सम्बन्धों के पक्षधर, समाज-शैथिल्य के समर्थक और सो विरोध एवं साम्यवाद-विरोध का विरोध करने वाली प्रजातांत्रिक शक्ति विरुद्ध भौतिक-आत्मिक का प्रयोग करने के लिए सब दक्षिण-पंथी संगठनों का अ करता है। सारे नव-क्रांतीवादी तथा उग्रवादी, जो पश्चिमी जर्मनी में छुपे छुपे रूप में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल के भारों तरफ़ सगठित

इटली में अनेक सक्रिय नव-क्रासिस्ट उग्रवादी संगठन और गुट हैं। उन एक इटली का सामाजिक आन्दोलन (एम० एच० आई०) है जिसकी नीति की कम्युनिस्ट पार्टी को (जो मेहनतकशों के हित में नव-क्रासिस्ट छुनरे के नि समर्थ का नेतृत्व कर रही है) नष्ट करना है। एम० एस० आई० अकेला क्रांति समर्थक संगठन नहीं है—दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संगठन राष्ट्रीय मोर्चा (एफ०) है। इटली में आज क्रासिस्ट-समर्थक संगठन देश में प्रजातांत्रिक शक्ति और गणतांत्रिक सविधान के लिए ख़तरा बन गये हैं। इसी कारण क्रासि समर्थक संगठनों की योजनाओं को विफल करने के लिए इटली की कम्युनिस्ट प व दूसरे वामपंथी दल, प्रजातांत्रिक संगठन और प्रगतिशील जन एक साथ गये हैं।

अमरीका में जान बर्च सोसायटी, कम्युनिस्ट-विरोधी ईसाई-क्रूसेड, या प्रतिरक्षा संघ, अमेरिकन लीजन (सेना), अमेरिकन राष्ट्रपति संघ और ऐसे संगठन सक्रिय हैं। अन्य क्रासिस्ट तत्वों के साथ जान बर्च सोसायटी सामा अमरीकी जन की प्रजातंत्र के लिए भावना के साथ बेशर्मी से छिलवाड़ करती। वे अमरीका की कम्युनिस्ट पार्टी को 'विदेशी-दलाल' कहकर बदनाम करती और यह दावा करती हैं कि साम्यवाद अपने सारतत्त्व में प्रजातंत्र विरोधी है अमरीका में अति दक्षिण-पंथी तत्व सरकार पर शीत-युद्ध को वास्तविक यु में बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। बर्चवादी जैसे क्रासिस्ट गुट छुपे और छु दोनों ही तरीकों से विनाशक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं और अमरीक निगमों द्वारा उनके लिए उदारता से वित्त-प्रबन्ध किया जाता है।

सत्तर के दशक की घटनाओं ने यह दिखाया है कि जब साम्राज्यवाद का संक गहरा होता है और जब प्रतिक्रियावादी, जनवादी एवं क्रांतिकारी शक्तियों के विरु अत्यधिक हिंसारमय दमन के तरीकों का प्रयोग करने के लिए विशेष कठोर प्रयत्न करते हैं, तब क्रांतीवाद की गतिविधियाँ तीव्र होती हैं।

सितम्बर, 1973 में बिनी के वैधानिक रूप में निर्वाचित लोकप्रिय मोर्चा

को उखाड़ कर सैन्य-क्रासिस्ट जनता ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

ने बिनी के देशभक्तों के साथ जो क्रूर आतंकवादी व्यवहार किया है, वह

सत्ते का एक और संकेत है। बिनी की घटनाओं ने यह दिखाया

है कि जैसे ही स्वाधीनता की घोषणा आकांक्षा पूँजीपतियों के वर्गहितो के लिए बनने लगती है, पूँजीपति वर्ग पूँजीवादी-प्रजातंत्र के मुखौटे को फेंक देता है और अपनी सर्वोच्चता की रक्षा तथा जनवर्गों द्वारा प्राप्त लाभों को नष्ट करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की मदद सहित सब प्रकार के तरीके प्रयोग में लाता है।

हम के वर्गों में नव-क्रांतियों की सर्वाधिक व्यापक कार्य-नीति मातृवादी बायीं द्वारा चुनाव, बिना बंधन पैदा करना, आर्थिक-अव्यवस्था को प्रोत्साहन देना जारी रही है। इस कार्य-नीति का एक उद्देश्य चुनाव की परिस्थितियों का लाभ उठाने हुए और 'अवस्था पुनर्स्थापित करने' के बहाने से अतिवादी दक्षिणपंथी शीवराजियों को सत्ता पर कब्जा करने का अवसर देना है। नव-क्रांतियुग संगठनों को (जो या तो पुनर्जीवित हो गये हैं या नये संगठनों की स्थापना की गई है) कार्य करने से रोकने के लिए यदि जनवादी शक्तिर्षा अधिक दृढ़ता से सघर्ष नहीं करती है तो वे संगठन जाति एक चुनाव-नीतिय के लिए सधीर खतरा बन सकते हैं।

विपरीत पूँजी के सर्वाधिक प्रतिनानिधारी तरीकों के राजनीतिक तत्त्व के रूप में, कुछ के बाद के समय में क्रांतियुग संगठनों का उदय को मूल रूप ग्रहण करता है। कुछ समूह हिटलर एवं भगोमिनी के बुद्धि विचारों में खुलेआम विश्वास प्रकट करते हैं जबकि कुछ अन्य पूँजीवादी दलों व संगठनों (सत्ताहीन दलों व संगठनों सहित) में भीतर बुलबुल छुपे रूप में ऐसा करते हैं और उन संगठनों का अपने बस में सामाजीपूर्ण उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। मुद्दोत्तर बात में विशेष रूप से पूँजीवाद के आम-सकट की तीव्ररी अवस्था में, प्रजातंत्र के विरुद्ध शक्तिवादा का हमला सर्वप्रथम व्यवहार एक चुनावी-व्यवस्थाओं के खुले-बंदोबस्त के रूप में विकसित हो रहा है। इसे सभी पूँजीवादी देशों में देखा जा सकता है। कुछ देशों में सरकार की शक्ति को मजबूत करने तथा उसकी शक्ति-विधियों पर विधायिका के नियंत्रण को निर्बंध करने के लिए अनेक सर्वप्रथम बंदोबस्त प्रस्तावित किये गये हैं। कुछ अन्य देशों में व्यवस्था के अधिकारों का अर्थ बनाने के लिए चुनावी कानूनों को संशोधित किया गया है जिसका परिणाम यह हुआ कि हाथी चतुर्धातर दक्षिणपंथी पूँजीवादी दलों के बस में व्यवस्था का भारी झुकाव हुआ है।

जिन विशेष तरीकों में शक्तिवादा प्रजातंत्र का अर्थव्यवस्था करना है, उनमें से एक 'कामगारों के विरुद्ध लड़ने' के बहाने से आक्रमण करना है। क्रांतियुग दलों एवं पार्टी कार्यरी में ऐसा ही हुआ और आज कुछ दलों के देशों के मुकाबले की शक्तिवादा, साम्राज्यवादी क्षेत्र उनका अनुसरण कर रहे हैं। प्रजातंत्र का अर्थव्यवस्था करने के लक्ष्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करना है। शक्तिवादी तरीकों से

में प्रजातंत्र के पक्ष में संघर्ष करने के लिए एक व्यापक-मोर्चा बनाने की कम्युनिस्ट संभावनाएँ उत्पन्न होनी हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि पूँजीवादी गणतंत्र का बेहतर माने पीछे वित्तीय-पूँजी के वर्ग-आधिपत्य के तंत्र को छुपाये रहता है और पूँजीपति वर्ग समस्त प्रजातांत्रिक संस्थाओं का नियंत्रण अपने हितों की दृष्टि से करने का प्रयत्न करता है, लेनिन ने बताया है—“अपनी मुक्ति के लिए पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग के लिए प्रजातंत्र का बहुत भारी महत्त्व है।” मजदूर वर्ग के नेतृत्व में प्रजातंत्र एवं शांति की शक्तियों का मोर्चा साम्राज्यवादी शक्तियों के सामरिक क्षेत्रों की स्थानीय युद्ध न उकसाने, एक नये युद्ध के लिए तैयारियाँ रोकने और अर्थव्यवस्था को नागरिक-आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए विभक्त कर सकता है। यह मोर्चा क्रान्ति प्रतिक्रियावाद को भी रोक सकता है और शांति, राष्ट्रीय स्वाधीनता, जनवादी अधिकार तथा उच्चतर जीवन-स्तरों के कार्यक्रम को क्रियामुक्त करने के लिए साम्राज्यवादी सरकारों को मजबूर कर सकता है।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान कम्युनिस्ट दलों के नेतृत्व में मजदूर वर्ग का आंदोलन साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद के आक्रमण को रोकने और किसान एवं मेहनतकशों के अग्य क्षेत्रों को (जो मजदूर वर्ग के स्वाभाविक साथी हैं) संघर्ष में शामिल करने के लिए जनवादी अधिकार तथा स्वतंत्रताओं का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहा है। मेहनतकश संसद के लिए ऐसे प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो संसद में साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग की प्रतिक्रियावादी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और प्रतिक्रियावादी कानूनों को स्वीकृत होने से रोकेंगे।

मजदूर वर्ग के लिए प्रजातंत्र का महत्त्व केवल इस तथ्य से ही निर्धारित नहीं होता है कि वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में इसका प्रयोग करता है, बल्कि इस तथ्य से भी होता है कि वास्तविक प्रजातंत्र की माँग मजदूर वर्ग के आंदोलन के अंतिम उद्देश्य और वर्ग-आधिपत्य को पूरी तरह नष्ट करने में उसकी ऐतिहासिक भूमिका को पूरा करती है। इस सम्बन्ध में लेनिन ने बताया है—“यह सोचना अतिवादी भूल होगी प्रजातंत्र के लिए संघर्ष समाजवादी क्रान्ति से सर्वहारा का ध्यान हटाने में या इस उद्देश्य को छुपाने, छुंघला कर देने आदि में संघर्ष है। इसके विपरीत, जैसे ऐसा कोई विजयी समाजवाद नहीं हो सकता जो पूर्ण प्रजातंत्र पर हो, उसी तरह प्रजातंत्र के लिए संपूर्ण, लगातार और क्रान्तिकारी सर्वहारा पूँजीपति वर्ग पर विजय के लिए तैयारियाँ भी नहीं कर

करना।¹ प्रजातन्त्र के लिए सघर्ष मजदूर वर्ग की समाजवादी शक्ति के लिए तयार करता है।

रक्षावादी व सामर्थी अवसरवादियों से अलग कम्युनिस्ट तथा मजदूर दल सामाजिक आर्थिक-आध्यात्मिक माँगों तथा उन्नत प्रजातन्त्र के लिए सघर्ष का (समाजवाद के लिए संघर्ष से उसकी तुलना करते हुए) विरोध नहीं करते हैं बल्कि उसे समाजवाद के लिए सघर्ष का हिस्सा मानते हैं। इसीलिए तथा उनकी आर्थिक सर्वोन्नता व राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जो मूलगामी जनवादी पुनर्रचना के बिना, वे व्यापक जनसमूहों को समाजवाद आवश्यकता अनुभव करने में नहीं हुई भाषा में सहायता करेंगे।

2 पूँजीपति वर्ग की विचारधारा का गहरा होता संकट

पूँजीवाद का आम-अवत केवल अर्थव्यवस्था तथा राजनीति को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि विचारधारा और पूँजीवादी समाज में जिंदगी के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। पूँजीपति वर्ग ऐसे विचार प्रस्तुत करने में अब अधिक तय नहीं है जो जनव्य के दिल और दिमाग को जीत सके। पूँजीवादी देशों में बहिष्कृत जनता पूँजीवादी विचार दृष्टि को अस्वीकार कर रहे हैं और पूँजीपति वर्ग की विचारधारा एवं नीति सबट में पड़ रही है।

कुछ पूँजीवादी देशों में, विशेषतः अमेरिका में पूँजीवादी राजनीतिक नेता और मिडिलक्लास दल विचार को स्वीकृत बना रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूँजीवाद का 'चांदी का युग' हो गया है और 'पुराना पूँजीवाद' एक नये 'पूँजीवाद' से प्रतिस्थापित हो गया है। नये पूँजीवाद ने अपने अटमार करने वाले शोषक स्वभाव को त्याग दिया है और अब यह, यह कहा जा सकता है कि 'जनता का पूँजीवाद' एक सर्वोद्योग व्यवस्था' और एक 'प्रचुरता का समाज' हो गया है जिसका उद्देश्य 'असौखिन' एवं बेरोजगारों के हितों की सेवा करना है। अमेरिका के विषय पर विश्व-व्यापक के सी० कार० जे० मानसोन कम देकर कहते हैं—'पूँजीवाद का अपनी बहुत विविध परिभाषा में अमेरिका का इन्हीं में विद्यमान एक गवाम्दी में अविष्कार (जिसे अभी उदय अवस्था में है) नहीं रहा है।'²

अमेरिकन पूँजीवाद की हारणार्थ पूँजीवाद के बढ़ते विरोधमूलक अवरोध तथा इसके अव-अवत की बढ़ती महारथ पर परदा हटाने और इसीसे जारी हुए के

1. सी० कार० जे० मानसोन, 'अमेरिकन राजनीति और समाज के अर्थव्यवस्था का विकास' का अविष्कार।

इस प्रकार श्री १०८ के अर्थ, जबकि समुच्चय उच्चम व्यापक रूप में है, पूँजी के रूप में (विशेष की वही शक्ति से अनुसूचित) स्वाभिव्यक्त का विभाजन विद्यालय क्षेत्र में है। वही वही है। इस पर बहुत पहले ही ध्यान दिया था। पूँजीवादी विचारों के अर्थ है कि समुच्चय-उच्चम उच्चम राष्ट्रीय है, स्वाभिव्यक्त के रूप के रूप में उच्चम का अर्थ है कि उनके अर्थ को रख देने हैं। वे इस तथ्य को भी भूल गए हैं कि उच्चम की उच्चम अर्थों से रूप पर निर्भर होती है।

१. नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (क) नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (ख) नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (ग) नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (घ) नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (ङ) नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

१६६६ ई. में जब कि अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था, तब भी वे बंगालियों को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। वे बंगालियों को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। वे बंगालियों को अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे।

[illegible][illegible]

माधियम को छुटाने के लिए गड़ी जानी है। इजाजतदार पूँजीपति वर्ग सब तरह वह धर्म फैलाने की कोशिश कर रहा है कि मेहनतकश जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब वर्तमान व्यवस्था के अनिवार्य रूपान्तरण के बिना भिन मरना है। अने शोषक व आक्रामक सारतत्त्व को छुटाने के लिए पूँजीवाद अनेक प्रकार की पत्र-गमपत्र, धारणाओं का सहारा लेता है।

‘पूँजीवाद के रूपान्तरण’ की आधारभूमि के रूप में ‘पूँजी के जनवादीकरण’ की कल्पित कथा का उपयोग किया जाता है। पूँजीवादी अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि सार्वजनिक निगम तथा जनता के बीच शेयरों के व्यापक वितरण का अर्थ यह है कि पूँजी का जनवादीकरण हो गया है और सभी शेयरधारी पूँजी के सह-स्वामी हैं तथा लाभभाग प्राप्त करने वाले हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री एडोल्फ बर्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मेहनतकश वास्तव में पूँजीवादी उद्यमों के मालिक हैं और निजी स्वामित्व का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये ‘मिडॉल’ समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच धनराशि तथा मूल्य के आधार पर शेयरों के वितरण की पूरी तरह अपेक्षा करते हैं। इस बात के साक्ष्य हैं कि समस्त शेयरों का दो-तिहाई से अधिक भाग (मूल्य के अनुसार) ऊँची आमदनी वालों, नाम लिया जाये तो पूँजी-पति, बड़े जमींदारों आदि के हाथों में संकेंद्रित है। मजदूरों के पास बड़ी बचत नहीं होती है और जो कुछ संसाधन वे बचा पाते हैं, उसे मुसीबत के दिनों के लिए (आर्थिक रूप से उन दिनों के लिए जब वे बेरोजगार हो जाते हैं) सुरक्षित रखते हैं। बड़े पूँजीपति छोटे व मध्यम शेयरधारकों की क्रोमट पर अपनी पूँजी बटाने के लिए स्टॉक-एक्सचेंज की सट्टेबाजी का चालाकी भरा उपयोग करते हैं।

लेनिन ने इस संबंध में लिखा है—“शेयरों के स्वामित्व का जनवादीकरण जिससे पूँजीवाद क्रुतकों और अवसरवादी तथाकथित ‘सामाजिक जनवादी’ पूँजी के जनवादीकरण तथा छोटे स्तर के उत्पादन के महत्त्व एवं भूमिका के महवृद्ध हो जाने आदि की आशा रखते हैं (या कहें कि वे आशा करते हैं) वास्तव में विनाश अल्प-संख्य की शक्ति में वृद्धि करने का एक तरीका है।” इस प्रकार पूँजी के ‘जनवादीकरण’ और ‘स्वामियों के क्षेत्र विस्तार’ की जगह वास्तविकता में पूँजी-पतियों के एक छोटे समूह के हाथों में पूँजी का केन्द्रीकरण हो रहा है।

‘पूँजीवाद के रूपान्तरण’ के पक्ष में दूसरा तर्क तथाकथित ‘प्रबंध-क्रांति’ का है। यहाँ इसका मतलब यह है कि आधुनिक परिस्थितियों में, पूँजीपतियों ने व्यवस्थापक रूप में अर्थव्यवस्था पर स नियंत्रण छो दिया है—नियंत्रण का भार किराये पर रहे गये (वेतनभोगी—बनु०)

प्राधिकार हो गया है।

आधुनिक पूँजीवाद के अंतर्गत, जबकि संयुक्त उद्यम व्यापक रूप में हैं, पूँजी के भीतर (निवेश की गयी राशि के अनुकूल) स्वामित्व का विभाजन विशाल क्षेत्र में फैल गया है। कार्ल मार्क्स ने इस पर बहुत पहले ही ध्यान दिया था। पूँजीवादी विचारक जो यह कहते हैं कि संयुक्त-स्टाक उद्यम राष्ट्रीय हैं, स्वामित्व के रूप के प्रश्न के स्थान पर प्रबंध के रूप के प्रश्न को रख देते हैं। वे इस तथ्य को भी भूल जाते हैं कि उद्यम की प्रकृति प्रबंध के रूप पर निर्भर होती है।

पूँजीवादी विचारक व पूँजीवादी समाज में प्रबंधक की भूमिका को भी गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट रूप में प्रबंधकों का कोई विशेष वर्ग नहीं है। जो प्रबंध व्यवस्था के नीचे खाले कम में हैं अर्थात् जो भौतिक-उत्पादन में प्रत्यक्ष शामिल होते हैं, वे बेतनभोगी हैं। वे नीति-संबंधी निर्णय नहीं करते हैं और लाभ के बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जहाँ तक शीर्षस्थ प्रबंधकों का सवाल है, वे उद्यम की गतिविधियों का निर्देशन सभी कर सकते हैं जब उनके पास 51 प्रतिशत शेयरों का नियंत्रण हो अर्थात् जब वे पूँजीपति हों।

इसलिए 'प्रबंध-शक्ति' के दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। वे वित्तीय अल्प-संख्य की सर्वोच्चता और उनके बढ़ते मुनाफ़ों को छुपाने के लिए गढ़े जाते हैं।

1960 के दशक में, पूँजीवादी साहित्य में समय-अभिरूपता का सिद्धांत व्यापक प्रचलित हो गया था। यह सिद्धांत अनिवार्यतः जो दावा करता है, वह यह है कि जैसे-जैसे पूँजीवाद तथा समाजवाद का विकास होता है, वे दोनों बढ़ती मात्रा में समान विशेषताओं को अपनाने लगते हैं और दोनों के बीच का अंतर धीरे-धीरे मिटने लगता है। पूँजीवादी विचारक कहते हैं, यह इस तथ्य के कारण होता है कि दोनों व्यवस्थाओं में औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दशाएँ अधिक-से-अधिक समान होनी आ रही हैं। समय-अभिरूपता का सिद्धांत स्वामित्व के भिन्न रूपों—समाजवादी व निजी पूँजीवादी—में उत्पन्न आधारभूत अंतर की उपेक्षा करता है। न तो प्रौद्योगिक विकास और न ही संपन्न व प्रबंध की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस अंतर को समाप्त कर सकती हैं। पूँजीवाद के अतर्गत प्रौद्योगिक विकास व अधिक कार्य-क्षमता का उपयोग अधिक लोहण व्यय, मजदूर वर्ग के बढ़े हुए जोषण में होता है और इसका परिणाम पूँजीवाद के अंतर्घटकों में अधिक गहनता होती है। समाजवाद के अतर्गत तकनीकी प्रगति समस्त जनगण के जीवन-स्तरों में सुधार की आधारगति के रूप में और अर्थ के आधार को बचाने के लिए काम आती है।

समय-अभिरूपता का सिद्धांत इस तथ्य का भी विशेष प्रतिबिम्ब है कि एक के रूप में पूँजीवाद स्वयं को प्रतिष्ठाहीन बना चुका है।

जो वे हड़तालों की बढ़ी संख्या और वर्ग-संघर्षों का गभीर होना

आधिपत्य को छुपाने के लिए गड़ी जाती है। इजारेदार पूँजीपति वर्ग सब जगह यह ध्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि मेहनतकश जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब वर्तमान व्यवस्था के क्रांतिकारी रूपांतरण के बिना मिल सकता है। अपने शोषक व आक्रामक सारतत्त्व को छुपाने के लिए पूँजीवाद अनेक प्रकार की पक्ष-समर्थक धारणाओं का सहारा लेता है।

‘पूँजीवाद के रूपांतरण’ की आधारभूमि के रूप में ‘पूँजी के जनवादीकरण’ की कल्पित कथा का उपयोग किया जाता है। पूँजीवादी अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि सार्वजनिक नियम तथा जनता के बीच शेयरों के व्यापक वितरण का अर्थ यह है कि पूँजी का जनवादीकरण हो गया है और सभी शेयरधारी पूँजी के सह-स्वामी हैं तथा लाभार्थ प्राप्त करने वाले हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री एडोल्फ बर्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मेहनतकश वास्तव में पूँजीवादी उद्यमों के मानिक हैं और निजी स्वामित्व का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये ‘सिद्धांत’ समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच धनराशि तथा मूल्य के आधार पर शेयरों के वितरण की पूरी तरह उद्देश्य करते हैं। इस बात के साक्ष्य हैं कि समस्त शेयरों का दो-तिहाई से अधिक भाग (मूल्य के अनुसार) ऊँची आमदनी वालों, नाम भिया जाये तो पूँजीपति, बड़े जमींदारों आदि के हाथों में संकेन्द्रित है। मजदूरों के पास बड़ी बचत नहीं होती है और जो कुछ सत्ताधन ने बचा पाते हैं, उसे मुसीबत के दिनों के लिए (शायद कल से उन दिनों के लिए जब वे बेरोजगार हो जाते हैं) सुरक्षित रखते हैं। बड़े पूँजीपति छोटे व मध्यम शेयरधारकों की कीमत पर अपनी पूँजी बढ़ाने के लिए स्टॉक-एक्सचेंज की सट्टेबाजी का बालाफी भरा उपयोग करते हैं।

लेनिन ने इस संबंध में लिखा है—“शेयरों के स्वामित्व का जनवादीकरण जिससे पूँजीवाद बुनकों और अवसरवादी तथाकथित ‘सामाजिक जनवादी’ पूँजी के जनवादीकरण तथा छोटे स्तर के उत्पादन के महत्व एवं भूमिका के मजबूत हो जाने आदि की आशा रखते हैं (या कहें कि वे आशा करने हैं) वास्तव में वित्तीय अल्प-जंघ की शक्ति में कूटि करने का एक तरीका है।” इस प्रकार पूँजी के जनवादीकरण और ‘स्वामियों के बीच वित्तसार’ की जगह वास्तविकता में पूँजीपतियों के एक छोटे समूह के हाथों में पूँजी का केन्द्रीकरण हो रहा है।

‘पूँजीवाद के रूपांतरण’ के पक्ष में दूसरा लक्ष्य तथाकथित ‘अवध-आदि’ का है। बड़ी इसका मतलब यह है कि आधुनिक परिस्थितियों में पूँजीपतियों ने तथाकथित रूप से अर्थव्यवस्था पर नैतिक नियंत्रण खो दिया है और अब नियंत्रण का कार्य श्रमिकों पर रहे सके (वैतनिकों की—अनु०) सैनिकों, जनसम के प्रतिनिधियों का

प्राधिकार हो गया है।

आधुनिक पूँजीवाद के अंतर्गत, जबकि संयुक्त उद्यम व्यापक रूप में हैं, पूँजी के भीतर (निवेश की गयी राशि के अनुकूल) स्वामित्व का विभाजन विशाल क्षेत्र में फैल गया है। कार्ल मार्क्स ने इस पर बहुत पहले ही ध्यान दिया था। पूँजीवादी विचारक जो यह कहते हैं कि संयुक्त-स्टाक उद्यम राष्ट्रीय हैं, स्वामित्व के रूप के प्रश्न के स्पष्ट पर प्रबंध के रूप के प्रश्न को रख देते हैं। वे इस तथ्य को भी भूल जाते हैं कि उद्यम की प्रकृति प्रबंध के रूप पर निर्भर होती है।

पूँजीवादी विचारक व पूँजीवादी समाज में प्रबंधक की भूमिका को भी समस्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट रूप में प्रबंधकों का कोई विशेष वर्ग नहीं है। जो प्रबंध व्यवस्था के नीचे वाले क्रम में है अर्थात् जो औद्योगिक-उत्पादन में प्रत्यक्ष शामिल होते हैं, वे वेतनभोगी हैं। वे नीति-संबंधी निर्णय नहीं करते हैं और लाभ के बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अहाँ तक शीर्षस्थ प्रबंधकों का सवाल है, वे उद्यम की प्रतिबद्धियों का निर्देशन तभी कर सकते हैं जब उनके पास 51 प्रतिशत शेयरों का नियंत्रण हो अर्थात् जब वे पूँजीपति हों।

इसलिए 'प्रबंध-क्रांति' के दावे वास्तविकता में मेल नहीं खाते हैं। वे वित्तीय बल्य-तंत्र की सर्वोच्चता और उनके बड़ते मुनाफों को छुपाने के लिए गढ़े जाते हैं।

1960 के दशक में, पूँजीवादी साहित्य में सम-अभिरूपता का सिद्धांत व्यापक प्रचलित हो गया था। यह सिद्धांत अनिवार्यतः जो दावा करता है, वह यह है कि जैसे-जैसे पूँजीवाद तथा समाजवाद का विकास होता है, वे दोनों बढ़ती मात्रा में समान विशेषताओं को अपनाने लगते हैं और दोनों के बीच का अंतर धीरे-धीरे मिटने लगता है। पूँजीवादी विचारक कहते हैं, यह इस तथ्य के कारण होता है कि दोनों व्यवस्थाओं में औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दशाएँ अधिक-से-अधिक समान होनी जा रही हैं। सम-अभिरूपता का सिद्धांत स्वामित्व के भिन्न रूपों—समाजवादी व निजी पूँजीवादी—से उत्पन्न आधारभूत अंतर की उपेक्षा करता है। न तो प्रौद्योगिक विकास और न ही संपन्न व प्रबंध की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस अंतर को समाप्त कर सकती हैं। पूँजीवाद के अंतर्गत प्रौद्योगिक विकास व अधिक कार्य-क्षमता का उपयोग अधिक तीव्र धूम, मजदूर वर्ग के बड़े हुए शोषण में होता है और इसका परिणाम पूँजीवाद के अंतर्विरोधों में अधिक गहनता होती है। समाजवाद के अंतर्गत तकनीकी प्रगति सशस्त्र जनमण के जीवन-स्तरी में सुधार की आधारशिला के रूप में और धूम के भार को कम करने के लिए काम आती है।

सम-अभिरूपता का सिद्धांत इस तथ्य का भी विशेष प्रतिबिम्ब है कि एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में पूँजीवाद स्वयं को प्रतिस्थापित बना चुका है।

पूँजीवादी देशों में हड़तालों की बड़ी संख्या और वर्ग-संघर्षों का गभीर होना

